

भारत में बंधुआ मज़दूर

महाश्वेता देवी
निर्मल घोष

हिन्दी अनुवाद
आनन्दस्वरूप वर्मा



राधाकृष्ण

1981

©

महाश्वेता दवी
निमल घाष

हिंदी अनुवाद

राधाकृष्ण प्रकाशन
नई दिल्ली

प्रथम हिंदी संस्करण 1981

मूल्य

30 रुपये

प्रकाशक

राधाकृष्ण प्रकाशन
2 जसारी राड दरियागज
नई दिल्ली 110002

मुद्रक

भारती प्रिंटर्स
दिल्ली 110032

बधुआ मजदूर का मामला आज भी एकदम जीवत और सशक्त है। आज भी बेतहाशा प्रचार और धूमधाम के साथ देश में जब किसी परियाजना का उदघाटन किया जा रहा होता है—किसी जंगल में दश की किसी मुलायम या कठार धरती के हिस्से पर कोई अभागा परिवार चुपचाप गुलामी की जजीर में कसता जा रहा होता है। यह राग काफी पुराना है और आज भी काफी मजबूत राग है।

किसी भी कानून जथवा अध्यादेश ने बधुआ मजदूरों की मदद नहीं की। राष्ट्रीय धर्म सस्थान ने यह साबित कर दिया है कि दश में लगभग 23 लाख बधुआ मजदूर हैं। जब तक बधुआ मजदूरों में चेतना नहीं पैदा होती और वे एकजुट होकर खड़े नहीं हो जाते, कोई भी उन्हें आजाद जिंदगी बिताने का हक नहीं देगा।

ક્રમ

પ્રસ્તાવના	9
પૂર્વિકા	11
અધ્યાય ૧૪	41
અધ્યાય ૨1	63
અધ્યાય ૩૦	77
અધ્યાય ૪૦	128
અધ્યાય ૫૧	139
પરિશિષ્ટ	144

प्रस्तावना

10 भारत म बधुआ मजदूर

हमन इस पुस्तक का टिप्पणिया और सदर्थों स बोचल नही बनाया है । हम उनव प्रति आभार व्यक्त करते है जिनकी पुस्तका और लेखा स हमन मदद ली ।

महाश्वेता देवी
निमल घोष

भूमिका

अंग्रेजों द्वारा लागू की गयी भूमि व दबोवस्त प्रथा न भारत में बधुआ मजदूर प्रणाली के लिए आधार प्रदान किया ।

इससे पहले तक जमीन को जतन वाला जमीन का मालिक भी था । जमीन की मितिकयत पर राजाआ और उनके जागीरदारा का कोई दावा नहीं था । उह वही मिलता था जो उनका बाजिव हक बनता था और यह कुल उपज का एक प्रतिशत हाता था । हिन्दू राजाआ के शासन-काल में यह हिस्सा कुल पैदावार के बारहवें हिस्से से छठे हिस्से तक घटता-बढता रहा । मुगल शासन काल में यह हिस्सा बढकर एक तिहाई तक हा गया ।

शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के लउखडाते दिना में शाही शुल्क वसूलन के लिए जिम्मेदार अधिकारी अर्थात् नहसीलदार लोग और भी क्यादा जानामक हा गये । ये लोग एक ऐसी अढ मामती व्यवस्था चाहते थे जिसमें इनके पाम एक जागीरदार अथवा गवनर की शक्ति और अधिकार हा और जो शहशाह के प्रति बहुत मामूली ढग से उत्तरदायी हो । उन तथाकथित राजाआ या गवनरा ने अपने नये अधिकारा को पूरी तरह जमल में नाते हुए करा की दर बढा दी और इसे फसल का आधा भाग कर दिया । यह कमरताड भार और भी क्यादा हा गया जब इतिहास के महत्वपूर्ण सत्रमण-काल में भारत के रगमच पर अंग्रेजा ने प्रवेश किया ।

करा की वसूली के लिए जो तरीके अपनाये गये वे बेहद अमानवीय थे ।

फिर भी सदिया पुराना ग्रामीण समाज तथा आदमी और जमीन के बीच का परम्परागत रिश्ता कायम रहा । अभी भी करा का भुगतान नकद के रूप में बहुत कम हाता था—यह फसल के रूप में ही होता था । करा के रूप में फसल की कितनी मात्रा ली जाये, इसे एक्जित फसल के आधार पर तय किया जाता था ।

अंग्रेजा न इस स्थापित परम्परा का अपनी खुद की प्रणाली से कैसे बदला ? कैसे उन्होंने जमीन को जामानी में बेचन लायक मान का रजा दे दिया औ-

स्वतंत्र मजदूरों में रॉतिहर मजदूरों और बंधुआ मजदूरों को जन्म दिया। इस प्रक्रिया को समझने के लिए भारत में ब्रिटिश शासन के पूर्व के समाज और भूमि प्रणाली का अध्ययन किया जाना चाहिए।

ग्रंजों के आगमन से पूर्व भारत के गांव एक-दूसरे से काफी दूरी पर फैले हुए थे। प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर था। जमीन और हस्तकला से उत्पादित चीजों का, गांव की जनता ही पूर्ण तरह इस्तेमाल करती थी। गांव का अपना समाज पर शासन था। याय दिलाते जमीन सम्बन्धी विवादों तथा सामाजिक संघर्षों को हल करने की व्यवस्था गांव करता था। यह विभिन्न व्यवसायों में लोगों को लगाता था तथा उत्पादन के समान वितरण की व्यवस्था भी करता था। वस्तुतः किसी तरह के बाहरी हस्तक्षेप या मध्यस्थता की कोई जरूरत ही नहीं थी।

उनका रहन-सहन का स्तर साधारण था। वे बेचल-खेती करना जानते थे। खेती से सम्बन्धित चटाव उतार के साथ ही वे डूबते उभरते थे। यदि फसल नहीं हुई तो उनका रहन-सहन का स्तर पारंगत गिर जाता था। अकाल, बाढ़, सूखा तथा अन्य विपदाओं में दुख उठाना तो हर आदमी का बंधन था। लोहार, बढई, कुम्हार आदि कारीगरों की स्थिति, एक हद तक कुछ बेहतर थी क्योंकि संकट के समय वे गांव छोड़कर राजों व महलों की बाहर जा सकते थे।

इसलिए यह कहना सही होगा कि निम्नांकित बातें भारत के ग्रामीण समाज का आधार थीं—जमीन तथा लोगों को उसे जानने का अधिकार और कृषि तथा हस्तशिल्प का संयोग। उन दिनों के हमारे गांवों में धर्म का यह वितरण एक अकाट्य नियम था।

वसंत पाले ही बताया है कि किसान ही जमीन के स्वामी थे। जनक सहिताश्रम में लिखा गया है कि जमीन का असली स्वामी राजा था। फिर भी एक बार जानने के लिए जमीन तयार कर लेने के बाद यह मिलिक्रयत किसान के हाथ में चली गयी। राजा के आधिपत्य और किसान के स्वामित्व के बीच कोई विवाद नहीं था। युद्ध-क्षेत्र में हुए फसलों के अनुसार राजा और राजत्व में परिवर्तन होता रहा, लेकिन किसानों की मिलिक्रयत कभी भी प्रभावित नहीं हुई। सिर्फ वर-विभी दूसरे की तिजारी में जान लया। राजा और किसान के बीच कोई विचौलिया भी नहीं थी। भूमि प्रशासन ठीक से चलाने के लिए राजा गांवों में मुखिया नियुक्त करता था। इन मुखियाओं के इस्तेमाल के लिए अनाज तथा इधन की व्यवस्था रखत करती थी।

कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में कहा गया है कि भूमि पर समस्त अधिकार राजा में निहित है। जिस जमीन का वह जोतने के लिए तैयार करता है उसे कृष्य भूमि कहते हैं। इस ग्रंथ में उस जमीन की उपज से रयत को आज्ञा तथा उठान का अधिकार है जिस पर वह खेती करता है। इसमें यह भी माना गया है कि खेती

के अयोग्य सभी भूमि पर रैयत का पुष्टनी हक है। अगर खेती न की जा रही है, उसी हालत म राजा खेती के योग्य और अयोग्य सभी भूमि का वापस ले सकता है और रैयत का वेदखल कर सकता है। यह एक सुविचारित धारणा है कि बंगाल मे एक पुष्ट से दूसरी पुष्ट तक व्यक्तिगत आधार पर जमीन की मिल्कियत की प्रथा का प्रचलन था। अथ प्राता म भूमि सम्बन्धी अधिकार समग्र रूप मे परिवार की इकाई मे निहित थे। वशानुक्रम सम्बन्धी अपन विख्यात सिद्धांत म विज्ञानेश्वर ने इसका उल्लेख किया था। जा भी हो, ये दाना प्रथाएँ प्राचीन थी।

उल्लेखनीय बात यह थी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि के उत्पादन का ही लाभ उठा सकता था। जहां तक जमीन का मामला है इसे अथ वस्तुआ की तरह बेचा या खरीदा नहीं जा सकता था। बुनियादी तौर से किसी कृषि प्रधान समाज म आत्मनिर्भर किसान भू-स्वामी और उत्पादक दोनों था। मन्चे अतः सम्बन्ध का यही सार था और इस आधारशिला पर ही प्राचीन भारत की सामंती व्यवस्था का उदय हुआ था।

अपनी निम्न अथव्यवस्था और जमीन की सामूहिक मिल्कियत वाले ग्रामीण परिवेश म भू-स्वामी-बेटाईदार सम्बन्ध अथवा भू-स्वामी क्षतिहर मजदूर सम्बन्ध जसा अतर्क्य गतिविज्ञान विकसित नहीं हो सका। जमीन का कोई अभाव नहीं था और किसी तरह का व्यक्तिगत स्वामित्व भी नहीं था। इस हैमियत से जमीन जोतने वाला की सट्टा मे वृद्धि भी ऐसा मामला नहीं था जिसमे कोई परशानी पदा हो। किसी को स्वावलम्बी किसान मानन पर भी बाइ प्रतिवध नहीं था। बाइ क्या साधारण मजदूर बनना चाहगा जब वह जासानी स मालिक उत्पात्क हो सकता हो? उन दिनों हल चलान के लिए बलों की भी कमी नहीं थी।

मुस्लिम सम्राटों का शासन-काल के दौरान बाई परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने जमीन के पद बनाये जिन्हें अच्छी तरह सीमांकित क्षेत्रों का स्थानीय नियंत्रण मापा गया। फिर भी उनका ग्रामीणों और किसानों से सीधा सम्बन्ध नहीं था। सम्राट के लिए करा की वसूली तक ही उनकी भूमिका सीमित थी। इस काम मे उन्हें गांव के मुखिया की मदद मिलती थी। इस प्रकार वशानुगत जमींदारी प्रणाली मरूपांतरित हाते राजवंश को बरों का भुगतान करने की प्रथा की संभावना नहीं थी। मुगल शासन काल म भी ऐसा कोई अभिजात वर्ग नहीं था जा भूमि के स्वामित्व पर आधारित हो।

मुगल शासन काल मे भू राजस्व के भुगतान को संचालित करने वाले सिद्धांत के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख करना बेहद जरूरी है। प्रथम हिंदू राजाओं का अपने क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। दूसर, मुगल सरकार अपने लिए कर वसूलने वालों का हमेशा नवद के रूप मे वेतन नहीं देती थी। इसकी

बजाय कर वसूली वाला था उनका लिए निर्धारित क्षत्राग कर की बगुली की पूरी ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती थी। नतीजा यह होता था कि सरकारी स्तर पर छानबीन करने में बावजूद इन अधिकारियों को कर वसूलन में एक तरह से चुनी छूट प्राप्त थी। तीसरे कुछ मामला में ये अधिकारी गांव में मुखिया पर भरोसा नहीं करत थे और सरकारी खजाना में जमा कराने के लिए बिगाना से मीघ कर वसूलत थे।

इन तीन कारणों से कर-वसूली में बड़े पैमाने पर रिवाजों से अलग जान की स्थिति मिलती है। फिर भी जमीन की मिलितत राज्य अथवा जमींदारों के हाथ में नहीं जाती थी। मत का जोतन और अनाज पैदा करने वाले अभी भी पहले की ही तरह इन सत्ता के मालिक थे। उन दिनों में जिन्हें जमींदारों के नाम से जाना जाता था वे दरअसल कर वसूल करने वाले एजेंट थे। दमन और यंत्रणा का अस्तित्व था। कवि मुकुंदराम चन्नर्ती लिखित 'चण्डीमंगल' में चिह्नित दारा पोतदारा आदि जम मुगल अधिकारियों द्वारा जवणनीय यातना दिये जाने के अनवर प्रसंग मिलते हैं। यहाँ तक कि धूम दन में भी काम नहीं जाता था। सिपाहियों द्वारा एक के बाद एक मराना पर छापा मारा जाता था और वज्र जमीन का खेतिहर जमीन के रूप में दज किया जाता था। वे जाबूज कर सेता की तिरछी पैमाइश करते थे ताकि जमीन का क्षेत्रफल अधिक दिखा कर जमीन का जाली खाता तयार कर सकें। इस स्थिति पर कवि मुकुंद न लगभग बिलखते हुए लिखा— किसानों की दुहाई पर कोई नहीं करता सुनवाई। केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के काफी दूर होने के कारण स्थानीय अधिकारियों के लिए निदयी और दमनकारी होना आसान था। स्पष्ट था कि कर वसूलन की यह प्रणाली दुख और यातना को न मंद रही थी। और गौर करने की बात है कि कवि मुकुंदराम जिस काल का बयान कर रहे हैं वह मुगल सत्ता का शिखर काल था।

मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ इस प्रणाली का संचयन ध्वस्त होना लगा। केन्द्र में एक कमजोर सरकार के होने का लाभ उठा कर कर-बगुली के सभी तीनों वर्गों ने अपने-अपने इलाकों में नकद और अनाज दोनों रूपों में भुगतान किया जानेवाले कर की राशि में मनमाने ढंग से बढ़ि कर दी। इसके फलस्वरूप किसानों को भयकर यंत्रणा का शिकार होना पड़ा। फ्राँस्वा बर्निएर के यात्रा-वृत्तान्त के पन्नों को पलटने से कोई भी देख सकता है कि कारीगरों और छोटे व्यापारियों का भी नहीं बर्शा गया। ऊपर से एक नयी मुसीबत यह खड़ी हो गयी कि इतने दिनों से—अफगान राजाओं के शासन काल से ही विवक्षित तिबाई व्यवस्था अब बख़्ताने लगी। उसने धती की बुनियाद पर ही मरणातक प्रहार किया। एक तरफ़ तो तुर्कों के सूबेदारों, जागीरदारों, जमींदारों तथा अन्य जफ़मरों की फीज थी

और दूसरी तरफ पानी का अभाव था। किसानों को कुछ भी नहीं सूख रहा था। कुछ स्थानों पर तो किसानों ने विद्रोह कर दिया।

काफी समय तक गांव की सामाजिक व्यवस्था ने विदेशी हमला से अपनी हिफाजत की। बदकिस्मती से इसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह अपेक्षाकृत उच्च स्तर की सामाजिक शक्ति का मुकाबला कर सके। यह प्राचीन, स्थिर और जड़ व्यवस्था उस प्रगति की राह में एक जबरदस्त बाधा बन गयी जिसकी शुरुआत नवोदित बुजुआ वर्ग के हाथ हुई थी, जो शीघ्र ही प्रभुत्व स्थापित करने लगा था। उन दिनों व्यापार पर आधारित बुजुआ वर्ग अभी भ्रूणावस्था में था और काफी कमजोर तथा असंगठित था। देश की प्रगति का खाका तैयार करने में यह प्रभावकारी भूमिका नहीं निभा सका। यही वह कारण है जिससे भारत में सामंती व्यवस्था अपना पूर्ण विकसित रूप नहीं पा सकी।

इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार पर विजय पाने के फौरन बाद ग्रामीण समाज की जड़ पर प्रहार किया। अंग्रेजों की बुद्धि ने तुरंत वास्तविकता को भांप लिया। इंग्लैंड का माल बेचने तथा किसानों के उद्योग धंधा को कच्चे माल की शाश्वत कमी को पूरा करने के लिए सबसे पहले इन किसानों को गुलाम बनाने की जरूरत थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जरूरी था कि किसानों को उनके चिरपरिवारित माहौल अर्थात् गांव से बाहर खींचा जाये। अंग्रेजों के सत्ता में आने से पूर्व अंग्रेज सादागरा का जकेले गांव में अपने माल की फेंरी लगाने में असफलता का ही सामना करना पड़ा था। इन आत्मनिभर गांवों में विदेशी सामान के खरीदार एकदम नहीं थे। शहरों और शहरों के आसपास के इलाकों में ही खरीददार तैयार किए जा सकते थे। ब्रिटिश शासन की जैसे भारत की मिट्टी में तब तक गहराई तक नहीं पठ सकी जब तक उन्होंने ग्रामीण समाज का साह नहीं किया।

और उन्होंने यही किया।

सत्ता में आते ही अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने दो तरीके अपनाये। पहला तरीका एक नयी कर प्रणाली की शुरुआत थी। दूसरा तरीका था कर भुगतान के रूप में फसल की जगह नकद राशि लेना। इन दो तरीकों से उन्होंने जमीन की व्यक्तिगत मिल्कियत का मांग प्रशस्त किया—एक ऐसी प्रणाली को जन्म दिया जो उनका अपने देश में प्रचलन में थी। इस प्रकार उन्होंने प्राचीन व्यवस्था का ध्वंस पूरी तरह कर दिया और नयी व्यवस्था की शुरुआत की।

अंग्रेज शासन ने एलान किया कि जमींदार गुमास्ता और गांव के मुखिया के रूप में पुकारा जाने वाला वर्ग ही जमीन का असली मालिक है। भुगतान ग्रामों की शब्दावली में 'जमींदार' का अर्थ एजेंट था। जब यह अर्थ हमारा बन लिए

16 भारत में बहुआय मजदूर

दफना दिया गया। जमीनाराने न अब बिगाना स अपनी ताकत भर बगुनना शुरू किया। साथ ही उन्होंने तीन अय हथियारा का इस्तेमाल किया—जमीन की बिक्री जमीन का वितरण और गिरवी के रूप में जमीन रखना। इन तरीकाने दमन करने वाले नये वर्गों का जन्म हुआ—गाँदीनार पट्टीनार, तरपट्टीनार और ताल्लुकदार।

उन्होंने अग्रजों द्वारा शुरू की गयी प्रणाली का किसानाना य गृह हलक के नीचे ठल दिया। फलस्वरूप किसानाना का जमीन पर स अपना पुस्ती ह्व सग के लिए छोड़ना पड़ा।

भारतीय रगमच पर अग्रजों के प्रकट हान तक महान मुगल साम्राज्य का प्रकाश धुधला पड़न लगा था। किसान पहले ही उन सारी चीजों से वंचित हान लग थे जो उनके पास अपनी सम्पत्ति के रूप में थी। अग्रजों ने इन सामान्य अवस्था मान लिया और उन्होंने भी उसी दूर अत्याचार और लूटपाट का रास्ता अख्तियार किया।

मुगल शासन-वाले के अंतिम दिन मता कर बसूलन के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाना आम बात थी। धूत अग्रजों का मस्तिष्क इस मामले में मुगलों से भी ज्यादा उबर था।

दय कर के भुगतान न किए जाने पर किसानों की जमीनें बच देने की एक प्रणाली लागू की गयी थी। जब अग्रेजों का कुछ पदा करते थे उसकी और गरीब किसान अपना खून पसीना बहाकर जा कुछ पदा करते थे उसकी आधी से भी कम मात्रा उनके पास बच रहती थी। यह गणित बहुत सरल था।

1764-65 के अंत में जब मुगल साम्राज्य अंतिम साँस ले रहा था और बंगाल में नवाबी प्रणाली एक दिशा ले चुकी थी बंगाल में भूमि कर 8 14 000 पौंड था। 1765 में बंगाल विहार और उड़ीसा के दीवान के रूप में इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार जमाने के बाद 1765-66 के गणना त्रय में कुल 14 70 000 पौंड राजस्व की वसूली हुई थी। 1793 में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह राशि 30 91 000 पौंड हो गयी थी।

इसने अलावा अलग अलग लागों को मिल व्यक्तिगत पुरस्कार और जमीन लूट का विस्सा ही और था। किसानों को बहन दरिद्रता की स्थिति तक पहुँचाने के बाद भी अग्रज नरम नहीं पड़े। उन्होंने चावल की जखीरेवाजी शुरू की। इस काम को कंपनी के एजेंट करते थे। उन्हें पता था कि अनाज की कमी हाते ही मुनाफा बढ़ना लाजिमी है।

अंत में बुरे दिन आ गये। किसानों को जिन्हे फसल पका करना आता था

बेवकूफ नहीं बनाया जा सका। उह अपनी उस सीमित भूमिका का एहसास हा गया जा फसल कटने के साथ ही समाप्त हो जाती थी। खेती से हुई फसल पर जिसे वे कमरतोड महनत के बाद पैदा करते थे, अब उनका किसी तरह का दावा नहीं था।

वे खेती के प्रति उदासीन हो गए। इससे खाद्य स्थिति और भी खराब हो गयी। जनाज की जखीरवाजी करके और कीमता में बेतहाशा वृद्धि करके ब्रिटिश सौदागरा न बेशुमार मुनाफा कमाया, लेकिन इसका जा अवश्यभावी नतीजा था वह भी सामन आ गया।

बंगाली कैलेंडर के अनुसार 1176 का बष बहुत अशुभ साबित हुआ। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर का बष 1770 जो बंगाली कैलेंडर के उस बष से मेल खाता था, देश में घुम आये इन नये जुटेरा के लिए भरपूर समद्वि का बष था।

1176 का यह साल औरा का तथा इतिहास को बखबी याद है। यह जबरदस्त जकाल का बष था—ऐसा जकाल जिसे मनुष्य ने तैयार किया था।

बंगाल, बिहार और उडीसा को मिला कर बनाये गये सूबे की एक तिहाई आबादी के मुह से खान के लिए जा चीख निकली वह कमश धीमी होती हुई सदा-सदा के लिए खामोश हो गयी।

खेतीवाडी का काम ठप पडा था, पर अंग्रेज सौदागर शामक अभी भी कर वसूलन निबलत थे। जत्याचार, मत्रणा, बलात्कार और लूटपाट ही इनके हयियार थे। इसमें उह सफलता मिली। 1768 ई० में, अकाल से दो बष पूव बंगाल में कुल 1,52,40,856 रुपए कर के रूप में वसूले गए। 1771 ई० में, अकाल के एक बष बाद यह राशि 1,57,26,576 रुपए हो गयी।

साल दर-माल कम्पनी के खजान में ज्यादा से ज्यादा कर जमा हान लगा। कुछ अधिकारिया द्वारा व्यक्तिगत तौर पर अपनी जेजे भरन के लिए गर कानूनी ढग से करा की वसूली की गयी और बस पत्रिया में तरह-तरह के जत्या चार भी किय गये जिसके फलस्वरूप एक असगठन की स्थिति पैदा हो गयी। नतीजा यह हुआ कि कम्पनी अपनी करारोपण प्रणाली का मुचार रूप से न चला सकी।

1772 ई० में इमने 'पँचसाला वदोबस्त' नामक प्रणाली शुरू की। जकाल के प्रभावा ने इस प्रयास का विफल कर दिया। इससे पूव एकसाला वदोबस्त को पहले ही रफनाया जा चुका था। बाद में, 'दससाला वदोबस्त' भी करारापण की नियमित प्रणाली को समथन नहीं दे सका।

एकदम हताश हाकर साड कानवालिंस न अन्तिम समाधान का सहारा लिया।

और यह था स्थायी वदोबस्त।

इस कदम के जरिए कर वसूलन वाला को भू-स्वामी बनाने का घातक काम किया गया। तब पढ़ने वाले ही जमीन के स्वामी थे और उनमें कर की वसूली का काम कम्पनी के एजेंट करते थे। अब स्थिति उलटी हो गयी थी। नये भू-स्वामियों का उन किसानों के कर वसूलन का अधिकार दिया गया जो अब तब तक नहीं थे और जो अब इन भू-स्वामियों की प्रजा बना दिए गए थे।

स्थायी बंजरस्थल में पहले भूमि का उचित तरीके से सर्वेक्षण नहीं किया गया था। तबसे लाभ जमींदारों ने उठाया और सती के लिए अयोग्य भूमि, चरागाहों व जंगल भूमि पर मुक्त भूमि तथा हर भरे जंगली इलाके पर बंजर कर लगाया। इस प्रकार मजदूरों की स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। नये शासकों ने अपने खुद के देश में अपनाय जा रहे भू-स्वामित्व के मतांग्रह रूप को शुरू करने की कोशिश की थी। 1793 ई० में पहले बंगाल के मूल में और बाद में उत्तरी मद्रास में उन्होंने अपनी याजना का वायावित किया। इसमें सबसे बड़ा कर वसूली का दृढ़ करना तथा अपना खुद का शासन बायम करना। स्थायी बंजरस्थल के तहत घोषित किया गया कि जमींदार लोग वसूले गए कर का 10/11वाँ हिस्सा सरकार का देण और 1/11 वाँ हिस्सा खुद रख लेंगे। असली लाभ सरकार को न कि जमींदार और किसान का मिलता था। बंजर बड़ी साफ थी।

उस समय जमींदारों को 30 लाख पौंड सरकार को देना था—यह राशि पहले की तुलना में किसी भी राशि में बहुत ज्यादा थी। पुराने जमींदार परिवार जिनके किसानों से वह घनिष्ठ सम्बन्ध थे इस राशि का नहीं वसूल कर सके। उन लिए किसी पर जल्दाचार करने और सतान की बात अपने आप में एक अभिप्राय थी। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि उनके स्थान पर कुछ ऐसे व्यापारिकों का रखा जाय जो खून चूमने और अत्याचार करने में माहिर हों। सरकार का सलुष्ट करने और वसूल की अपनी लिप्ता को पूरा करने के लिए उन्होंने आतंक का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो इतिहास में बमिसाल है।

यह कुलीन जमींदारों का एक नया बग था जिस स्थायी वंशवत्त्व न जान बूझ कर तैयार किया था। फिर भी स्थायी वंशवत्त्व सरकार का प्रारम्भिक लक्ष्य नहीं पूरा कर सका। बाद में रूप का मूल्य गिर गया। सरकार को वही कर मिले जा आमतौर से मिलते थे। लेकिन जमींदारों ने और अधिक कर वसूलन शुरू किया। फलस्वरूप सरकार का एकचौथाई भाग मिला जबकि जमींदारों ने अपने लिए तीन चौथाई हिस्सा रख लिया।

तब के बटवारे की बात चाहिए हमें पर साम्राज्यवादी खम में स्थायी वंशवत्त्व के बिना आवाज उठने लगी। इस जालाचनाओं को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इन्होंने इडिया कम्पनी ने भारत की भूमि समस्या के बारे में अनजान होने के

कारण असावधानीवश किसानों पर कर का बोझ डाल दिया। असलियत यह है कि इन आलोचनाओं का निशाना था राजस्व में आयी गिरावट — यह ऐसा तथ्य था जिसे बड़ी कुशलता के साथ छिपा रखा गया था।

फिर भी दूसरा मकसद पूरा नहीं हुआ। नये जमींदारों ने अंग्रेजी शासन का मजबूत बनाने और टिकाव रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अंग्रेजों ने जिन वग को जम दिया था, उसने शासकों के हित के साथ अपने हित को बड़े करीब से पहचाना। आगे चलकर लांड वेंटिक ने स्वीकार किया कि स्थायी बदोबस्त ने जन विद्रोह या नाति के खिलाफ हुआ पक्ति के रूप में जमींदारों का एक काफी बड़ा वग पदा किया। जमींदारों को जिनका जनता पर काफी प्रभाव था, अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाने में सफलता मिली, क्योंकि यह शासन उनके स्वार्थों को पूरा करता था।

वेंटिक की यह धारणा आगे चल कर सही साबित हुई। जमींदारों के विभिन्न संगठनों, मसलन जमींदार महामण्डल, जमींदार एसोसिएशन आदि ने औपचारिक बठका के जरिए अंग्रेजी हुकूमत के प्रति अपनी वफादारी का एलान किया। वग जमींदार समिति ने 1925 ई० में वायसरॉय को विशिष्ट सेवा का प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें समिति के सदस्यों ने वायसरॉय से कहा था कि वह उनके समर्थन और सहयोग पर भरोसा कर सकते हैं। 1938 ई० में निखिल भारत जमींदार सम्मेलन के अध्यक्ष मैमनसिंह के महाराजा ने इसी तरह की टिप्पणी में कहा था कि जमींदार वग के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें सरकार के हाथ मजबूत करने होंगे।

चाटुकारों के एक वग का स्थापित करने में कम्पनी को कामयाबी मिल गयी। फिर भी उनके आर्थिक मामलों में अभी भी बहुत गड़बड़ घाटाला था। तथ्य ने उन लोगों का अर्थ देशों में स्थायी बदोबस्त को लागू न करने के लिए प्रेरित किया। जमींदारी प्रणाली के साथ किये गये प्रयाग से उन्हें यह सन्नक हासिल हुआ कि करा की प्रत्यक्ष वसूली करनी होगी। बिना किसी विचौलिये की मदद लिये किसानों का शापण करना बेहतर है।

उन्होंने दक्षिण भारत में रयतवाड़ी प्रणाली स्थापित की जिसमें सरकार सीधे किसानों से निबटती थी। लेकिन तो भी यह स्थायी कदम नहीं था। इनमें सशान्ति की गुंजाइश थी। परिणामस्वरूप सरकार समय-समय पर नये मिरस भूमि का सर्वेक्षण और करा में वृद्धि कर सकती। जमींदारों अथवा जय विचौलिया की मदद के बिना सरकार करों की समूची राशि खुद अपने लिए वसूल सकती। इस दिशा में सरकार का प्रयास और जातान हो गया, क्योंकि गांव की सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व पहले ही समाप्त हो चुका था। दक्षिण भारत के लिए भी यह बात सही थी। 1818 ई० में मद्रास राजस्व वाट द्वारा जारी एक

स्मरण पत्र में प्रस्तुत जालोचना में कहा गया था कि ग्रामीणों का एक वापसी लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से विदेशी सरकार ने पुरातन ग्रामीण परम्पराओं का नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये वही परम्पराएँ थी जिनका गाँवों में जनतंत्र का बनाव रखा था।

सैंकड़ों वर्षों में जो जमीन गाँवों की सामूहिक सम्पत्ति थी उसका नये कृषि कानूनों में विघटन कर दिया। इस आशय के आशयमन्त्रित किया गया कि जमीन के बारे में सरकार के दावे सीमित रहेंगे। वास्तविक अर्थों में ऐसा नहीं था।

रयता की जमीन का निरन्तर पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा था और नये कर घोषित जा रहे थे। किसानों का जबरन जमीन में नये कर दिया जाता था—ठीक वैसे ही जैसे मुसलमान राजाओं के शासन-काल में होता था और यह प्रक्रिया खासतौर से उन जमीनों पर लागू की जा रही थी जिन पर करों का नये तरीके पर बढ़ा रखा गया था। इस मुसीबत से निपटने के लिए भागन की बार्डें जगह नद्वी थी। जो किसान खेतों में भागते थे उन्हें जबरदस्ती पसीटकर बांध पर लया दिया जाता था। फसल कटने तक दावा के बारे में हर तरह का बहस का स्थगित रखा जाता था। किसानों के हिस्से में उस बीज और बल ही पड़ते थे। जिस किसानों के पास यह भी नहीं था उन्हें सरकार द्वारा यह दिया जाता था। ऐसा करना सरकार के हित में था।

रयतवादी प्रणाली के तहत किसानों की जमीन के मालिक के रूप में स्वोकार किया जाता था। जमीनारी बग की रचना का कोई प्रयास नहीं किया गया। ता भी यथायथ में होता यह था कि कोरपाविला प्रणाली के जिन सूर्यग्राहों की जमीन की मिल्कियत मिलने लगी और रयतवादी प्रणाली के अंतर्गत पत्त बांध क्षत्रा में जमीनदारों की तात्पर्य तन्त्री से घटने लगी। जाकड़ा में पता चलता है कि 1901 ई० से 1912 ई० के बीच मद्रास में एम भू-स्वामियों की संख्या, जो किसान नहीं थे प्रति हजार भू-स्वामी पर 19 से बढ़कर 49 हो गयी। किसान भू-स्वामियों की संख्या 484 से घटकर 381 रह गयी। किसान रयता की संख्या प्रति हजार पर 151 से बढ़कर 225 हो गयी।

उक्त अवधि की जनगणना रिपोर्ट में अन्य मुद्दों के बारे में भी ऐसा ही तर्कवही उभरती है। पंजाब में भूमि-करों पर निर्भर रहनेवाला की संख्या 1911 ई० में 6 26 000 थी जो 1921 में बढ़कर 10 08 000 हो गयी। समुक्त प्रांत में 1819 में 1921 ई० के बीच इस तरह की जायान्तों में 46 प्रतिशत का वृद्धि हो गयी। इस अवधि में हर पर निर्भर लोगों की संख्या में 52 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

उत्तर और उत्तर-पश्चिम में अंग्रेजों ने महलवादी प्रणाली शुरू की। यह स्थायी बंदोस्त और रयतवादी प्रणाली के बीच का रास्ता था। महलवादी

प्रणाली ने ग्राम-सभाज अथवा कबीले का भूमि के सामूहिक स्वामी की भावना दी। लेकिन यह महज एक स्वाग था, क्योंकि कबीले के सदस्यों को सौंपी जाने वाली जमीन का अलग-अलग सर्वेक्षण और पैमाइश की जाती थी। मिसाल के तौर पर पंजाब की बात लें। गांव का मुखिया ही कर वसूलने और भुगतान करने के लिए जिम्मेदार था। फिर भी कर की वसूली प्रत्येक किसान ने अलग अलग की जाती थी।

स्थायी वदावस्त रैयतवादी और महलदारी ही वे तीन हथियार थे जिनसे अंग्रेज शासक ने भारत की एक एक जमीन को हड़पना शुरू किया। उन्होंने जमीन से किसानों को हटा कर जमींदारों को बसाया। सूदखोर महाजन किसानों की पीठ पर सवार हो गए जिनके पास कुछ भी नहीं था। कोरफाविली प्रणाली ने उन्हें ऐसे लोगों की प्रजा बना दिया जो खुद भी प्रजा थे। अब जमीन उर्वारी नहीं थी। कोरफाविली प्रणाली के लगातार बढ़ते उपाया ने जमींदारों तथा पंचायत व्यवस्था को जन्म दे दिया था। इन विचौलियों का जमींदारों और किसानों के बीच जिन्हें कोरफा रैयत के स्तर तक नीचे ला लिया गया था घुसा दिया गया।

और फिर भी किसानों की जिंदगी चलती रही। बस अब वे अपनी पीठ पर एक पिरामिडी ढांचा ढा रहे थे जिन्होंने उनका खून चूस लिया था। जमीन की अब उन्हें मान जानकारी थी जिसके साथ उनका जातिगत सम्बंध बना हुआ था, पर अब जमीन पर उनका कोई हक नहीं था। एक बार फिर बंकिम मुकंदराम के गीतों के शब्द सच लगने लगे — किसानों की पुकार कौन सुनता है? उन्होंने सब कुछ खा दिया — यहाँ तब कि हल, बल और प्रीति भी। जमीन खा कर अब वे भूमिहीन खेतिहर मजदूर बन गये थे। और ऐसे नागा की सट्टा बढ़ती गयी। 1882 ई० की जनगणना में इनकी सट्टा 70 20,000 थी। 1921 ई० की जनगणना में यह सट्टा बढ़कर 2 10,00 000 हो गयी। 1931 ई० में इनकी सट्टा 3 30 00,000 तक पहुँच गयी। इन आँकड़ों की व्याख्या में यह लगाया गया कि उन दिनों किसानों का एक तिहाई हिस्सा खेतिहर मजदूर था। 1941 ई० में वह कुल जावादी का 50 प्रतिशत था।

यह हुआ कैसे? जिस जमीन से किसी जमाने अथवा जमानों की पूर्ति न हो वह अलाभकर है। छोटे किसान और बड़ाईदार जो ऐसी जमीन जोतते थे दिन-दिन और भी गरीब तथा दरिद्र मजदूर होते गये। दाना बर्गों के बीच ज्यादा फल हो — ऐसी बात नहीं थी। 1930 की मद्रास बंकिम रिपोर्ट में बताया गया था कि कोरफाविली किसानों और खेतिहर मजदूरों के बीच का फल दीखता नहीं था। कोरफाविली को इस समयदारी के आधार पर कमजोर कर दिया गया था कि कर का भुगतान नकद रूप में होना। जमीन का वितरण जमानदारी के आधार

पर किया गया था। फिर भी भू-स्वामियों ने रयत का 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत और 80 प्रतिशत तक फसल से भी वचित हान का मजदूर किया। इस प्रकार जल्दी ही रयत का दिवाला पिट गया और जमींदारों में साधना का कज बना पड़ा। इस राशि की अदायगी का मतलब बर्खास्त क समय फसल का अपना हिस्सा जमींदारों के अनाज गोदाम में जमा करना होता था। और इस प्रकार उनका किस्मत पुराना होती गयी।

उन जिनका एक किसान का अपने परिवार का दैनिक खर्च चत्तान के लिए 5 पकड़ था 15 बीघा जमीन तथा अपने छुट्टे के हल-बल की जरूरत पड़ती थी। पलायन कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया था कि सती मल्ल परिवारों में से तीन बीघाई के पास 15 बीघा से कम जमीन थी। लगभग 57.2 प्रतिशत परिवारों के पास 9 बीघा से भी कम जमीन थी। देखने के बाद में माका मुआयना करने में पता चला कि जिस वष फसल अच्छी होती थी उस वर्ष भी 8 प्रतिशत किसानों के पास पर्याप्त खाद्य नहीं होता था। वसूदयार महाजन ने अपने जीवन यापन के लिए मूल पर पैसे खर्च किए। जिन पर जिन कज का बोझ बढ़ता गया। फिर अचानक एक दिन उन्होंने पाया कि वे अपनी जमीन खो चुके हैं और भूमिहीन मजदूरों की श्रेणी में आ गए हैं।

एक पुरानी कहावत है कि दान कर धन ना घट। यह मूल विचार की नकल लगता था। मूलधार महाजन जितना ही पैसा कज के रूप में देते थे उतनी ही उनकी समृद्धि बढ़ती थी। किसान लोग विद्रोहियों के उस चूहे के समान थे जो सापा के घुसने के लिए ही बिल बना रहे थे। उनकी फरियाद कौन सुने? कोई नहीं—एकदम बाई नगा।

सेतिहर मजदूरों का किस दर से पैसे दिए जाते थे? 1842 ई० में एक मजदूर का प्रतिदिन एक आना मिलता था। तब एक रुपये में 40 मन चावल मिलता था। 1922 ई० में चावल एक रुपये में 5 सर के दर से बचा जाता था जबकि एक मजदूर का दैनिक मजदूरी 4 से 6 आना थी। 1842 में 1922 ई० के 80 वर्षों के दौरान मजदूरी में 4 से 6 गुनी वृद्धि हुई, जबकि चावल के मूल्य में 8 गुनी बढ़ोतरी हुई। फलस्वरूप वास्तविक मजदूरी में 25 से 50 प्रतिशत की गिरावट आयी। 1842 ई० में कोई मजदूर एक आना से दस सर चावल खरीद पाता था जबकि 1922 ई० में वह 5 से 6 आना में लगभग डेढ़ सर चावल खरीद पाता था।

सेतिहर मजदूर का काम मासमी होता है। अधिकांश स्थानों में येन बाने और बाटने का काम वष में एक बार होता था। मजदूरों के पास कज लेने के जलावा और बाई चारा नहीं था। लाखों लोग कबल कज के बल पर अपनी गाड़ी चलाते थे। कज के साथ-साथ उनकी जिन्दगी में थपमान न भी प्रवेश किया।

स्वतंत्र मजदूरों का एक बड़ा हिस्सा बंधुआ मजदूर बन गया। उन्हें फिर कभी मानवोप मर्यादा नहीं मिल सकी।

कज देकर गुलाम बनाने की नीति आदिवासियों के मामले में काफी पहले शुरू हो गयी थी। 1855-56 में जो सथान विद्रोह यानी हूल हुआ था उसका मुख्य कारण यह था कि जमींदारों और सूदखार महाजनों ने सथाला को बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की थी। उन दिनों के बलकत्ता गजट में यह उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार सथाला के भालेपन का नाजायज फायदा उठा कर सूदखोर महाजन उनसे 50 प्रतिशत से 500 प्रतिशत तक सूद बसूलने थे। कज के एवज में मजदूरों को गुलामी के पट्टे पर दस्तखत करना पड़ता था। हटर लिखित इतिहास में जवरन गुलाम बनाये जाने की घटनाओं के स्पष्ट मदभ मिलते हैं। इस काम में जमींदारों और महाजनों को सरकार की पूरी मदद मिलती थी। मिथू और कानू के नेतृत्व में किये गये हूल तथा प्रतिरोध की अन्य घटनाओं के पीछे—जो अंग्रेजी राज के दौरान घटित हुए—इसी शमनाक शोषण का हाथ था।

9034

अपनी पुस्तक 'भारत की भूमि समस्या' में प्राफेसर राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि स्याही खेतिहर मजदूर भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर जाते थे। नकद के रूप में पारिश्रमिक पाने की घटनाएँ इन्का दुकरा ही थीं। इन खेतिहर मजदूरों के बीच गुलामी के कई रूप देखने को मिलते हैं। कुछ तो विशुद्ध गुलाम थे और कुछ गुलाम जैसे थे—फकत बहुत मामूली या। जमींदारों मालगुजारों तथा इस तरह के अन्य वर्गों ने कज व घातक जाल के जरिए अपने गुलामों का पगु बनाने का मिलसिना चना रखा था। भारत के कई हिस्सों में यह प्रथा आज भी जारी है। यह निकट प्रथा वाप के बाद बट क द्वारा चलायी जाती थी। महाराष्ट्र की दुधिया और कालिया जातियाँ गुलामों में बेहतर नहीं हैं। इनमें से अधिकांश पीढ़ी दर पीढ़ी अपने मालिकों की गुलामी करत रहे हैं। मद्रास व दक्षिण पश्चिम में एन्नावा, चेम्मा, पुली और होलिया पाय जाने हुए जास्तब में गुलाम हैं।

मद्रास के पूर्व में समुद्र से घिरी नदियाँ की तटवर्ती जमीनों पर ब्राह्मणों की मिल्कियत है। स्वाभाविक तौर पर मजदूरों पर आ और परिजाला का अधिकार हिस्सा अछूत भी है। काफी पहले अपने पुरखा द्वारा लिये गये कज को जदान कर पाने के कारण परिजाला के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी चलती रही है।

इस तरह के कज कभी चुकता नहीं हो सकते और यह बोझ एक के बाद एक अगली पीढ़ी पर खिसकता गया। जहरत पड़ने पर मालिक इनकी जमीन बेच सकता है लेकिन ये गुलामों को एक मुश्त सौदे का हिस्सा है और इस प्रकार वे खरीदार की सम्पत्ति बन जाते हैं। इस तरह के गुलामों की सूची में विहार

कमिया है जो बेहद निचले बग व है और बज की जमीन म जकड़े हुए है। अपने बज से जाशिक छुटकारा पाने के लिए उनके मालिक ऐसे काम उनस ल सक्ते है जिनका बयान भी नहीं किया जा सकता।
इस तरह के कजों के बारे म अब हम बताएंगे।

(2)

अब हम छोट किसाना और खेतिहर मजदूरा द्वारा लिय गये बज का विश्लेषण करेगे। हमने पहले ही इनकी आर्थिक अवस्था भारतीय अर्थ-व्यवस्था म इनकी स्थिति इनके स्थान तथा बज लेने के कारण पर प्रकाश डाला है। छोटा किसान अपन परिवार या भरण पोषण करने के लिए अपनी जमीन से पर्याप्त उत्पादन पान म असमर्थ है। इसी के साथ बरा, बीज पर जान बानी लागत शान्तिया और दाहकम पर होने वाले खर्चा का बोझ भी उन्हें बेचना पडता है—दवाआ पर होने वाले पच की तो बात ही अलग है। सूदखोर महाजन स पस की भीख मांगे बिना के रह ही नहीं सक्ते।

किसी काम समय म मजदूरा की आय तथा चावल के निर्धारित मूल्य की तुलना की जानी चाहिए। जाच से यह पता चलेगा कि मजदूरा का एक दिन भा पट भरना नहीं नसाय होता था। छोटे किसाना की तरह—जो अमानत करूप म अपनी जमीन गिरवी रखत थे—उन्हें भी बज लेना पडता था। जल्दी ही बज बढ़त उठत इतना हो जाता था कि उन्हें अपनी जमीन बेच देनी पडती थी और व भी खेतिहर मजदूरा की दुखद श्रेणी म आ जात थ। छोटे किसाना के विनाश का अर्थ सूदखोर महाजना को लाभ था।

सादमन कमिशन रिपोर्ट का कहना है कि किसाना का अधिकांश हिस्सा महाजना और जमीन इस्तमाल करने वाला व बज स बधा था। किसाना और खेतिहर मजदूरा की ददनाक अवस्था के लिए अंग्रेजा व अलावा और कोई जिम्मा दार नहा है। इन पर बज का जस जसे बाध बढता था ब्रिटिश शासक द्वारा की गयी प्रगति की रफ्तार और तब हो जाती। निरन्तर आन वाली रिपोर्टों म ग्रामनौर स पिछले 50 वर्षों की अवधि म बज के निरन्तर बढ़त बाझ, हुताशा म बेची गयी और गिरवी रखी गयी जमीना का जिक्र 1911 ई० म सर एडवड मयनागा न अपन बयान म किया है।
1911 और 1938 व बीच की अवधि के आँकड़ा पर यदि एक निगाह डालें तो बात बहुत साफ हो जाती है।

वर्ष	कज का बोझ (रुपये में)
1911	300 करोड़
1924	600 करोड़
1930	900 करोड़
1935	1200 करोड़
1938	1800 करोड़

इस बात से कोई इकार नहीं कर सकता कि गावों में गरीबी का कारण कज का यह बोझ ही है। कुछ सर्वेक्षणों से पता चला कि अधिकांश मामलों में किसानों ने मवेशी खरीदने, खेतों के लिए लागत पूजी जुटाने और करों के भुगतान के लिए कज का सहारा लिया। कज का 1/5वां से भी कम हिस्सा सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए खर्च होना था। आज की हालत भी पहले से भिन्न नहीं है। अभी हाल के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि उपकरणों तथा बीजा की खरीद के लिए तथा करों का भुगतान करने के लिए किसान लोग प्राप्त ऋण का 47.5 प्रतिशत खर्च करते थे। केवल लगभग 33.7 प्रतिशत राशि को सामाजिक दायित्व पूरा करने पर खर्च किया जाता था।

किसानों की निरंतर बढ़ती कजकारी के असली कारणों का बड़ी कुशलतापूर्वक छिपाया जाता था। कहा जाता था कि किसान अपनी चादर देखकर पैर नहीं फलाते। किसी कंगाल का महल के मपने देखने की क्या जरूरत? सामाजिक और धार्मिक अवसरों पर वे क्यों इतना पैसा बहाते हैं?

पहले, पैसे का प्रमुख स्रोत गांव का महाजन होता था। अंग्रेजों के आने से पूर्व, किसान व्यक्तिगत गारंटी पर उनसे कज ले सकते थे। इससे वे निरुपय नहीं होते थे, क्योंकि महाजन को भी गांव के ही बायदे कानूनों का पालन करना पड़ता था। गांव का समाज किसी का इस बात की इजाजत नहीं देता था कि कज चुकता न होने पर उनकी जमीन हड़प ली जाये। अंग्रेजों ने इन सारे नियमों को बदल दिया और सूदखोर महाजन गांवों के मालिक बन बैठे। अंग्रेजी शासन का प्रारंभिक दिनांक यही महाजन बस फसल लेने के बाद किसानों को छोड़कर था — उनकी जमीन नहीं छूटे थे। लेकिन अंग्रेजी राज ने ठूपापूर्वक इन महाजनों के अधिकार बढ़ा दिये और कानून, पुलिस तथा ब्रिटिश सरकार के भरपूर समर्थन से उन्हें जमीन पर कब्जा करने का अधिकार मिल गया। सूदखोर महाजनों को अब सारी फसल जब्त करने का अधिकार मिल गया। और यह सब करने के बाद भी कज को ज्यों का त्यों दिखाया जाता था। मूल और सूद में कौन क्या है — किसे यह पूछने का साहस था?

महाजन के कोठार में जो अनाज चला जाता था उसमें से ही फिर किसान

को अपना पट चलाने के लिए बज्र मिलता था। और इस प्रकार बज्र पर बज्र बढ़ता जाता था। किसानों को कवि ने एक बार कहा था कि अगर आवाज का बागज बना दिया जाय समुद्र का दायात और घास का बलम तो भी उसकी कविता पूरी नहीं होगी। गाँवों में बज्रदारी का वृत्तांत लिखने के लिए आवाज समुद्र और घास की बलम भी पर्याप्त नहीं साबित होगी।

हर बार इस कथा का अंत बज्र चुकता करने के लिए हताश हाथों जमीन खेचने और स्वतंत्र किसानों के बटाइदार अथवा सतिहर मजदूर बनने में होता था। इस प्रकार गाँव के महाजन छोटे माटे पूजोपति और किसान उनका मजदूर बन गए।

कम्पनी द्वारा संचालित सरकार ने खुद अपने स्वार्थों के लिए महाजनों का बड़ावा दिया।

1799 ई० में मातव विनियमन—कुछान हैफ्टम ला —की घोषणा हुई। इस कानून ने जमींदारों और महाजनों का खयता तथा किसानों में जमीन खाली करवाने के अधिकार दे दिए। इसका अलावा किसानों पर पावदी लगा दी गयी कि वे एक जमींदार को छोड़कर दूसरे के पास जाने के लिए अपना ब्लाका नष्ट छोड़ सकें। साथ ही वे कहीं और काम भी नहीं कर सकें।

1812 ई० में पाचव विनियमन — पजन ला — का लागू किया गया। इस कानून के जरिए जमींदार पहन से ही करा की दर तय कर सकता था और फिर खती के लिए लाइसेंस का वितरण करता था। इस लाइसेंस का कभी भी वापस लिया जा सकता था। फल जल करने का अधिकार पहन ही 1793 ई० से दिया जा चुका था।

मुगल शासन काल में करा की दर को मनमाने ढंग से नष्ट करता जा सकता था। लेकिन विशेष स्थितियों में अनिवार्य अवकाश (उपकर) लगान की इजाजत थी। 1859 ई० के बंगाल कर कानून के मुताबिक निर्धारित कर का जमींदार किसी भी बहाने से बढ़ा सकता था। समूचा देश उन खूबों के व्यक्तियों का शिकारगाह बन गया।

कई मामलों में ये सूदखोर महाजन खुद ही जमींदारों या विचौलियों बन गए। फलस्वरूप एक ही तरह के लोग न—जिन्हें चाहे जमींदार कहिये या ताल्लुकेदार पट्टनीदार गरीदार या महाजन—लूटमार का मुनियोजित कार्यक्रम शुरू कर दिया। करा के अलावा किसानों को उस समय घूस भी देनी पड़ती थी जब उनसे दर स कर जमा करने आदि जसी छोटी मोटी चीजें चूक जाती थी। अनेक छोटे मोटे अधिकारी भी थे जिन्हें चुश रखना पड़ता था। जमींदारों का एकाउंट उसका कास्टेबल उसका बारिदा—इन सबकी हथेली गरम करनी पड़ती थी। घूसखारों को एक प्यारा सा नाम दे दिया गया था—इन धोती

खरीदना' कहते थे। लेकिन कवि मुकुन्दराम इस पर अफसास जाहिर करते हैं कि 'धानी खरीदने से भी किसानों की सुरक्षा नहीं मिल पाती थी। फसल जब्त होनी और यहाँ तक कि जमीन से बेदखल होने का खतरा हमेशा सर पर भँडराता रहता था। अदालतों से कोई मदद नहीं मिलती थी। व जमींदारों के बैठकघरों की तरह थी।

जो स्थिति तब थी वही आज भी है। जमींदारों, विचौलियों और महाजनों की फरमाइश पूरी करने के बाद गरीब किसानों के पास कुछ भी नहीं बचता था और उसे फिर बज का सहारा लेना पड़ता था। एक कहानी है कि किसी ऊँद विलाव ने एक मछली पकड़ी और उस बाटन का काम जंगली बिल्ली का दिया। नतीजा यह हुआ कि मछली का पकड़ने के लिए ऊँदविलाव का फिर पानी में गाना लगाना पड़ा।

निश्चय ही यह बड़ी निराशाजनक स्थिति थी। फसल के रूप में दिया गया बज पर 150 प्रतिशत और नकद के रूप में दिया गया बज पर 200 प्रतिशत मूल्य लगता था। और बज की यह धाली जंगली पीढ़ी के गिर पड़ती थी। जहाँ तक कानून की बात है— वह हमेशा धनिका की मदद करता था।

क्या बिमानों ने इन प्रचुर भाग्य के सामने हथियार डाल दिए थे? नहीं, कई स्थानों पर उन्होंने विद्रोह किया। उनके अंदर न तो बग-चनना थी, न मगठन था और न बुशम नेतृत्व हो था जिसमें वे विजयी हो सकें। बशक उन्होंने अपने दुश्मनों की शिनाख्त कर ली थी। उन्होंने सरकार, उसके शक्तिशाली मगठन जमींदारों और महाजनों के नकायतों के चेहरों की आलियत का समर्थन किया था। हमें उदाहरण के तौर पर अंग्रेजी काठियों पर हमला किया जाने अस्मित्व की उदाहरी उदाहरण के तौर पर राणाजीव महल मिला। इसके बाद उत्तराखण्ड में—नीलमौर के नेतृत्व में धारावाहिक का बहाली विद्रोह, फरीदपुर का फराजी विद्रोह 1832-33 में मानास में बृषि विद्रोह, 1831-32 का कान विद्रोह 1855-56 का मयान विद्रोह, नील बागा के मजदूरों का विद्रोह पायना-बागुडा का किसान विद्रोह दखन का किसान विद्रोह, मालाबार में मापना बिमानों का विद्रोह। क्या इन फरमाइशों का भूला जा सकता है? हजारों बिमानों के मूलों से रंगी धरती पर आज अनाज के घेत ध्येय सड़के शहर, दूबान और बाजार पत हैं। लेकिन उन विद्रोहों की मर्यादों को मामूली की ली की तरह पक कर बुझाया नहीं जा सकता। यह अभी संभव नहीं है।

अपने नामों के विद्रोहों में कुछ साम्राज्याधीनता का इतिहासकारों ने किसानों के विद्रोहों का काफी समझा छोड़ा आवरण चढ़ाने का जनाता का मामला पेश किया है। जनता का पता पता कि यहाँ साम्राज्यिक दंग दरिद्रों की आँखें थीं। आज की भाषा में इन उदाहरणों का नामांकन विद्रोहों—प्रधानों अथवा अंग्रेजों नाम

म सुनते हैं। अंग्रेजों के दमन के खिलाफ सघप करने वाले वह पहले विद्रोही नेता थे। यह घटना 1780 ई० में भागलपुर में घटित हुई। उन्होंने अपनी सेना का निर्माण किया और पांच वर्ष तक लड़ते रहे। उन्होंने ही छापामार युद्ध के जरिए भागलपुर के बलकट्टर क्लीवलैंड का सफाया किया। 1855-56 के विद्रोह पर उनके सघप का जबरनस्त प्रभाव पड़ा था। तिलका माषी का नाम पुराने रस्तावेजों में पाया जा सकता है हालाँकि इतिहास के शोधकर्त्ताओं का उनके नाम का उल्लेख करना गवारा नहीं है।

सन 1855-56 के सवाल विद्रोह की मुख्य मांग थी कि खेती योग्य तैयार की गयी जमीन पर अधिकार को उनकी मांग की सुनवाई की जाय। साथ ही जमादारा, मदानना और सरकारी जफतारा तथा पुलिस को उनके इलाके में प्रवेश की इजाजत न दी जाय। कमिया या गुलामी की कुख्यात प्रथा को खत्म किया जाये। दूसरे शब्दों में कहें तो यह आजादी की लड़ाई थी। खेती गवा, हलगाया हो' (हम सचमुच लड़ेंगे) की रणभेरी के साथ उन्होंने सघप को जागे बढ़ाया। सवाल ने धने जगला का साफ करके जमीन का खेतीबाड़ी करने और रहने के योग्य बनाया था। उन्होंने इसमें फसलें पैदा की। व्यापारियाँ और सूदखोर महाजना ने उनके भोलेपन, ईमानदारी तथा सीधेपन का बड़ी क्रूरता के साथ फायदा उठाया। फसल की कटाई के समय वे अपनी खाली बैलगाड़ियाँ लेकर पहुँचे और उनमें फसल भरने लगे। बदले में इन धूर्तों ने उन लोगों को थोड़ा सा नमक तम्बाकू तथा शीरा दे दिया—कभी कभी कुछ सिक्के भी दे दिये। इस प्रकार जमींदारा, पुलिस और यूरोपीय जिला मजिस्ट्रेटों के पूरे समर्थन से फसल पर उनका कब्जा हो गया।

बरसान के मौसम में गरीब सत्थान भूखा मरते थे। सूदखार महाजना ने उन्हें कज लेने को मजदूर किया और कज सम्बन्धी रक्का पर उनके अमूठे के निशान न लिये। अगर एक दिन सवाल महाजना से उधार लिये जनाज को खाता था तो आने वाले दिन वह आर उसका परिवार पूरी तरह उस महाजन की गुलामी की जजीरा में बंद मिलता था। 33 प्रतिशत चन्चवद्धि व्याज की दर से देयते देखते देखते कुछ रुपये सैकड़ों रुपये में बढ़ल जात थे। एक दिन वह सवाल मर जाता है आर उसका बेटा अपने बाप के अंतिम सस्कार के लिए फिर पैसा उधार लेता है। कज देने हुए महाजन की बाँछे खिल जाती है। लोनकथाओं का जादुई तोता राजकुमार को हीरे मानी और मणि देने के लिए उकसाता था। सूदखोर महाजन न भी भोने वाले सवाल के साथ यही किया जिन्हें यह कभी जाभाम न हो सका कि वह जो कज आज ले रहे हैं वह भविष्य के ग़म में पत्नी पीढ़ियों के लिए भी एक अदृश्य जजीर बनने जा रहा है। महाजन की इस धमकी से कि वह उन्हें जेल भेज देगा सवाल कांप उठत थे। वे खुले आवाज और बिस्तार क्षितिज के प्राणी

ई० में बंगाल का शक्तिशाली कानून पारित हुआ। इस कानून ने जमीन के अधिग्राही जन किये जाने तथा किसानों का जमीन से प्रेदखल करने पर रोक लगा दी।

इसके कुछ ही समय बाद दक्खिन में मोपला लोग का विद्रोह हुआ। दरअसल यह 1873 में ही शुरू हुआ था और 1921 तक चलता रहा। मोपला लोग ने— जो धर्म से मुसलमान थे— दमन की तीव्र शक्तियाँ अर्थात् अंग्रेज़ों जमींदारों और सूदखार महाजनों के खिलाफ हथियार उठाया। यह विद्रोह तेज होता गया और फिर इसने खिलाफन विद्रोह का रूप ले लिया। दुश्मन ने भी अपनी ताकत बटाई। अंग्रेज़ों की सेना और पुलिस का जमींदारों और सूदखार महाजनों की निजी सेना ने मदद पहुँचायी जिससे बाकायदा बतन प्राप्त करने वाले सैनिक थे। वे मालुवागाड और एरनाम में उतरे। बड़ी बरहमी से उन्होंने मोपला लोगों का बत्लेआम किया। उनके अत्याचार आतंक के पर्याय बन गये।

बावजूद इसके मोपलाओं ने मघप जारी रखा। उन्होंने एलान किया कि उनकी धरती आजाद है और अली मुजलिफ़ार को उन्होंने अपना स्वतंत्र राजा बनाया। लेकिन अंग्रेज़ बेहद मजबूत थे। उनके पास आधुनिक हथियार थे। उनसे निपटने के लिए छापामार युद्ध ही एकमात्र तरीका था। 48 वर्ष के दौरान मोपलाओं ने पाँच बार विद्रोह किया।

पाँचवें विद्रोह के बाद उन्हें हथियार डालन पड़े। अंग्रेज़ों ने सक्का विद्रोहियों को गोली से उड़ा दिया और विद्रोह के प्रमुख नेताओं का सावजनिक स्थान पर फाँसी पर लटका दिया।

लेकिन ये विद्रोह आंशिक रूप में सफल रहे क्योंकि इन विद्रोहों के कारण ही अंग्रेज़ शासकों ने 'महाजन कानून' पारित किया।

जो जाने कुरबान गयी उनकी तुलना में जो छोट मोटे काम हुए उनके लिए ज़रूरत में ज्यादा कीमत जदा करनी पड़ी। दमन अभी भी बरकरार था। महज कानून पारित करने का मतलब कुछ नहीं होता। कानूनों का अमल में भी लाया जाना चाहिए था। यह कभी नहीं हुआ।

लेकिन विपत्ति अभी भी घात लगाकर बैठी थी। इन गरीबों के जपट लागू का घोषा देने के लिए जाली बागजात की मदद करना बहुत आसान था। अदालतें जमींदारों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। कानून का अमल में लाने के लिए नियुक्त जफ़सरा का घूस देकर भ्रष्ट कर दिया जाता था। 1928 ई० के मनी आयोग में बड़ी बहुता के साथ लिखा कि लागू अपनी किस्मत पर बहुत निर्भर रहते हैं और अपनी जमीन बचाने के लिए सूदखार महाजनों के आग्रह मानते हैं। इसमें कहा गया था कि इस प्रकार महाजनों का शक्ति दिना दिन बसता जाता है।

आयोग ने सच्चाई का बयान नहीं किया। इसने यह तरीका बताया कि इस

काम में सरकार उनकी मदद करती है।

1931 में सेंट्रल बॉय जाव समिति की रिपोर्ट ने उन्हीं दो तथ्यों का दुहराया जिससे बार में हम पहले से जानते हैं। पहली बात तो यह कि ब्रिटिश शासन-काल में प्रारंभिक दिनों में किसानों को इसलिए सरकार के दमन का शिकार होना पड़ा क्योंकि वे कर का भुगतान नहीं कर सके थे। दूसरे, बाद में उन्होंने अपनी जमीन बच दी और खेतिहर मजदूर अथवा बंधुआ मजदूर बन गये।

इस प्रकार किसानों की जमीन पर उन लोगों की मिल्कियत हो गयी जो खेती नहीं करते थे। भावात्मक सम्बन्ध समाप्त हो गया। वर्ग विभेद और भी खुलकर सामने आ गया तथा खेती-बाड़ी के काम में कमी आयी।

यहाँ तक कि आज भी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक असंतुलन, उत्पादों के मूल्य में गिरावट, द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रभाव तथा व्यापक अकाल के कारण खेती का काम बड़े सक्लपूर्ण दौर से गुजर रहा है।

उत्पादना की कीमत गिरने के साथ ही किसानों की भी स्वतन्त्र कृषि शक्ति में कमी आयी।

आँखों से पता चलता है कि अथर्व्यवस्था में भयंकर सिकड़ शुरू होने से पूर्व सन् 1928-29 में वृषीय उत्पादन का औसत मूल्य फसल कटने के समय 1034 करोड़ रुपये के बराबर था। 1933-34 में इसमें कमी आयी और यह 473 करोड़ रुपये रह गया। कीमतें तो गिर गयीं लेकिन टैक्स में कोई कमी नहीं हुई। 1928-29 में भूमि कर के रूप में कुल राशि 33 करोड़ 10 लाख रुपये थी। 1932-33 में भी यह राशि 33 करोड़ ही बनी रही। 1933-34 के दौरान जनता किसानों को अपनी जमीन में हाथ धाता पड़ा। वे करों का भुगतान नहीं कर सके जबकि यह राशि कम हो गयी थी और 30 करोड़ रुपये पर आधारित रह गयी थी।

1934 ई० में बंगाल पटवन्त जाव समिति की रिपोर्ट में बताया गया था कि बंगाल में 1920-21 में लेकर 1929-30 तक बिन्नी योग्य उत्पादना का औसत मूल्य 72 करोड़ 40 लाख रुपये था। 1932-33 में यह कम होकर 32 करोड़ 70 लाख रुपये हो गया। दूसरी तरफ वित्तीय दयताएँ 27 करोड़ 90 लाख रुपये में बढ़कर 28 करोड़ 30 लाख रुपये तक पहुँच गयीं। यदि हम विश्लेषण करें तो पता चलता है कि किसानों की स्वतन्त्र कृषि शक्ति 44 करोड़ 50 लाख रुपये में बढ़कर 28 करोड़ 30 लाख रुपये हो गयी।

और एक तथ्य का बराबर अनङ्ग्य किया गया है कि जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा रहा।

मजदूरों का भी करों का भुगतान करने का अवसर 71,430 किसानों का अपनी जमीन में हाथ धाता पड़ा। साथ ही उनमें करों की बगुनी के लिए

2,56,284 वारट भी जारी किये गये ।

कृषि-याग्य भूमि का दायरा निरतर कम होता गया क्वाकि अधिकांश व लाग, जिनके हाथ म जमीन पहुँची थी खेती-वाडी का काम नही करते थे । यह एक बहुत भयकर पड्यन था । जमीन के कम हिस्से को खेती के लिए इस्तेमाल करने मे उन लोगा को ज्यादा फायदा दिखायी देता था । इस प्रकार वे उत्पादना की आपूर्ति का नियमित कर सकते थे और निधन जनता को ज्यादा से ज्यादा कज लेने के लिए प्रेरित कर सकते थे । आम जनता के खून से तैयार समृद्धि की इस मदिरा ने नय भू स्वामिया का मदहोश कर दिया था ।

1933 34 मे कुल 23 करोड 30 लाख एकड जमीन म खेती-वाडी हाती थी । 1934 35 के दस्तावेजा को देखने से पता चलता है कि इस क्षेत्रफल मे कमी आयी और यह 22 करोड 60 लाख एकड हो गया । अनाज के उत्पादन-याग्य भूमि के क्षेत्रफल म 55 लाख 89 हजार एकड की कमी आयी थी । किसाना को पीडा असीम थी । वावजूद इसके किसी ने भी उनके कष्ट पर ध्यान नही दिया ।

बंचारे मुकुंदराम । उनका स्वर नक्कारखाने मे तूती की आवाज बनकर रह गया । सच्चाई तो यह थी कि किसी ने उन किसाना के बारे म सोचने का कष्ट ही नही किया ।

1934 ई० से किसाना की आर्थिक अवस्था मे तेजी से गिरावट आयी और व कज के सागर मे डूब गये । वे भूख की भट्टी मे तप रह थे और भूख को इससे काई सरोकार नही कि वह किसी अमीर आदमी के पास है या गरीब के पास ।

1931 से 1937 के बीच कज की राशि 67 करोड 50 लाख पौंड से बढ़ कर 134 करोड पौंड हो गयी ।

सबसे बडी विडम्बना तो यह थी कि हमार राष्ट्रीय नेताआ ने आजादी की लडाई पहले ही से शुरू कर रखी थी । व अपने कट्टर दुश्मन अर्थात अंग्रेजा के बारे म खूब चचाएँ करते थे लेकिन कभी भी जमींदारो और महाजना का नाम नही लिया जि होने पूरी अव्यवस्था का दीवालिया बना दिया था ।

अंग्रेज के चेहरे पर एक कुटिल मुसकान थी क्वाकि उसे पता था कि वह हमार समाज मे आत्म विनाश के बीज बो चुका है ।

द्वितीय विश्व-युद्ध की शुरुआत और बमा मे जापानी फौज के पहुँचने के साथ ही वह घटिया चावल भी मिलना बंद हो गया जिसका विदेशो से आयात किया जाता था । इसका बाद ही हमारी कृषि की दुव्यवस्था की तसवीर सबके सामने आयी । इस घटिया चावल का गरीब लोग खरीद सकते थे लेकिन इसका आयात बंद हाने के साथ ही अनाज का भयकर सकट पैदा हुआ । कोमता मे भी तेजी बढ़ि शुरू हुई । उन दिनों के गीता मे पता चलता है कि वहा कितनी

स्थिति थी।

अंग्रेज़ों ने अनाज की सप्लाई की कोई व्यवस्था नहीं की थी। इससे विपरीत सैनिक साज सामान की सप्लाई के काम में तनिक भी बाधा नहीं पड़ी और वस्तुतः किसानों की लूट में अर्जित धन में ही यह काम होता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि दश भयंकर मुद्रास्फीति की चपेट में आ गया। ज़ख़ीरवाज़ा ने इस स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठाया और ख़रिद-विक्रय मुनाफ़ा कमाया।

इस प्रकार 1943 ई० के मानव निर्मित अकाल का जन्म हुआ।

सरकारी आकड़ा के अनुसार अनाज की सप्लाई में 14 लाख टन की कमी हुई। उन्ही आकड़ा के अनुसार अक्टूबर-नवंबर में 35 लाख लोग मौत के शिकार हुए। अकाल के बाद महामारी का हमला हुआ। इसमें और 12 लाख लोग मारे गए। बड़ी कुशलतापूर्वक उत्पन्न किये गए इस अकाल में महानगरों और काला बाज़ारों का 150 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा हुआ।

इस अकाल को हमारे इतिहास विषयक अभिलेखागारों में 'बचाम' के अकाल के रूप में एक खाना मिल गया क्योंकि 1943 का वर्ष और बंगाली कलेंडर का वर्ष 1350 एक ही था। यह अकाल और 1770 का अकाल एक युगांतरकारी घटना थी।

1943 के अकाल ने लगभग 75 प्रतिशत किसानों की कमर तोड़ दी। उनमें से प्रत्येक के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन थी जिससे उस किसान और उसका परिवार के सदस्यों का भरण पोषण के लायक भी अनाज नहीं पैदा हो सकता था। यह स्थिति और भी भयंकर हो गयी थी क्योंकि ज़ा भी चावल उपलब्ध था उसे मई माह के आते-जाते ज़ख़ीरवाज़ा ने छिपा कर रख दिया था। इस दुष्टतापूर्ण कार्य में सरकारी अधिकारी व्यापारी काला-बाज़ारी आदि ज़मींदार—सभी शामिल थे।

अकाल के शिकार सबसे पहले गरीब किसान हुए और फिर छोटे किसानों की बारी आयी। इन सबका अपनी ज़ोना से हाथ धोना पड़ा। अप्रैल 1943 से जून 1944—यानी अकाल ने एक वर्ष के अकाल को देखने से कई दिलचस्प तथ्यों का पता चलता है। इनसे बंगाल के 15 90 000 किसानों की किस्मत का जानकारी मिलती है

देखी में लगे परिवार

जिन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा	2,60,000
जिन्हें अपनी जमीन का एक हिस्सा बचना पड़ा	6,60,000
जिन्हें अपनी फसल गिरवी रखनी पड़ी	6 70 000

अकाल के दौरान 7 10 000 एकड़ जमीन पर मित्कियत की फरवदल हुई। इसमें से केवल 20,000 एकड़ जमीन ज़मींदारों और महाजनों के हाथ

लगी। लगभग 4,20,000 एकड़ ऐसी जमीन में हाथ में पहुँची जो खेती नहीं करती थी। साथ ही किसानों पर वज्र का बोझ अभूतपूर्व ढग से बढ़ गया।

अनुमान के अनुसार 1943 में कृषि में लगे लगभग 43 प्रतिशत परिवार वज्र में डूबे हुए थे। 1944 में यह संख्या 66 प्रतिशत तक पहुँच गयी। इससे पहले भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की इतनी बड़ी तादाद देश में कभी नहीं देखने में आयी थी। हम उन्हें अब भी किसान ही कहेंगे क्योंकि वे ही ऐसे लोग थे जो जानते थे कि किस प्रकार वज्र घरती कालहलहात खेता में बदला जा सकता है। किसानों पर वज्र की राशि कितनी मामूली-सी थी। पर इस मामूली-सी रकम के एवज में वे गुलाम बन जाते थे और इस तरह के कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं

उदाहरण—1

एक किसान ने कभी दो मन चावल उधार लिया जिसे वह लौटा नहीं सका और उसे बधुआ मजदूर बनना पड़ा।

उदाहरण—2

एक किसान 'क' के परदादा ने अपने भू-स्वामी से 17 सेंटर जी उधार लिया था। परदादा और उसके बेटे जबकि 'क' के बाप का बधुआ मजदूर के रूप में जिंदगी बितानी पड़ी। 'क' को भी अपने मालिक का गुलाम होकर रहना पड़ा। 'क' के परिवार ने 1978 तक भू-स्वामी को 2600 रुपये का भुगतान किया था। भू-स्वामी का कहना था कि अभी 300 रुपये उनकी तरफ बकाया पड़े हैं।

उदाहरण—3

उदयपुर में जीरा नामक एक अनाथ का उसके चाचा ने 80 रुपये का वज्र चुकता न करने के कारण ज़मींदार को बेच दिया। अब जीवा तब तक गुलाम बना रहेगा जब तक वह मर नहीं जाता।

उदाहरण—4

मध्य प्रदेश में सनना में, काबू के चाचा ने उसे 150 रुपये में बेच दिया।

उदाहरण—5

तमिज़नाडु के दक्षिणी आरकाट ज़िले में अरमुगल के पिता ने 100 रुपये चुकता न करने के कारण अपने बेटे को ज़मींदार के हाथों बेच दिया। हम उस नौ आन का भी नहीं भूलना चाहिए जिसने किसी का जीवन भर के

लिए गुलाम बना दिया। दशमलव प्रणाली शुरू होने से पहले पनामू जिले के एक आदिवासी ने जमींदार महाजन से वह गशि उधार ली थी। 1976 तक वह बड़ा उतर नहीं सका था और यह अभी भी बना रहेगा।

एक वधुआ मजदूर अपने मालिक से क्या पाता है? मामूली मा वेतन और थोड़ा खाना। अगर वह चाहता मालिक उसे आजादी द सकता है। लेकिन क्या वह कभी ऐसा चाहता है?

वधुआ मजदूर कभी गांव छोड़कर नहीं जा सकता। अपने थम और अपने उत्पादन को वह खुद कभी नहीं बेच सकता। कभी तो वह अकेले और कभी अपने पूरे परिवार के साथ गुलाम बना रहता है। 1921 ई० में बम्बई जनगणना, जायोग ने गुजरात के हाली लोगो के बारे में एक रिपोर्ट दी थी। जमरीबा में वह युद्ध से पूर्व के वागाना में काम करने वाले गुलामों की तरह ही हाली नाम से पूरी तरह गुलाम की जिंदगी बिताते थे।

(3)

1931 ई० में भारत में 30 लाख वधुआ मजदूर थे। खेती बाड़ी से सम्बन्धित कुल आवदी का यह 3 प्रतिशत हिस्सा था। भूमिहीन किसानों की सख्या के बारे में अध्ययन करने से पता चलता है कि आजादी के बाद वधुआ मजदूरों की सख्या में किस तरह और क्या बढ़ि हुई?

संदर्भ ७५ 1931

1 सतिहर मजदूरों की कुल सख्या—4 करोड़ 20 लाख

2 वधुआ मजदूरों की सख्या—30 लाख

3 मामूली वेतन पर काम करने वाले मजदूरों की सख्या—3 करोड़ 50 लाख

4 दैनिक दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों की सख्या—40 लाख

1. मुद्राजन 24 वा प्रतिशत 37 8

1891 में यह प्रतिशत 13

गतिर मजदूर मालिकों और महाजनों में उधार लेते—यह तो स्वाभाविक है। हम प्रकाश गुलाम वर्गों यह भी बहुत स्वाभाविक है। यह धनित कारोबार जारी रहेगा यह भी स्वाभाविक है।

हम प्रकार प्राथमिकता की भावना हमारे ऊपर इस तरह काम करती है। हमें तत्वान जिस चीज की जरूरत है वह है रंगा टलिविजन। वधुआ मजदूर का बचान जमा शरीर रंगीन डिग्राया जाय तो थांग बेहतर लगेगा और धूप में चमकनी पकी फगन में मरे गाता की पछमूमि हो तो क्या करने।

बेतिहर मजदूरों की एक विशाल फौज है। गरीब किसानों का सत्या भी कम नहीं है। 1931 में उनकी संख्या 3 करोड़ 70 लाख थी।

आगामी का केवल 33 3 प्रतिशत हिस्सा खेती बाड़ी में लगा था। जमीन मालिक थी। इसलिए उन्हें जमींदारों और महाजनों पर निर्भर रहना पड़ता था। बसी विडम्बना है, ज़ेद पर बकर की निर्भरता। खानी मामूली जाय से बेकज चुकना नहीं कर पाते थे। ब जमीन में हाथ धोकर माघाण मजदूर बन गये। लेकिन काम भी पर्याप्त नहीं था। उनके पास काम की गारंटी नहीं थी और आज भी नहीं है। 1931 में 4 करोड़ 20 लाख बेतिहर मजदूरों में से 3 करोड़ 50 लाख बेरोजगार थे। एक बहुत बड़े हिस्से को वातान दर से काफी कम मजदूरी पर काम करना पड़ता था।

दैनिक दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों का एक हिस्सा, जिनकी लागत 40 लाख थी, चाय बाँपी और रबर बागानों में काम करने लगे। 1929 में इस श्रेणी में 10 71 000 मजदूर थे। आधे से अधिक लगभग 5 57 487 व्यक्ति जमम के चाय बागानों में नग हुए थे। बगानों के बागानों में 1 96 899 और मद्रास के विभिन्न बागानों में 1 02,700 मजदूर काम कर रहे थे। 1946 में ब्रिटिश राज के अंतिम दिनों में यह संख्या बढ़ कर 10 91 461 हो गयी थी।

चाय और काफी बागानों में काम करने वाले मजदूरों का मान सम्मान के लिए स्वतंत्र थे। वास्तविक अर्थों में उनके हिस्से में गुनामी ही थी। उन्हें काम के समय मालिकों उनसे स्वका पर अगूठे के निशान लगवाता था। ठेकेदार मजदूरों का तात्पर्य देकर बागानों में काम दिलाने ल जाते थे और फिर उन्हें वधुआ बना लेते थे। उनकी दुख भरी कहानियाँ दसजीवनी और 'द बगानी' में प्रकाशित होती थीं। द्वाराकानाथ गांगुली ने इन अखबारों का कई प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट भेजी थी। यूरोपिया द्वारा महिला मजदूरों पर किये गये अत्याचारों की कहानी कुत्रांत 'दक बाड' के जरिए काफी प्रचारित हुई। गान्धेय दस बाड का विवरण 'भारत में 'माघ की हत्या' शीर्षक में प्रकाशित हुआ।

बेतिहर मजदूरों में से अधिकांश लोग आदिवासियों और हरिजनों के बीच में आते थे। 1930 में की गयी उनकी गणना इस प्रकार थी

मयुवन प्रांत	1 करोड़ 20 लाख
बंगाल	1 करोड़ 15 लाख
मध्य प्रांत	33 लाख
मद्रास	65 लाख
बिहार और उड़ीसा	50 लाख
पंजाब	28 लाख

अमम	10 लाख
ग्रन्थई	15 लाख
सतिहर आगणी के मुकायन उनका प्रतिशत दम प्रकार था	
ग्रन्थई	57 प्रतिशत
समुक्त प्रात	21 8 प्रतिशत
बगाल	33 प्रतिशत
मध्य प्रात	52 प्रतिशत
मद्रास	54 प्रतिशत
विहार और उड़ीसा	35 प्रतिशत
पजाब	14 5 प्रतिशत
अमम	25 प्रतिशत

1931 में सतिहर मजदूरों की समस्या सती-बाड़ी में लगी जागणी का 70 प्रतिशत थी। जो आदिवासी नहीं थे वे मुख्यतया अनुसूचित जाति के तथा गरीब मुसलमान थे। मगध हिंदू तथा गैस मुसलमान पढ़े लिखे थे। उन्हें कम कलकटरी तथा जमीन के बंदोबस्त से संबंधित अन्य नौकरियां मिल गयी थी। उन्हें भली भाँति पता था कि अपढ़ किसानों से जमीन हड़पने के लिए कानून की धमियाँ का कैसे इस्तेमाल किया जाये। बंदा की गयी जमीन को अमीरा में बाँट दिया जाता था। इस प्रकार जाति और वर्ग का सूक्ष्म भेद धीरे धीरे एक हो गया। एक उदाहरण प्रस्तुत है।

उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा के समाप्त किए जाने से पूर्व पुरानी कर प्रणाली के आधार पर जमीन को 37 क्षेत्रों में बाँटा गया था। पहले 'सेहाना सरदार' नाम से ज्ञात एक ग्रुप के प्रमुख नेता के ऊपर कर वसूलने की जिम्मेदारी थी। उसके मातहत अनेक सहायक सेहाना होते थे। वे अपने प्रमुख के अधीन रहकर कर की वसूली और जमीन के निर्धारण का काम करते थे। वे सर्व राजपूत और ब्राह्मण थे। वे अनुसूचित जाति के उन लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे जो कर देने में असमर्थ होते थे। जल्द की गयी सारी जमीन को अपने वर्ग के लोगों के बीच बाँट दत्त थे। इस प्रकार अधिवाश जमीन पर राजपूत और ब्राह्मणों की मिल्कियत कायम हो गयी।

पूरे साल के लिए सतिहर मजदूरों के पास काम नहीं होता है। यहाँ तक कि सोहन शुद्ध होने पर भी सभी का काम नहीं मिलता। कुछ का इस बात पर काम मिलता है कि वेतन के रूप में वे बंधव खाना पा सकेंगे। कुछ को बंध लेने के कारण बंधुआ मजदूर बना लिया जाता है। उनके पास कोई और चारा नहीं है। बंधुआ मजदूरों का काम-में काम खाना तो मिलता था—यह बात जलम है कि क्या खायेंगे।

जहाँ तक खाने की बात है, इसका विवरण बहुत घृणाजनक है। मध्य भारत में हलवाहा को खाने का वही मिलता है जो उनके धर्मपरायण हिंदू मालिक पवित्र समझते हैं। वे अपने मजदूरों को वह अनाज देते हैं जो गाय और भैंस पचाने के कारण गोबर के साथ बाहर निकाल दी जाती है। इस अनाज का धाया जाता है और फिर हलवाहा द्वारा खाया जाता है। यह कोई कल्पित बात नहीं है और बहुत पुरानी बात भी नहीं है।

इस प्रकार एक राज्य से दूसरे राज्य तक वधुआ मजदूरों की संख्या बढ़त जाने का कारण साम्राज्यवादी भूमि-वदोस्त प्रणाली है।

वधुआ मजदूर का मामला आज भी एकदम जीवन और मशक्कत है। आज भी बेतहाशा प्रचार और धूमधाम के साथ दश में जब किसी परियाजना का उद्घाटन किया जा रहा होता है — किसी जंगल में दश की किसी मुलायम या कठोर धरती के हिस्से पर कोई अभाग्य परिवार चुनचाप गुलामी की जजीर में बसता जा रहा होता है। यह रोग काफी पुराना है पर आज भी काफी मजबूत रोग है।

अलग-अलग स्थानों में वधुआ मजदूरों का अलग-अलग नामों से जाना जाता है। वे गुजरात में हाली, दक्षिण मद्रास में इझवा, चेन्नई में पुली और होलिया मद्रास में पूर्वी नदी घाटी में परियाल तमिलनाडु में पत्तियल और पविराम, आंध्र प्रदेश में गस्मिगुल्ला, हैदराबाद में भगोला, अयोध्या में सनवक, मध्य भारत में हरवाहा, बिहार में सकिया, बमिया, सेवकिया और जतौर के नाम से जाने जाते हैं। उड़ीसा में उन्हें गांटी बरमसिया, नागा मुनिया और डडा मुनिया कहा जाता है। जम्मू-कश्मीर में इन्हें माक्षी, पन और लचरी कहा जाता है। करल में बगार और राजस्थान में सगरी नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में वेड या बगार है। उत्तर प्रदेश में मट, खडिन आर मजिमत है। सरकारी तौर पर पश्चिम बंगाल में एक भी वधुआ मजदूर नहीं है। लेकिन भतुआ, बारोमिया, महिंदर और बागल लोग वधुआ मजदूर के सिवा और कुछ नहीं हैं।

कर्नाटक में ये जुथा नाम से हैं।

इसके अलावा और भी कुछ हैं जिनके बीच क्या-क्या अंतर नहीं है।

हम बाद में उस पर विचार करेंगे।



15 नवम्बर 1947 के अविस्मरणीय दिन से पहले के 45 वर्षों में कृषि के काम जान वाली जमीन में 148 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि बाबादी में 37.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में केवल 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चूँकि उत्पादन में वृद्धि आबादी में वृद्धि की तुलना में कम थी, प्रति व्यक्ति कृषि-उत्पादकता में गिरावट आयी। हम विरासन के रूप में एक ऐसा कृषि-अप-व्यवस्था मिली थी और यह बड़ी अफसोस की बात थी, क्योंकि 1951 की जनगणना में जानकारी दी गयी थी कि आबादी का 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि पर निर्भर है।

आजादी के 30 वर्ष से भी अधिक समय और कुछेक पाँच-वर्षीय योजनाओं के बाद भी हम आज भी कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति का दावा नहीं कर सकते। जनसंख्या में वृद्धि और बढ़ती कीमतों ने सारी प्रगति को बराबर कर दिया है। अंग्रेजों के औपनिवेशिक हितों ने भारतीय उद्योगों को चौपट कर दिया और साथ ही इन्हें एसी सीमा में बँद कर दिया जिससे व अतिविकास नहीं कर सका। इन स्थितियों का असर हमारी कृषि पर भी पड़ा और इसमें कोई शक नहीं है। आश्चर्य तो इस बात पर है कि आजादी के बाद भी इन बंधनों को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गयी। यूरोप का इतिहास हमें बताता है कि जब तक कृषि के क्षेत्र में अतिरिक्त पैदावार नहीं होती तब तक यह पैदावार औद्योगीकरण के लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृषि का ठोस आधार बनाय बिना खाद्य पदार्थों और बुनियादी वस्त्रों माल की आपूर्ति भी संभव नहीं है। तबों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को गुरा करने के लिए ये अतिरिक्त हैं।

प्रथम पंच-वर्षीय योजना के दौरान सिंचाई रूप में महत्त्व प्राप्त हो गया था कि सिंचाई और बिजली के साथ साथ कृषि को मरोड़ता दी जायेगी। कृषि की ओर से आपत्तियाँ बरतना संभव नहीं था, क्योंकि अतिरिक्त खाद्य पदार्थों और वस्त्रों माल के अभाव में औद्योगीकरण का प्रयास धराशायी हो जाता।

इसलिए प्रथम पंच-वर्षीय योजना में कृषि का ही रास्ता अपनाया गया।

टुपि एवं ग्रामीण विकास के लिए 35 करोड़ 40 लाख रुपये निर्धारित किए गए। कुल बजट का यह 14.9 प्रतिशत हिस्सा था। गिराई और रिजनी के लिए 64 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी जो बजट का 27.2 प्रतिशत थी।

दूसरी योजना में हमारी प्राथमिकता बढ़ाने ली, जबकि गंगा बरन का उचित समय नहीं था। टुपि और ग्रामीण विकास के लिए कुल बजट का 11.8 प्रतिशत तथा उत्पादन एवं ग्रामीण विकास के लिए 18.5 प्रतिशत अनु निर्धारित किया गया।

दूसरी योजना में टुपि के क्षेत्र में उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया गया। तीसरी योजना में भी उत्पादन पूरा निर्धारित लक्ष्य में (जो 10 में 10.5 करोड़ टन था) बहुत कम रहा।

1952-53 में 1964-65 तक के चार वर्षों के आँकड़ों से—जिनका मंत्रालय ने प्रकाशित किया है—पता चलता है कि टुपि के क्षेत्र में सम्मिलित वार्षिक विकास दर केवल 3 प्रतिशत रही। इसमें से नीचे-पाए भूमि में 1.21 प्रतिशत तथा उत्पादन में 1.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई। शुरू की तीसरी पंच-वर्षीय योजनाओं के दौरान टुपि उत्पादन के पंचम्वरूप कुल लाभ 2.1 प्रतिशत हुआ। प्रथम योजना के दौरान इसमें 1.2 प्रतिशत और द्वितीय योजना के दौरान 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तीसरी योजना के समाप्त होने तक इसमें 2 प्रतिशत का ह्रास हो चुका था।

चौथी और पाँचवी योजना के अंत तक यह लाभ रखा नहीं जा सका। इसका कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा घोषी गयी पुरानी साम्राज्यवादी भूमि प्रणाली में कोई तबलीली नहीं की गयी और इस कारण को हमेशा नजरअंदाज किया गया। जब तक यह पूरा नहीं होता तब तक न तो उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है और न किसानों की दशा में कोई सुधार किया जा सकता है।

जब हम अर्थ-व्यवस्था के कृषीय क्षेत्र में उत्पादकता और विकास की बात करते हैं तो निश्चय ही हम किसानों के जीवन स्तर को सही अर्थों में बेहतर बनाने की दुर्ग्राह्य अवधारणा को भी इसमें शामिल करते हैं। इस अवधारणा को वे लोग नहीं पसंद करते जो आज भी दमन की पुरानी परंपरा निभान में पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं।

प्रोफेसर कोमाम्बी ने ठीक ही कहा है कि यदि आधुनिक भारत के गाँवों की यात्रा की जाये तो उन वस्तुओं—मसलन पुराने उपकरण, बलगाड़ियाँ, शोषण और भूख से पीड़ित चेहरे—को देखा जा सकता है जो ईसा पूर्व 150 और 200 ईसवी के कुषाण साम्राज्य की मूर्तियों की शक्ति से अभर हो चुकी हैं।

किसानों से लिया जा चुका है कि हमारे किसान आज भी उमी तरह की

जिंदगी गुजार रह है। निश्चय ही सामाजिक अत्याय का यह एक जबरदस्त उदाहरण है।

आजादी से पूर्व और आजादी के बाद भी कांग्रेस शासन न किसानों की पीड़ा पर कई बार विचार किया। दिसम्बर 1947 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष न कुमारप्पा समिति का गठन किया जिसका काम भूमि-सुधार के मामला की छानबीन करना था और इस सर्वेक्षण के बाद उसे उपयुक्त सिफारिशें करनी थी। जुलाई 1949 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में जब तक पूरी तरह सुधार नहीं किया जाता तब तक समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। ऐसा करने के लिए त्रिचोलिया का खत्म करना होगा और जमीन की किसानों के हाथ में सौंपना होगा। इसके साथ ही विधवाया, नाबालिगों और अपंग व्यक्तियों को छोड़कर अब किसी भी मामले में भूमि पट्टेदारी की प्रथा पर रोक लगानी होगी। इसमें यह भी उल्लेख किया था कि भूमिहीन किसानों को कुछ अधिकार भी देन होंगे। एक सुझाव दिया गया था कि जा लाग लगातार छह चप से किसी जमीन का जोत-बो रह हा उन्हें अपने आप ही उस जमीन पर स्वामित्व कायम करने का अधिकार मिल जाना चाहिए। अब मामला में जा असली मालिक है वे यदि चाहें तो जमीन पर अपने दावे फिर कायम कर सकते हैं वरतें इसे व एक निर्धारित समय में पूरा कर लें। रिपोर्ट में अनेक ऐतिहासिक उपायों को भी शामिल किया गया था ताकि जमींदार लोग कोई अनुचित लाभ न उठा लें

(क) जिन लोगों ने यूनतम परिमाण में भी शारीरिक श्रम किया है और खेत जोतने-बोने में खुद भी हिस्सा लिया है उन्हें वास्तविक किसान माना जायगा।

(ख) जमीन के असली मालिक अपने दावे जमीन के उसी हिस्से पर कर सकते हैं जो उनकी जोत को आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बना सके।

रिपोर्ट में उल्लिखित अब सिफारिशों में कहा गया था कि किसान वास्तविक किसानों का एरिया लैंड ट्रिव्यूनल द्वारा निर्धारित मूल्य पर जमीन खरीदने का अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही जमीन से बदलल किये जाने के मिलसिले को भी फौरन रोक दिया जाना चाहिए। सभी वर्गों के किसानों को ऊँच करा तथा गर-कानूनी मांगों से हिफाजत देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। करो का निर्धारण नकद के रूप में किया जाना चाहिए और इसके लिए उचित दरें भी तय कर देनी चाहिए। अब में खेत की एक सीमा निश्चित करने की भी सिफारिश की गयी थी जिसे अधिकतम उस जमीन के क्षेत्रफल का तीन गुना माना गया था जो आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ जमीन थी।

इन सिफारिशों में तीन तरह की गतिविधियों का शामिल किया गया था—
यक्तिगत खेती, सहकारी खेती और सरकारी खेती। कृषि योग्य बनायी गयी

भूमि के बारे मे प्रस्तुत सुझावा म कहा गया था कि ऐसे मामला म भूमिहीन मजदूरों का बड़े पैत प्रान का अवसर दिया जाना चाहिए भल ही इस काम म लाभ हा या नुकसान ।

इस सुधार समिति न एक ऐसी कृषि प्रणाली के बारे मे सोचा था जिसम किसानों का नतत्व हागा । अपेक्षाकृत बड़ी लाभोमुख पृष्ठभूमि के मुकाबले मालिका और मजदूरों के बीच सत्रय कायम करने की कोई वांशिश नहा की गयी ।

य सिफारिशें ज्यों की-या बनी रही—इका अस्तित्व कागजा तक ही सीमित रहा । प्रथम पंच वर्षीय योजना म सरकारी तौर पर तयार की गयी भूमि नीति न समिति द्वारा पेश किय गय मुझावा के मुख्य पहलुओं की उपशा की । इसका एक पहलू हम किसानों की परिभाषा म देख सकत ह जिसम कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रम का एक यूनितम परिमाण संच करता है, उसी अवस्था मे उसे किसान माना जा सकता है । जहा तक जमीन की मिल्कि पत का सवाल है इसन लेती करन वाले मालिका और लेनी न करन वाले मालिका के बीच एक फक दिखाया । लेती के काम म लग किसान जमीन पर सीधे अपना दावा प्रस्तुत कर सकते थ, जबकि खुद लेती न करन वाले मानिक केवल उसी जमीन पर दावा कर सकत थ जो किसानों की आर्थिक जोता की सीमा को पार करती थी । यदि इस सिद्धांत पर भ्रमल किया गया होता ता जमीन स बेदखल किय जान की अनेक घटनाएँ राकी जा सकती थी ।

इस आवश्यक अतर को कभी निर्धारित नहीं किया गया । जमीन पर फिर से दावे करने के मामल म उन लागों का बरीयता दी गयी जा खुद लेती नहीं करते थ और इसके फलस्वरूप संचमुच मेहनत करन वाले वग को पूरी तरह या आंशिक रूप से बेदखल कर लिया गया । यथाथ म बेदखली की घटनाएँ बढ़नी गयी और जमीन की मिल्किगत बंद लागों के हाथा म सिमटती चली गयी । मेहनतकश किसानों का पक्ष लेने वाले मामले बहुत कम थे । इसका नतीजा यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों म दा चर्चों के बीच का अतर लगातार बढ़ना गया और आर्थिक विषमता भी बढ़नी गयी ।

काशनकारी से सम्बन्धित नीतिया भी समान रही थी । सुधार समिति विधवाओं नाबालिगों और अपंग लोगों के मामला को छोड़कर पट्ट पर जमीन दन के मिलाप की । फिर भी पहली पंच वर्षीय योजना म जो अग्रवन विधान था उसन संपूचे मामलों को उन लोगों व पक्ष म कर दिया जिहों जमीन को पट्टे पर लेन की नीति अपनायी थी ।

ऐम लागों को इज्जतदार कहा जाता था । साथ ही उन लोगों व बीच कोई भद नहीं किया गया जो छाटी जान के मालिक थे और अनिश्चित आय व लिए

महाराज जात भ तथा जा रही जात के मातिव य मरु मरु मरु मरु ।
 य । इस बारण जमीदार-बास्तनपर सम्बन्ध धरु मरु मरु मरु ।
 जारी रहा ।

वर्द्ध मामला में वरा की अधिकतम दर अभी भी फसल के पंचम प्रतिशत हिस्से से अधिक है। उड़ीसा में एक कानून के जरिए यह घोषित किया गया है कि फसल का 25 प्रतिशत हिस्सा ही कर के रूप में लिया जाएगा, फिर भी पुराना कानून अपनी पूरी ताकत के साथ बरकरार है और किसानों में फसल का 50 प्रतिशत हिस्सा चमूला जाता है। अपनी योजनाओं के दौरान हमने देखा कि पंजाब में जमीन में वेदखन किये जान की घटनाएँ अभी भी तेजी पर हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में बगदारा को किसान न किसी चहाने जमीन से छेड़ दिया जाता है। 1948-51 के बीच सरक्षित वास्तविकारों की संख्या 17 लाख 7 घटकर 13.6 लाख हो गयी। इनके अधीन जा भूमि थी यह भी घटकर 18 प्रतिशत रह गयी। आंध्र प्रदेश सरकार की एक जांच समिति ने पता किया कि 1951 और 1955 के बीच सरक्षित वास्तविकारों और उनकी जात में कमी आयी और यह प्रमश 50 तथा 59 प्रतिशत हो गयी। समिति के अनुसार कानून में निहित खामी ने इसे अप्रभावकारी बना दिया।

इसका नतीजा यह हुआ कि अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं के तयार किये जाने के बावजूद खेतिहर मजदूरों की संख्या हज़ारों में बढ़ती जा रही है। जन गणना रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये गए हैं वे पहली बार सही जानकारी का सामन ला सके हैं।

1951 में खेतिहर मजदूरों की संख्या 7,15,766 थी। 1961 में यह संख्या 3,15,19,411 और 1979 में 4,73,04,808 तक पहुँच गयी। दूसरी तरफ किसानों की संख्या 9,95,28,313 थी। 1971 में यह घटकर 7,87,06,896 हो गयी। कहना न होगा कि इस अवधि के दौरान मजदूरों की हानत में और भी गिरावट आयी।

1951-52 और 1956-57 की पहली और दूसरी खेतिहर मजदूर जांच समिति की रिपोर्टों में काफी व्यौरा मिलता है। खेतिहर मजदूरों की शिनायत करने के लिए दोनों समितियाँ न अलग अलग पमान का इस्तेमाल किया है। पहली समिति के अनुसार जिन लोगों ने खेती में अपने श्रम का आधा हिस्सा दिया था उन्हें खेतिहर मजदूर कहा गया। दूसरी समिति का कहना था कि जिन लोगों ने अपनी कुल आय का आधा हिस्सा खेती-बाड़ी के लिए अर्जित किया था उन्हें खेतिहर मजदूर कहा जाना चाहिए। इसमें काफी भ्रम फैला।

इसका कारण यह था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि हर बार फसल की कटाई के समय किसी मजदूर को काम मिल ही जायेगा और वह भी प्रतिदिन। यदि उसे काम मिल भी जाता है तो मजदूरी के रूप में जो भी राशि उसे प्राप्त होगी वह बड़े किसानों और जोतारों की मर्जी पर निर्भर है (वैश्व, 'यूनितेड वलन के सम्बन्ध में एक कानून था')। फलस्वरूप अपना जीवन-यापन के

लिए मजदूरों को दूसरे काम भी करन पड़त थ (शायद गहरी खेती में भीय माना पड़ती थी)। इसलिए खेती-बाड़ी में लगाय गये समय में आधार पर अथवा इसके जरिए अर्जित आम के आधार पर खेतिहर मजदूरों की सख्या निर्धारित करना उचित होगा।

इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1951-52 और 1956-57 के बीच मजदूरों की मजदूरी का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ। पुरुष-मजदूरों की सख्या में 13 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई और महिला-मजदूरों की सख्या में यह वृद्धि 51 प्रतिशत रही। महिला-मजदूरों की सख्या में अपेक्षाकृत ज्यादा वृद्धि हुई, क्योंकि इनका दी जाने वाली मजदूरी कम थी। दूसरी तरफ, पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी की दरों में क्रमशः 12 प्रतिशत और 13 प्रतिशत की कमी आयी। फलस्वरूप प्रत्येक परिवार की आय में 22 प्रतिशत की कमी हो गयी वरन् वज्र में 31.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वज्र से लदे परिवारों की संख्या 44.5 प्रतिशत में बढ़कर 63.9 प्रतिशत हो गयी।

1950-51 में वज्र की कुल राशि 80 करोड़ रुपये थी जो 1956-57 में बढ़कर 143 करोड़ रुपये हो गयी। 1960-61 में दूसरी योजना के अंत में यह राशि 160 करोड़ रुपये तक पहुँच गयी।

भूमि सुधार के प्रारम्भिक क्रम के रूप में प्रथम योजना के दौरान ही 1951 में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1954 आते जाते विचौलिया का अस्तित्व कम से-कम कागज पत्रों में समाप्त हो गया। इसके पीछे मुख्य इरादा सरकार और किसानों के बीच लेन-देन की सीधी व्यवस्था कायम करना था। कानून में इतनी सुविधा थी कि भूतपूर्व जमींदारों का अस्तित्व भी बना रहा। पहले की ही तरह वह वज्र जारी रहे। केवल नाम बदल गये। जिन्हें पहले सामंती भू-स्वामी और जमींदार के नाम से जाना जाता था वह अब भूतपूर्व जमींदार, जेतदार और धनी किसान बन गये थे लेकिन छोट किसानों, बगदारा और खेतिहर मजदूरों की पुरानी पहचान बनी रही। धनी किसानों के शक्तिशाली गुट का 'भारतीय कुलक' भी कहा जा सकता है। आंकड़ा से पता चलना है कि पहली योजना के दौरान अनेक छोटे किसानों और बगदारों को उनकी जमीन से वंचित किया गया और यह जमाय का ऐसा उन्मूलन हुआ जो सालों के इतिहास में कभी देखने का नहीं मिला।

पश्चिम बंगाल की स्थिति पर विचार करें। जमींदारी प्रथा के तत्पश्चात् ही वे बंगाली बगदारा और बटाईदारों को जो 25 प्रतिशत से 46 प्रतिशत जमीन प्राप्त थे, किसी तरह का फायदा नहीं हुआ। असली फायदा भू-स्वामी को मिला जो खेती-बाड़ी करने वाली जावादी में अल्प संख्या की रिपोर्ट में 1956 में बगदारा के हितों की रक्षा करने के प्रयास विफल हो गये।

कानून बना जिसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 25 एकर अधिक जमीन नहीं होगी। यह कानून एक्ट में शामिल हो गया, क्योंकि वडे भूस्वामियों ने अलग-अलग नामों से जमीन पर अपना कब्जा बाँट रखा। वगदारा ने महसूस किया कि सरकार और कानून में उनकी रक्षा नहीं हो सकती। दरअसल, हर समय जमीन से बेदमल कराया जाना का गतरा तलवार की तरह मर पर लटक रहा था। बित्तन परिवारों का बेदमल कराया गया यह अब इतिहास का विषय बन गया है।

इस प्रकार जमीन से बेदमल किये जाने के बाद छोटे किसानों और वगदारा ने स्वतंत्र भारत में खेतिहर मजदूरों की रतार में शामिल होना बेहतर समझा। दूसरी तरफ वे मालिकों और महाजनों से ज्यादा बड़ा लेन लग ताकि उनकी और उनके परिवारों का खर्च चल सके। उनकी आय और बज्र की मात्रा के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है।

(2)

1967-68 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ग्रामीण जावादी का 70 प्रतिशत हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे रहता है। इस रेखा से नीचे और सबसे नीचे खेतिहर मजदूर आते हैं। येशव यह कहा जा सकता है कि वे जीवित थे क्योंकि वे उस समय तक मर नहीं सके थे। 1972 में बौकड़ा जिले के दो गाँवों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि खेतिहर मजदूरों की दैनिक मजदूरी 37 पैसे थी। तत्कालीन श्रम आयुक्त ने इस पर टिप्पणी की थी कि ये लोग कैसे जीवित हैं, यह एक चमत्कार है। अब सभी राज्यों में भी मजदूरों के मामले में यह बात सच थी।

आजादी के बाद सरकार ने खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी के सिलसिले में अनेक कानून बनाए। लेकिन इन कानूनों को कभी भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। कानून में उनके खामियों के कारण या तो इन्हें अप्रभावकारी बना दिया गया था या भूस्वामियों के हाथ में ये हथियार बन रहे गये थे। कांगड़ पर मजदूरों में कुछ वृद्धि दिखाई दी थी, लेकिन इस वृद्धि को कीमतों में हड़बड़ों ने नाकाम कर दिया। जिन मजदूरों ने न्यूनतम मजदूरी की मांग की लेकर आंदोलन किया उन्हें काम से हटा दिया गया। भूस्वामियों ने कम मजदूरी पर बाहर से बुलाकर मजदूरों का भर्ती किया। स्थानीय और बाहरी मजदूरों में कई बार संघर्ष हुए लेकिन इसमें भूस्वामियों को किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ा। इस तरह के अनुभवों से मजदूरों ने निश्चय होकर अपने घर-बार छोड़ दिया और दूसरी जगह चले गये।

खेतिहर मजदूरों के लिए काम मिलने की भी कोई गारंटी नहीं है। औसतन 15 प्रतिशत मजदूरों के लिए काम नहीं मिलता। जिन्हें मिलता भी है वे साल

के बारहा महीन काम पर नहीं होते। खेता म जो काम करते हैं उन्हें वष म लगभग 150 दिन मजदूरी सहित काम मिलता है। सिंचाई वाले खेता म काम करन वाले मजदूरों को केवल वान और काटन के समय ही काम मिलता है। साल के बाकी दिना म व बेरोजगार रहते हैं। 1950-51 म इस तरह के मजदूरों की दैनिक मजदूरी 207 पैसे थी। 1956-57 म 230 पैसे और 1964-65 म 297 पैसे हो गयी। सेंट्रल लेबर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट म बताया गया है कि पिछले 14 वर्षों म खेतिहर मजदूरों की आय म 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन वास्तविक आय म पांच प्रतिशत की गिरावट आयी।

कृषि का सहारा लेना पड़ता है। छोटे किसानों और बगदारा की जरूरतों म थोड़ा-सा फर्क है। उनकी कृषिदारी मुख्य रूप से इसलिए बढ़ती है क्योंकि उन्हें उपकरण बीज और रासायनिक खाद खरीदने पड़ते हैं। इसके अलावा फसल तैयार होने तक खान के लिए भी उन्हें खर्च करना पड़ता है जिसके प्रति धनी या गरीब एस सामाजिक दायित्व को भी पूरा करना पड़ता है। उनके प्रति धनी या गरीब कोई भी उपेक्षा नहीं करते सक्ता। एक बार लिया गया कृषि पीढ़ी दर-पीढ़ी सर पर चढ़ा रहता है। उनकी निरक्षरता का फायदा महाजन लोग उठाते हैं और कृषि रूप म लिखी गयी राशि को बढ़ाते रहते हैं। कृषि की राशि का चाहे जितना भी हिस्सा चुकता किया जाये मूल राशि म कोई कमी नहीं आती और चरवृद्धि व्याज की दर से इसम वृद्धि होती रहती है।

भारत सरकार की 1961-62 की रिपोर्ट म बताया गया है कि खेती करने वाले प्रत्येक दस परिवारों म से छह परिवार कृषि से ग्रस्त थे। कृषि के रूप म ली गयी कुल राशि म से सहकारी संस्थाओं और यको न आठ प्रतिशत से भी कम दिया था। शेष राशि गांव के सुदखोर महाजनो से प्राप्त हुई थी। रिजर्व बैंक आफ इंडिया न अपनी रिपोर्ट म बताया है कि ग्रामीण कृषिदारी म 1961 और 1971 के बीच दुगुनी वृद्धि हुई। इसकी आधी राशि खेती बाड़ी के लिए किसानों द्वारा ली गयी थी। इस कृषि के चालीस प्रतिशत हिस्से पर व्याज की दर 12.5 प्रतिशत थी। रिपोर्ट म कहा गया है कि कुल ऋण 3,752 करोड़ रुपये था। यह राशि नकद के रूप म दी गयी थी और इसके बदले 96 करोड़ मूल्य के सामान (उधार लिये गये थे)। इसम से खेतिहर परिवारों ने (श्रमिक वर्ग का 72 प्रतिशत हिस्सा) 3,374 करोड़ रुपये लिये जो कुल राशि का 88 प्रतिशत था। खेतिहर मजदूरों ने 181 करोड़ रुपये या 4.7 प्रतिशत की राशि ली। कारीगरों ने 54 करोड़ या 1.4 प्रतिशत और गैर कृषिको न 239 करोड़ या 6.2 प्रतिशत की राशि ली।

1975-76 म लगभग सभी राज्यों म तरह-तरीका से ग्रामीण कृषि

रिपोर्ट से यह भी पता चला कि कज की आध से अधिक राशि महाजन द्वारा दी गयी थी जबकि वहाँ सरकारी समितियाँ और ग्रामीण बका की सुविधाएँ उपलब्ध थी। सरकार की सारी एजेंसियाँ महाजनो के जाल से गरीब किसानों और मजदूरों की रक्षा करने में विफल हुई थी। यह विफलता अवश्यभावी थी, क्योंकि जिन लोगों को इसका शिकार बनाया गया था वे गरीब, असहाय और असंगठित थे। सरकारी कानूनान न केवल सुविधा सम्पन्न लोगों की ही मदद की। आसान दरा पर थोड़े समय के लिए कज देने वाली ऋण समितियाँ के कार्यों की जाच करें तो पता चलेगा कि इन पर धनी महाजनो, धनी किसान और उनके एजेंटों का ही नियन्त्रण है। इसमें उपलब्ध राशि के अपनी जोत बढान के लिए खच करत हैं अथवा व्याज की ऊँची दरा पर (24 से 120 प्रतिशत प्रतिवष) इसी राशि को वे गरीब किसानों का दे देते हैं।

राज्य व्यापार निगम की कहानी भी उतनी ही दुखद है। इस निगम की स्थापना का उद्देश्य यह घोषित किया गया था कि इसके

जरिए मुनाफाखोर विचौलिया को हटा दिया जायेगा। लेकिन इसमें उही तत्वा की मदद से काम शुरू किया। ऐसे लोग पहले की तुलना में और भी ज्यादा प्रभावशाली बन गये और किसानों पर अपना दमन तेज करने का उह और भी ज्यादा अवसर मिल गया। इन सबके बावजूद सरकारी कागज पत्रों में यही दिखाया गया कि हर योजना के दौरान गरीब किसानों और मजदूरों को लाभ मिलता रहा है और महाजनों से उनकी रक्षा की जाती रही है। यह सारा इतना एक धोखा था और जनता को ठगने का नया तरीका था।

घटनाओं का नाम कुछ ऐसा रहा कि छोटे किसान अनिवाय रूप से भयंकर कज से दबते चले गये और अपनी पुश्तैनी जमीनों से बदखल कर दिये जाने का बाद वे खेतिहर मजदूर बन गये। साथ ही इसी प्रक्रिया के जरिए इन मजदूरों का बंधुआ मजदूर बना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि गुलामी कराना गैर कानूनी है लेकिन व्यवहार में इसे हमेशा झुठलाया गया है। जब तक भूमि प्रणाली में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक गुलामी की प्रथा को रोका नहीं जा सकता, भले ही इसके लिए हजारों कानून क्यों न बना दिये जायें। यह दिन ब दिन बढ़ती ही जायेगी।

एक सवाल पडा हो सकता है कि जमींदार और महाजन इतने गरीब लोगों को कज क्यों देते हैं जो पसा चुकता न कर सकें? जहाँ तक छोटे किसानों की बात है उनके पास जमानत के रूप में दान के लिए कुछ तो है लेकिन साधारण मजदूरों के पास क्या है? यह बड़ी सहज बात है। कज के कारण छोटा किसान महाजन के लिए अपनी जमीन गँवा देता है और इसी तरह खेतिहर मजदूर बहुत मामूली महनताने पर श्रम करने के लिए बाध्य होता है। मजदूर के पास और कोई चारा

ही नहीं है। महाजन चाहता है कि य लोग उसस ज्यादा म ज्यादा बज लें क्याकि उस पता है कि इसकी अदायगी नहीं हो पायेगी और इस प्रकार उस मजदूर को अनक पीडिया इसकी गुलामी कर सकेंगी। यही वास्तविकता है। सतिहर मजदूर को इसी प्रकार गुलाम बनाया गया है और व पूरे वष महाजन के खता पर या तो बिना किसी मजदूरी के या बड़ी मामूली मजदूरी लेकर दिन रात काम करत रहत है। उह यह भी अधिकार नहीं होना कि वे किसी और व्यक्ति के खेत पर काम कर सक। अनक स्थाना म यह भी देखा गया है कि व अपन मालिक की इजाजत व बगर शादी भी नहीं कर सकत, भले ही उनक अदर शादी करन की क्षमता क्या न हा। रगपुर (अब वगलादेश म है) की एक प्रचलित प्रथा का उदाहरण दिया जा सकता है। यहा वधुआ मजदूरों के पास इतने पस नहा हो पात थे कि व अपन लिए शादी का इतजाम कर सकें। शरीर की इस प्राकृतिक भूख व तबाव स उनके काम पर असर पडता था जिसे मालिका न महसूस किया। इस समस्या व समाधान के लिए हिंदू और मुसलमान—दोनों जोतदारा न एक तरीका ढूढ निकाला। इन वधुआ मजदूरों को कुछ औरतों दी गयी और कहा गया कि इन औरतों का काम उनके लिए खाना बनाना है। सच्चाई यह थी कि उन्हें मजदूरों की काम-वासना की तपति के लिए भेजा गया था। तिकडमी मालिका के दिमाग न कसा अनुठा समाधान ढूढ निकाला।

लिय गय ऋण व बार म यदि विस्तृत जानकारी इकट्ठी की जाय तो पता चलगा कि इनका परिमाण क्या है? लगभग 58.1 प्रतिशत वधुआ मजदूरों पर प्रति व्यक्ति ऋण 500 रुपये 19.9 प्रतिशत पर 500 स 900 रुपये क बीच और लगभग 21 प्रतिशत पर 900 रुपये स अधिक का ऋण है। निश्चय ही निहार इसका एक ठोस उदाहरण है। यहाँ बज की राशि काफी कम है। आकड इस प्रकार ह

वधुआ मजदूरों का प्रतिशत

45.8

86.5

प्रति व्यक्ति ऋण

र० 100 या कम

र० 300 या कम

वगुन इसकी उलटी स्थिति का भी उल्लेख किया जा सकता है। राजस्थान व मगरी लाग म 12.9 प्रतिशत व ऊपर 500 रुपये स कम और 58.8 प्रतिशत व ऊपर 900 रुपये स अधिक का बज है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन दोनों राज्यों व मजदूरों का अलग अलग जीवन-स्तर है और उनकी सामाजिक अन त्रियाएँ भी भिन्न हैं। महाजन लाग तारी धरती पर एक नियम का गमान रूप से पालन करत है और वह यह कि व कभी एक बार म ही पयाप्न रकम बज व रूप म नहीं देत।

हमेशा कर्जदार की जरूरत से कम राशि ही कर्ज के रूप में दी जाती है। कर्ज मिलन तक उन्हें महाजनो के यहाँ कई-कई चक्कर लगान पड़ते हैं और इसका मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है।

बधुआ मजदूरों की यह कष्ट भरी कहानी बाजार से बेहद कम मजदूरी पर महाजना के जगला और खेतों में काम करने के साथ ही खत्म नहीं हो जाती। शुरू में लिया गया ऋण लगातार बढ़ता जाता है। मूल राशि पर और बढ़ती हुई मूल राशि पर व्याज की राशि भी बढ़ती जाती है।

व्याज की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। बिहार के कमिया लोग व्याज के रूप में चालीस प्रतिशत चुकता करते हैं। कई मामला में यह दर सौ प्रतिशत से भी अधिक है। कर्नाटक के बधुआ लोगों से भी चालीस प्रतिशत से ज्यादा व्याज वसूला जाता है। खेतिहर मजदूर कुछ भी चुकता नहीं कर पाते—वे कर्ज की अदायगी के बारे में तो सोच भी नहीं सकते।

मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में एक अजीब और दिलचस्प बात देखने में आती है। वहाँ के महाजन व्याज नहीं लेते। ऐसा सोचा जा सकता है कि वे बड़े मानवीय हैं लेकिन बात ऐसी नहीं है। दरअसल मजदूर एक ऐसी अवस्था में पहुँच गये हैं जहाँ व्याज वसूलना एक अनावश्यक श्रम होगा। शुरू में उहाँ जहाँ जो कर्ज ले लिया है और उस पर जो सूद इकट्ठा होता जा रहा है उसके कारण हमेशा के लिए वहाँ बंध गये हैं।

इस तरह के ऋणा के लेने का कारण विशुद्ध रूप से अपना जीवन यापन करना रहा है। कर्ज का 47.5 प्रतिशत हिस्सा खान के लिए और 33.7 प्रतिशत हिस्सा शादी-व्याह, दाह सस्कार आदि जैसे सामाजिक कार्यों के लिए खर्च हुआ। यह आरोप कि मजदूर लोग फिजूलखर्च करते हैं, एकदम गलत है और आँकड़ों से यह साबित हो सकता है।

यदि यह कहा जाये कि ग्रामीण कर्जदारी ने बधुआ मजदूरों को जन्म दिया, तो गलत नहीं होगा। सरकारी आँकड़ों के अनुसार खेतिहर मजदूरों का 4.2 प्रतिशत बधुआ मजदूर हैं। गर सरकारी आँकड़े इस 5 प्रतिशत अथवा इससे अधिक बताते हैं। जाठ विभिन्न राज्यों का जलम अलग-अलग व्यौरा यहाँ प्रस्तुत है

राज्य	बधुआ मजदूरों की संख्या	कुल खेतिहर मजदूरों का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	3 25,000	4.96
बिहार	1,11,000	1.70
गुजरात	1 71,000	9.40
कर्नाटक	1,93 000	7.60
मध्य प्रदेश	5 00 000	11.80

54 भारत म बहुआ मजदूर

राज्य	बहुआ मजदूरों की सख्या	कुल खेतिहर मजदूरों का प्रति
राजस्थान	67 000	9 40
तमिलनाडु	2 50 000	6 00
उत्तर प्रदेश	5,50 000	10 60

आकडा से पता चलता है कि आठ राज्या म बहुआ मजदूरों की सख्या 21 7 लाख है जो 3 कराड 70 लाख खेतिहर मजदूरों का 6 1 प्रतिशत है। यदि उडीसा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के सही आकड प्राप्त हों तो इस सख्या मे और भी वडि होगी।

अब हम उन सात जिला का ब्योरा देत हैं जहा सबसे ज्यादा बहुआ मजदूर हैं

क्षेत्र

उत्तरी तमिलनाडु
तलगाना (आंध्र प्रदेश)

गुजरात / महाराष्ट्र

मध्य गुजरात
महाकौशल (मध्य प्रदेश)

उत्तर प्रदेश (पश्चिम)

उत्तर प्रदेश (उत्तर) और
बिहार

निम्नावित जिलों को बहुआ मजदूर प्रदेश का उपनाम दिया जा सकता है

जिला

उत्तरी और दक्षिण आरकाट
नालगाडा करीमनगर
शिमोगा
अहमदनगर
बेडोना
सनना सादान बस्तर
पन्ना
देवरिया

जिले

धमपुरी उत्तरी और दक्षिणी आरकाट चिालपुट
हैदराबाद जादिलाबाद मेडक, करीमनगर, महबूब
नगर नालगाडा, निजामाबाद वारंगल।
वलसद, सूरत बिदरोदा, गुजरात, पंचमहल,
नासिक धूल जलगाव (महाराष्ट्र)।
महेशपना, सुरिंदरनगर, काठियावाड।
रायगड, रतलाम विदिशा गुना मुरना सागर
छनहार सतना रीवा, सदल सरगुजा,
बस्तर (विणप रूप से उल्लेखनीय)।
बिजनौर मुजफ्फरनगर भरठ मुरादाबाद, बरली
खीरी सीतापुर।

बाहा देवरिया, चम्पारण और सागन।

राज्य

तमिलनाडु
आंध्र प्रदेश
कर्नाटक
महाराष्ट्र
गुजरात
मध्य प्रदेश
बिहार
उत्तर प्रदेश

इन क्षेत्रों म जो बधुआ मजदूर हैं उनम से 78 प्रतिशत कज लेन के कारण बधुआ बनाये गये हैं और केवल 13 प्रतिशत—जो किसी खास जाति के हैं और कई दूसरा काम नहीं पा सकते—अपन मालिकों की जमीन कई पीढ़ियों से वास्तविक रूप म जोत रहे हैं।

इस गुलामी की समय सीमा पर ध्यान देना अत्यंत होगा। सामान्य तौर पर 60 प्रतिशत बधुआ मजदूर अनिश्चित काल के लिए बधुआ बनाये गये हैं। इस गुलामी से मुक्ति उनके मालिकों की दया पर ही निर्भर है। लगभग 10 प्रतिशत मजदूर दस वर्ष की उम्र से गुलाम हैं। इसके अलावा दस प्रतिशत मजदूर बीस वर्ष से भी अधिक समय से गुलाम हैं। महज चार वर्ष पूर्व 56 प्रतिशत मजदूरों का बधुआ बनाया गया है और अन्य 33 प्रतिशत मजदूरों ने अभी दो वर्ष पूर्व ही अपनी जायदादी खोयी है।

इसका ध्यान दें कि बधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए 1975 म एक अध्यादेश जारी किया गया।

किसी भी कानून अथवा अध्यादेश ने बधुआ मजदूरों की मदद नहीं की। व अभी भी महाजनो के जाल म हैं। अपनी जाय से वे कज चुकता नहीं कर सकते। इनम से लगभग तीस प्रतिशत लोग प्रति माह दस रुपये से कम पैसे कमाते हैं, हालांकि भुगतान की जाने वाली औसत राशि की दर 35 रुपये है।

तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के मजदूर काफी भाग्यशाली हैं—तमिलनाडु म पचास प्रतिशत मजदूरों की आय प्रति माह चालीस रुपये से थोड़ी ज्यादा है और यही स्थिति उत्तर प्रदेश के तीस प्रतिशत मजदूरों की है। कर्नाटक और बिहार म क्रमशः 39 प्रतिशत और 40 प्रतिशत मजदूरों की इनकी ही आय है।

यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नकद और फसल के रूप म उन्हें वस्तुतः क्या मिलता है। अनाज के रूप म जो कुछ मिलता है उसका मूल्यांकन यदि रुपये के सदर्भ में करें तो थोड़ा कहना ही बेहतर होगा।

हमन पहले ही बताया है कि हरवाह के नाम से शात गारखपुर और देवरिया के बधुआ मजदूरों का खुराक के रूप म क्या मिलता है। वे गाय और भैंस के गोबर से निकले अनाज को घाकर खाते हैं। भूख की ज्वाला को शांत करने के लिए ही वे ऐसा करते हैं और इस आहार का भी मजदूरी मान ली जाती है। इसके अलावा यदि उन्हें नकद के रूप म कुछ दिया जाता है तो उसमें से व्याज काट लिया जाता है। इस प्रकार वास्तव म उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और यही वजह है कि अतीत म लिये गये ऋण का कभी भुगतान नहीं हो पाता। उल्टे मालिक के खाते म यह बढ़ता ही जाता है। इसी तरह पीढ़ी दर-पीढ़ी गुलामी की जंजीर बसती जाती है। परीक्षणों से पता चलता है कि बधुआ मजदूरों की

कुल आवादी का 83 प्रतिशत हिस्सा उन लोग का है जिनकी आयु चालीस वष से कम है। इसका जलावा 53.6 प्रतिशत लोग तीस वष से और 21 प्रतिशत लोग बीस वष से कम उम्र के हैं। मालिक उन लोग को पसंद नहीं करते जिनकी उम्र चालीस वष से अधिक है क्योंकि कठार श्रम करने की क्षमता उनमें नहीं रहती। ऐसे मामला में उनके बेटों को हल जोतने के लिए लगाया जाता है और उन्हें काम से छुट्टी दे दी जाती है। गुलामी का बोझ जो एक लंबी अवधि से बाप के कंधा पर था अब बेटे के कंधा पर आ जाता है और कुछ समय बाद उसके बेटे के कंधा पर और इस प्रकार यह सिलसिला जारी रहता है।

बधुआ मजदूर परिवारों में से 75 प्रतिशत परिवारों में कम से कम दूरे परिवार का एक सदस्य मालिक के यहां गुलामी करता है। बिहार में 62 प्रतिशत परिवारों में से परिवार के चार सदस्यों को मालिक के यहां गुलामी करनी पड़ती है और यह संभव इसलिए कि वहां प्रचलित प्रथा के अनुसार उक्त परिवार के सभी सदस्य बंधक हैं। अन्य राज्यों में केवल उसी व्यक्ति का बधुआ रखा जाता है जिसने छंद कर लिया हो।

(3)

दरअसल बधुआ मजदूरों में सबसे ज्यादा सख्या हरिजन और आदिवासियों की है जो लगभग 84 प्रतिशत हैं। मालिकों में केवल 8.4 प्रतिशत हरिजन और आदिवासी हैं तथा 84.2 प्रतिशत सवर्ण हिंदू हैं। जाति और वर्ग हमेशा से ही दमन के हथियार रहे हैं। यदि वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करें तो इसका पता चल जायगा। मालिकों में हरिजन और आदिवासी अल्पमत में हैं पर य भी बधुआ मजदूर रखते हैं क्योंकि जमीन की मिल्कियत हाने से उनके वर्ण चरित्र में भी तबदीली आ जाती है। मिसाल के तौर पर, आंध्र प्रदेश के हरिजन—जिन्हें मलस कहा जाता है—बधुआ मजदूर रखते हैं तथा मुडिया और गाड नाम के बस्तर के आदिवासी अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बधुआ मजदूर रखना जरूरी समझते हैं। थोड़ा सुविधा सम्पन्न होते ही सवर्ण हिंदुओं द्वारा अपनाए जाने वाले बंधा कारण है कि अधिकांश बधुआ मजदूर हरिजन अथवा आदिवासी हैं? इसका लिए विस्तार से विश्लेषण करना जरूरी है।

1961 की जनगणना से पता चलता है कि बेटी-बाढ़ी से संबंधित लोग म. प्र. में 53 प्रतिशत ऐसे थे जो सचमुच बेटी करते थे। इनमें से हरिजन और आदिवासियों की संख्या क्रमशः 38 प्रतिशत और 68 प्रतिशत थी। खेतिहर मजदूरों में—जो कुल संख्या का 17 प्रतिशत थे—38 प्रतिशत हरिजन और 20 प्रतिशत आदिवासी थे।

आदिवासियों के लिए भती का काम काफी कठिन लगा। आदिवासी

किसानों में से 10 प्रतिशत से अधिक खानाबदोश ज़िंदगी बिताते हैं। वे ज़मीन के किसी खास हिस्से पर नहीं बस सकते। उनके रहने वाले अनेक इलाकों की वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है क्योंकि कभी इन इलाकों का सर्वेक्षण ही नहीं किया गया। यहाँ शायद ही सिंचाई की व्यवस्था कभी की गयी हो। जैसी ज़मीन उनके पास है वसी ज़मीन खेती करने के लिए एकदम अनुपयुक्त है। इनको अधिक-से अधिक चरागाह बनाया जा सकता है जबकि इन पर कुछ फल के पौधे लगाये जा सकते हैं। साथ ही, इस ज़मीन का क्षेत्रफल भी इतना कम है कि इसमें इतना उत्पादन नहीं हो सकता जिसमें पूरे परिवार का खर्च चल सके। इसका नतीजा यह होता है कि आदिवासियों को महाजन से ऋण लेना पड़ता है। अगर आदिवासियों के हिस्से की ज़मीन उपजाऊ हुई तो धनी किसान और जोतदार कोई न कोई तिकड़म करके उसे उनसे हड़पने में कामयाब हो जाते हैं। अगर ऐसा करने के लिए उन्हें हरिजन और आदिवासियों के परिवारों का ज़िंदा जलाना पड़े तो इसमें भी वे नहीं हिचकते।

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद में ज़मीन जबरन जोतने मजदूरी, बंधुआ मजदूर तथा ऋणदारी के सवाल पर 1974-77 में हुए संघर्षों के आकड़े प्रस्तुत किये हैं जो अपन-आप में हत्या, बलात्कार और अत्याचार की एक दुखद गाथा हैं।

इनका विवरण इस प्रकार है

राज्य	वर्ष	घटनाओं की संख्या
उत्तर प्रदेश	1974	805
	1975	329
	1976	591
मध्य प्रदेश	1974	59
	1975	76
	1976	323
आन्ध्र प्रदेश	1974	44
	1975	15
	1976	48
गुजरात	1974	2
	1975	7
	1976	14
कर्नाटक	1974	6
	1975	22
	1976	20

राज्य	वर्ष	घटनाओं की संख्या
महाराष्ट्र	1974	
	1975	17
	1976	10
	1974	9
	1975	8
बिहार	1976	5
		7

हरिजन और आदिवासी इसलिए बज्र लेते हैं क्योंकि उनकी जोतें अलवारि है और यह इसलिए क्योंकि उनके पास खेती के उपकरण नहीं हैं। बबढ़ता जाता है और अंत में वे अपने खेतों से हाथ धोकर वधुआ मजदूर बन जाते हैं। आदिवासियों की समस्या और भी गंभीर है। विभिन्न राज्यों में किये गये सर्वेक्षणों से विस्तृत जानकारी मिलती है। 1975 में पश्चिम बंगाल में आदिवासियों का मामला से संबंधित विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 1,602 आदिवासी परिवारों में से 1,080 परिवार बज्र के बोझ से दबे हैं। इनमें वे बाशिंदे हैं जिन्हें भोटिया, लेप्चा, लोडा, महाली, मोचा, मुडा, उराव, राबा और सथाल के नाम से जाना जाता है। ये जनजातियाँ पश्चिम बंगाल में रहने वाले आदिवासियों की कुल आबादी का 94 प्रतिशत हैं। जिन 1,080 परिवारों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनमें से 755 परिवारों में (69.9 प्रतिशत) नकद के रूप में 150 परिवारों ने (13.88 प्रतिशत) अनाज के रूप में और 177 परिवारों ने (18.2 प्रतिशत) नकद और फसल दोनों रूप में बज्र लिया था। ये ऋण गरीब आदिवासी महाजनों से लिये गये जो हर तिकड़म के तरीके तयार रखते हैं।

बिजय मुडा 24 परगना जिले में सदशखाली पुलिस थाने के अंतर्गत मणिपुर नामक गांव में रहता है। उसने 133 एकड़ जमीन गिरवी रखकर 400 रुपये बज्र लिया। इसके साथ ही यह भी कि 6 वर्ष तक खेत की सारी फसल महाजन लेगा। दार्जिलिंग जिले में पेडांग पुलिस थाने के अंतर्गत सक्वान गांव के तनजिंग भोटिया ने अपनी 0.15 एकड़ जमीन के बदले में 800 रुपये का बज्र लिया था। शत यह भी कि इस रकम का बज्र लेने वह अपनी फसल देकर बज्र उतार देगा और जब तक बज्र उतर नहीं जाता फसल की कीमत 15 रुपये प्रति मन के हिसाब से तय रहेगी। जाहिर है कि यह बज्र कभी चुकता नहीं हो सकता, क्योंकि बज्रगार को अपना खर्च चलाने के लिए और भी बज्र लेना पड़ेगा।

बिशाखापत्तनम में आदिवासियों के एक गांव में किये गये सर्वेक्षण में पता चला कि उस गांव के 61.24 प्रतिशत परिवार बज्र का बोझ में दबे हैं। भूमिहीन

परिवारों की हालत और भी खराब थी, क्योंकि कुल कज का 63 63 प्रतिशत जकेले उन पर था। किसानों में जिनके पास अपेक्षाकृत ज्यादा जमीन थी, उन पर कम कज था। प्रत्येक परिवार पर कज की राशि औसतन 308 रुपये थी। लगभग 72 22 प्रतिशत परिवारों पर 400 रुपये से कम का कज था।

शेष परिवारों ने 400 से 1200 रुपये के बीच कज लिये थे।

कजदारों में 67 4 प्रतिशत आदिवासियों ने अपने परिवार का खर्च चलाने और कुछ जय जूरते पूरी करने के लिए ही कज लिया था। आंध्र प्रदेश में भद्रागिरि में 1971 72 में किये गये एक सर्वेक्षण में बताया गया कि 57 प्रतिशत आदिवासी कज में डूबे थे। प्रत्येक परिवार पर औसतन 157 रुपये का ऋण था और 93 प्रतिशत ऋण बैलो तथा खेती बाड़ी से सम्बंधित जय सामान की खरीद के वास्ते लिये गये थे। कुल ऋण का केवल 6 4 प्रतिशत जीवन-यापन के खर्चों में शामिल हुआ था। श्रीकाकुलम के अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में 1972 में 677 परिवारों ने 1 14 लाख रुपये का ऋण लिया था।

1973 में बिहार में पलामू जिले में हरिजनो और आदिवासियों की कज-दारी के बारे में एक सर्वेक्षण किया गया। उन्होंने जीवन यापन के खर्च तथा पारिवारिक जरूरतों का पूरा करने के लिए कज लिया था। जनधिकृत रसीदों से उन ऋणों का प्रमाण मिलता है जिनके लिए 75 प्रतिशत ब्याज वसूला गया। लगभग 26 92 प्रतिशत परिवारों पर ऋण का बोझ था।

तमिलनाडु की स्थिति और भी खराब थी। कोली पहाड़ी के आदिवासियों ने जो ऋण लिया था वह प्रत्येक परिवार पर औसतन 2000 रुपये के बराबर था। कज लिये गये प्रत्येक 100 रुपये पर ब्याज 60 से लेकर 100 रुपये तक वसूला गया।

उड़ीसा में नारायण पटना ब्लॉक में 55 प्रतिशत आदिवासी अपने परिवार का भरण-यापन कराने के लिए कजदार बन हुए हैं। गजाम जिले के परलखमुडी सब डिवीजन में 66 7 प्रतिशत आदिवासी कज के बोझ से दबे हैं। इनमें से 91 4 प्रतिशत लोगों ने नकद के रूप में ऋण लिया है। ऋण लेने के कई कारण हैं—37 8 प्रतिशत मामलों में खेती बाड़ी के खर्च के लिए कज लिया गया है, 41 प्रतिशत खाद्यान्न के लिए और शेष पिछला कज चुकता कराने के लिए।

मध्य प्रदेश में एक इलाके में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों में से 52 5 प्रतिशत ऐसे हैं जो कज से लदे हैं। रतलाम जिले में ऐसे लोगों की तादाद 82 9 प्रतिशत है। प्रत्येक परिवार पर औसतन 357 रुपये का ऋण है। 34 5 प्रतिशत घरेलू जरूरतों के लिए, 12 2 प्रतिशत सामाजिक और धार्मिक कारणों से और 43 6 प्रतिशत खेती में काम के खर्च के लिए ऋण लिया गया।

हरादून के निवृत्त जौनसार गाँव क्षेत्र में आदिवासियों की एक बहुत बड़ी

सख्या कजदार क रूप म है। यहाँ भी पारिवारिक जम्हरत ही, ऋण लेन का मुख्य कारण बनी। ऋणग्रस्तता क परिमाण का सही सही पता कभी नहा लगाया जा सकता क्याकि इस मसले पर महाजन लोग वामोश है।

इस निष्कर्ष पर आसानी स पहुँचा जा सकता है कि जिन मामला का उत्तेज किया गया है उनम भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। चूकि कजदार उस कज क बल पर अपना जीवन-यापन ही कर पात है इसलिए जाग जितना रहन क लिए भी उह कज का ही सहारा लेना पडता है और इस प्रकार कज का बाय बढ़ता ही जाता है। यहाँ तक कि जिनक पास थोड़ी-बहुत जमीन भी है उह भी खेती करन के लिए कज का ही सहारा लेना पडता है। इससे क केवल व्याज चुपता क पाते है। इसलिए मूल राशि बढ़ती ही रहती है। जिस राशि पर वे हस्ताक्षर करत है (दरअसल अँगूठ का निशान लगात है) और जो राशि वे पात है उसम काफी अंतर हाता है।

ऋणग्रस्तता को समाप्त करन क बार म सरकार द्वारा पारित किय गय कानून किसी काम क साबित नहीं हुए। उह कभी लागू नहीं किया गया। इसको अमल म लाना तब तक संभव नहीं है जब तक वित्तप के रूप म किसी एस स्रोत की स्थापना न की जाय जहा स किसानों की जरूरत पूरी की जा सकें। कवा और सहकारी समितिया पर महाजना का ही नियंत्रण है। उनका विरोध करके किसान उनकी नाराजगी मोल लेना नहीं चाहता। यदि वे महाजना का नाराज करत ह तो बाग कज लेन का रास्ता बन हो जाता है। इस प्रकार कजदार अपन गले म पडा डलवान म खुद ही मददगार हा जाता है।

श्रीकानुलम विशाखापत्तनम और पश्चिमी तथा पूर्वी गोणवरी जिला म जहाँ अनुसूचित जातिक लोग रहते हैं वधुआ मजदूरी की प्रथा काफी प्रचलित है। इन इलाका म मद्रास ऋण वधन समाप्ति विनियमन कानून 1940 लागू है। यह कानून सभी समझौता को रद्द करता है सिवाय उन समझौता के जो मजदूरों और जोतदारा तथा महाजना के बीच प्रत्यक्ष रूप से सम्पन्न है और जिस जोतदार तथा महाजन अधिकारिया के समक्ष पेश करत हैं। अधिकारिया को इस बात की गारंटी की जरूरत होती है कि कोई समझौता घर कानूनी नहीं है। यह समझौता अधिकतम एक बरष के लिए होना चाहिए और इस पर व्याज की दर 6 5 प्रतिशत स ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहना न होगा कि इस कानून को कभी लागू नहीं किया गया।

1973 म बिहार म चनपुर लातेहर गडवा मनिका और रसका म एक दल ने सर्वेक्षण किया। दल को पता चला कि इन इलाका म वधुआ मजदूर बनाय रखन की प्रथा काफी प्रचलित है। इस सर्वेक्षण की कुछ खास बातें इस प्रकार हैं

(क) सर्वेक्षण दल ने जिन 58 वधुआ मजदूरों से भेंट की उनमें से 34 हरिजन और 24 आदिवासी थे। कुछ मामलों में सम्पूर्ण परिवार वधुआ मजदूर था।

(ख) प्रत्येक परिवार पर 22 रुपये से 350 रुपये तक का कर्ज था। यह ऋण जवानों के कारणों अथवा गैर सरकारी रसीदा के एवज में लिये गये थे। मूल राशि और व्याज की राशि के चुकता होने तक कर्जदारों को वधुआ मजदूर के रूप में काम करना था। यदि कर्ज देने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो उसके बेटे उसके स्थान पर काम करेगा।

(ग) कर्ज लेने का कारण परिवार के लिए भोजन, शादी विवाह के खर्च, इलाज और पिछले कर्ज के भुगतान की व्यवस्था करना था।

(घ) कर्ज देने वाले सूदखोर महाजन और जमींदार ब्राह्मण तथा बनिया जाति के थे—उनमें से कुछ दुकानदार भी थे।

(च) राज्य सरकार का श्रम विभाग न्यूनतम वेतन कानून को लागू करने में विफल रहा।

(छ) वधुआ मजदूरों को पाव भर पिसा मक्का नाश्ते में और जाधा किलो ग्राम मोटा चावल दोपहर के खान में मिलता था। मजदूरों के बीबी बच्चा को भी—यदि वह काम करते थे तो—इतना ही या इससे कम मिलता था।

(ज) एक गांव में सुनने में आया कि मजदूरों को खान के अलावा वेतन के रूप में प्रतिमाह 15 रुपये प्राप्त होते थे। इस राशि को कर्ज का भुगतान मानकर काट लिया गया। व्याज की दर 100 प्रतिशत थी।

1973 में बिहार सरकार के आदिवासी कल्याण विभाग ने भड़रिया और राका ब्लॉक के 27 गांवों का एक सर्वेक्षण किया। विभाग के अधिकारियों ने 232 लोगों से बातचीत की जिनमें 98 आदिवासी 11 हरिजन, 23 निचली जाति के लोग और एक मुसलमान थे। यह देखा गया कि अधिकांश वधुआ मजदूर आदिवासी थे जिन्हें करवा के नाम में जाना जाता है। हरिजनों में अधिकांश वधुआ मजदूर भुइया थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि

(क) कर्ज का भुगतान होने से पहले ही यदि कर्जदार की मृत्यु हो जाती थी तो वधुआ मजदूर के रूप में उसके बेटे को काम करना पड़ता था। उन लोगों में इस तरह के 18 उदाहरण मौजूद थे।

(ख) पारिवारिक जरूरतों ने कर्ज लेने के लिए मजबूर किया। 59 प्रतिशत कर्ज भोजन के लिए, 14 प्रतिशत शादी के लिए, 11 प्रतिशत शादी-ब्याह के लिए और शेष चिकित्सा तथा दाह संस्कार के वास्तव में लिये गये थे।

(ग) वधुआ मजदूरों के मालिक विभिन्न जातियों और सम्प्रदायों के थे 23 प्रतिशत भुइया, 10 प्रतिशत अहीर, 12 प्रतिशत राजपूत और शेष विभिन्न वर्गों के थे। कमिया (वधुआ मजदूरों) लोगों का पता था कि उनके मालिक जा

खरीदने में मदद पहुँचायी। यह इतिहास में उम्र एक बहुत छोटे बाल में सम्मिलित हुआ, जो बहुत पुरानी बात नहीं है।

इतिहास की यह धारा मुगल शासन काल में टीक्स-क्लेक्टरों से लेकर ब्रिटिश शासन काल में जमींदारों के समय तक बिना किसी शोरगुल के बहती रही। सल्तनत काल में मुसलमान जमींदार अस्तित्व में आए। उन तिन सत्ता के कमांडरों का चुनाव निरपवाद रूप से कुलीन घरानों में किया जाता था और इन कमांडरों का अपनी सेना का पच गुना ही उठाना पड़ता था। इस काम में मर्रा पहुँचाने के लिए उन्हें जागीरें तक दी जाती थी। इन इलाकों से वसूल कर व भी भी शाही खजाने में नहीं गए। इस कमांडर की जरूरत के मुताबिक खर्च किया जाता था। समय के साथ जागीर प्रणाली में मुसलमानों का आधिपत्य में जमींदारी प्रणाली का रूप ले लिया।

भारतीय ढंग की सामंती प्रणाली का इन तथ्यों से मदद मिली कि यहाँ के गांव असम्बद्ध और आत्मनिर्भर थे। बाद में तुर्कों अपना जीर मुगलों ने भारत के सभी क्षेत्रीय सामंत सरदारों को एकजुट करके कृत्रिम रूप से केंद्र शासन सामंतवाद थोपने की कोशिश की। इस हस्तक्षेप के बावजूद स्थानीय सामंतवाद का अस्तित्व बना रहा।

गांव के पुराने रीति रिवाजों के अनुसार सभी सामंत सरदार उच्च जातियों के थे। तुर्कों और मुगल सम्राटों की लूटपाट जब भी असहनीय होती थी, जनता स्थानीय सामंत सरदारों के यहाँ शरण लेती थी। उन्हें जनता के समर्थन से शक्ति मिलती थी और इससे वे इतने मजबूत हो जाते थे कि वे जिल्लों में शासन कर रहे सम्राटों की शक्ति की भी अवहेलना कर देते थे। मुगल शासन-काल के अंतिम दिनों में जब केन्द्रीय सत्ता के क्षीण होने के कारण जमींदारों और जागीरदारों की ताकत बढ़ी तो ग्राम समाज लड़खड़ा लगे। अब इन सरदारों ने दमन का सिलसिला शुरू किया जो प्लासी के युद्ध के बाद चरम सीमा पर पहुँच गया।

अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के जड़ जमाने के बाद इनमें से अनेक सामंत सरदारों का अस्तित्व समाप्त हो गया। उनकी बड़ी बड़ी जागीर नीलाम हो गयी जिन्हें उन लोगों ने खरीदा जो शहरों में रहते थे और निहंवाणिज्य व्यापार में अंग्रेजों से होड़ लेने में असफलता मिली थी। लोग ऊँची जाति के थे और उनके पास नकद राशि काफी थी जिसे जमीन खरीदने के अलावा और किसी काम में वे नहीं खर्च कर पाते थे। आज भी जो अधूरे जागजात हैं उनसे इसी तथ्य की पुष्टि होती है।

इनमें से एक हिस्सा उन लोगों का था जिन्होंने व्यापार और वाणिज्य के लिए काफी पूँजी इकट्ठी कर ली थी। उन्हें मध्य वर्ग का कहा जाता था। दूसरे व लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। इनमें से पहले वर्ग के

खास काना म रहत थ ताकि निचली जाति क लागे स इनका शरीर न छू जाय। इस सदी के पूवाद्ध म इनम स जनक न गैर-ब्राह्मण रयता थ हाय जमीन बच दी—य लाग ब्राह्मण ता नही थ पर ऊँची जाति क थ। सम्प्रति अधिकांश भू-स्वामी खेती न करन वाल ब्राह्मण और कायस्थ थे। जाटा, अहीरा और म भी एक मामूली सा प्रतिभात एस लोगे का है जिनक पास अपनी जर्म सामान्य तौर पर अधिकांश जमीन ऊँची जाति क लोगे के पास है जा ि नही है।

पश्चिम बंगाल म जमींदारी गरीदन म जिन लोगे न अपनी सम्पत्ति लग व थे—द्वारकानाथ टगोर पड़कापाडा क राजा सिंहा, हथकाला और रा वागान क दत्ता लोग रामदुलाल डे साहा और मल्लिक लोग। य सभी ऊँ जाति क थे।

दूसरी ओर गरीब बिगान खतिहर मजदूर और बधुजा मजदूर—य सभी निम्न हिंदू जातिया आदिवासिया और मुस्लिम समुदाया के हैं। मुसलमाना का प्रभाव-क्षय ज्यादा होन क कारण अंग्रजा द्वारा भाडे पर खरीदे गय इतिहासकारा ने उनके विद्रोहो को साम्प्रदायिक रंग दे दिया और इन विद्रोहा के महत्व को कम करन की कोशिश की। यह अब सभी जानते हैं कि सयासी विद्रोह (यह नाम मजनूशाह या मजनू फकीर के मतत्व के कारण पडा) और तोतूमीर के नेतत्व वाले बहावी विद्राह को साम्प्रदायिकता का जामा पहना दिया गया ताकि उनका महत्व कम किया जा सके।

इस प्रकार भारत का सामाजिक आयिक इतिहास बताता है कि यहाँ जा ही बग हो गया। चूकि 'जाति शब्द का एक महत्व है इसलिए हम लाग कि व्यक्ति की हैसियत का अंदाजा उसकी जाति से लगाते हैं। हम देखत ह कि ऊँच जाति क जोतदार गरीब हरिजन मजदूर या किसानो को जिंदा जलान म तनिक भी नही हिचकिचाते हैं। फिर भी वे ऊँची जाति क गरीब किसानो पर इम तरह का अत्याचार कभी नही करते। इसी वजह से हम यह कह रहे हैं कि जाति और वग एक दूसरे के पर्याय हैं।

कानून की खामियो को ही इस बात का थय है कि तथाकथित आजादी के बाद जमींदारा का नाम तो खत्म हो गया पर उनका नियंत्रण पहले जसा ही बना रहा। जहाँ तक जमींदारी और बिचौलिये की प्रथा के समाप्त हाने की बात है य जमूलन सही है पर कई मामलो म, मिसाल के तौर पर सुद कुश्ता रयतो जाति के मामलो म पुराना सिलसिला जारी रहा। इसक अलावा कानून को लागू करन स पूव जमादारा को काफी समय भी दे दिया गया ताकि क अपन रिश्तेदारी और कमचारियो के नाम गर कानूनी ढँग से जमीन हस्तांतरित कर सकें। जमा दारा न यही किया भी।

उह अनक वगदारा और रैयत। स अपनी जमीन खाली करान का अवसर भी मिल गया। कृषि के बारे में राष्ट्रीय आयोग द्वारा 1976 में प्रकाशित रिपोर्ट में ऐसे अनक उदाहरण देखने को मिलते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जमींदारों के खत्म होने से लगभग दो करोड़ किसानों का राज्य के साथ सम्पर्क कायम किया जा सका है। इसी के साथ लाखों रैयत और वगदार खेतिहर मजदूर बन गए। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कानून होने के बावजूद जमीन अभी भी मुठ्ठी भर धनी किसानों के हाथ में है और पिछले कुछ दशकों में स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आयोग के अनुसार इसका प्रमाण नेशनल सैम्पल सर्वे द्वारा एकत्र किया गया जाठवें चक्र का आकड़ा है जिससे पता चलता है कि 2 64 प्रतिशत परिवारों के पास 30 एकड़ जमीन है जो निर्धारित सीमा से 28 05 प्रतिशत ज्यादा है। 1970 71 की कृषि-गणना से पता चलता है कि भू-स्वामियों की संख्या कुल आबादी का महज 4 प्रतिशत है जिनके पास कुल जमीन का 30 5 प्रतिशत है।

इस मामले पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। 1951 की जोतो के बारे में कृषि श्रम जांच नमूना सर्वेक्षण से पता चलता है कि 5 एकड़ या इससे कम की जोत—जो कुल जोत का 15 5 प्रतिशत है—59 1 प्रतिशत परिवारों के पास था। इनके अलावा 25 एकड़ या इससे अधिक की जोत, जो कुल जोत का 34 4 प्रतिशत है, 5 6 प्रतिशत परिवारों के पास था। राष्ट्रीय प्रतिचयन सर्वेक्षण (नेशनल सैम्पल सर्वे) द्वारा जून 1960 से जून 1961 के बीच किये गए अध्ययन से पता चलता है कि जमीन का 56 2 प्रतिशत भाग 10 प्रतिशत परिवारों के हाथ में था। रिपोर्ट के अनुसार

30 प्रतिशत परिवारों के पास	0 1 प्रतिशत जमीन
अगले 10 प्रतिशत ,	0 6 ,
अगले 10 प्रतिशत ,,	2 1 ,,
50 प्रतिशत का कुल योग	2 8 ,
अगले 10 प्रतिशत के पास	4 7 ,,
अगले 10 प्रतिशत ,,	6 9 ,,
अगले 10 प्रतिशत ,	11 0 ,
30 प्रतिशत का कुल योग	22 6 ,,

इस प्रकार खेतीबाड़ी में लगे 80 प्रतिशत लोगों के पास कुल जमीन का केवल 25 4 प्रतिशत था। बाढ़ के 10 प्रतिशत लोगों के पास 18 4 प्रतिशत जमीन थी और अंतिम 10 प्रतिशत के पास कुल जमीन का 56 2 प्रतिशत था।

यह अंतिम 10 प्रतिशत ही देश में सामंतवाद के अलम्बरदार है और ये ही वे लोग हैं जिन्हें पंच-वर्षीय योजनाओं में दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता मिलती रही है। यही वे लोग हैं जिनको कानून का सहारा प्राप्त है। आश्चर्य नहीं कि खेती के क्षेत्र में इतनी विपत्ति देखी जाती है। अमीर और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन और ज्यादा गरीब हो रहा है।

भूतपूर्व खाद्यमंत्री श्री जगजीवनराम ने बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन में कहा था कि 42 प्रतिशत खेतिहर परिवार के पास केवल एक एकड़ जमीन है जबकि 22 प्रतिशत परिवार के पास एकदम जमीन नहीं है। लगभग 3-4 प्रतिशत परिवारों के पास अपार जमीन है और सरकारी मदद से वे अपना प्रभाव बढ़ाते हैं तथा अपनी नीतियों का पूरी ताकत के साथ लागू करते हैं। निधनतम क्षेत्र की उपेक्षा की जा सकती है। उनका कोई अस्तित्व नहीं है।

इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार इस व्यवस्था को ज़िंदा रखने के लिए हर कोशिश करती है और जातन वाले को जमीन सौंपने की बात चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करके जान वाले नारे के अलावा और कुछ भी नहीं है। बिना किसी लागू लपेट के यह कहा जा सकता है कि सरकारी भूमि नीति महज एक जमींदार बुजुर्ग नीति है जो सामंतवाद का बरकरार रखने के लिए उन्मुख है। बुजुर्ग वगैरह इतना सावधान है कि हर बार विद्रोह छिड़ने पर वह जमीन दान देना और जमीन का बंदोबस्त करने की बात को सावजनिक चर्चा में ला देता है। तेलंगाना सशस्त्र संघ और तेलंगाणा आंदोलन (वंगाल) तथा वल्लि विद्रोह (महाराष्ट्र) के बाद ऐसा देखने में आया है। इन विद्रोहों के बाद जब भी चुनाव नजदीक आया है बुजुर्ग वगैरह इस तरह का धोखा खड़ा किया है। यही बारीक बातें हैं। केरल में भी पहली कम्युनिस्ट सरकार ने किसानों को धान में रखने के लिए सरकारी खेती पर बड़ी लम्बी चौड़ी बहसों की थीं। नवलवाड़ी और श्रीकाकुलम में विद्रोह की लपटें उठने के बाद तथा पूर्वी गोदावरी और मुशहरी तराई में जमीन का छीनने की घटनाओं के बाद सत्तारूढ़ दल ने भूमि सुधार और किसानों को जमीन देने की आवश्यकता पर खूब बड़बड़ कर बातें शुरू कीं।

किसानों के धान पर बड़ा आकषक दिखने वाला मलहम लगाने के लिए सरकार ने भूमि हदबंदी कानून पारित किया जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि किसी व्यक्ति या परिवार के पास अधिकतम कितनी जमीन हो सकती है। साथ ही कानून के निर्माताओं ने बागों, सेव बागानों, चरागाहों, निवासस्थानों आदि की जमीन के लिए गुंजाइश छोड़ दी ताकि बड़े जोतदार इस कानून से प्रभावित न हों। और इस प्रकार जोतदारों को फायदा हुआ। नीचे दी गयी तालिका में विभिन्न राज्यों के लिए भूमि की अधिकतम सीमा का पता चलता है।

राज्य	अधिकतम सीमा (हेक्टेयर में)
आंध्र प्रदेश	4 05 से 21 85
असम	6 94
बिहार	6 07 से 18 21
गुजरात	4 05 से 21 85
हरियाणा	7 25 से 21 85
हिमाचल प्रदेश	4 04 से 12 14
जम्मू-कश्मीर	3 68 से 7 77
कर्नाटक	4 05 से 21 85
केरल	4 86 से 7 07
मध्य प्रदेश	4 05 से 21 85
उड़ीसा	4 05 से 18 71
पंजाब	7 00 से 21 80
राजस्थान	7 25 से 21 85
तमिलनाडु	4 86 से 24 28
त्रिपुरा	4 00 से 12 00
उत्तर प्रदेश	7 30 से 18 25
पश्चिम बंगाल	5 00 से 7 00

यथाथ में ये कानूनी बर्दिशों के कार हैं। कोयम्बटूर में एक भूतपूर्व कांग्रेस मंत्री कानूनी स्वीकृति के साथ 847 एकड़ जमीन रख सकता था और रख रहा है। इस जिले के जानुर चक्करह के पास 1,190 एकड़ जमीन है, पट्टा नायडू नामक सज्जन न मंदुर के पहाड़ी क्षेत्र में 3,000 एकड़ जमीन खरीदी। उसने अपनी जमीन से सभी रयता को खदेड़ दिया है और इस समय 6,000 एकड़ जमीन का मालिक है। बिहार में दरभंगा नरेश के पास ओसाई के लिए जो जमीन है उसका ही क्षेत्रफल 600 एकड़ है—जय खेतों की तो बात ही अलग है। बाघगया और घघनली में दो महता के पास क्रमशः 10,000 और 3,000 एकड़ जमीन है।

सभी राज्यों में जमींदारों, जोतदारों और यहां तक कि उद्योगपतियों में बराबर कानून का उल्लंघन किया है और हजारों एकड़ जमीन के मालिक बन बैठे हैं। सर्वेक्षण से पता चलेगा कि अंग्रेजों के जमाने के राजा और जमींदार आज भी पहले की ही तरह बड़ी बड़ी जोता के मालिक हैं—इतना ही नहीं, उनकी जोता में निरंतर वृद्धि भी होती जा रही है।

छोटे और लगभग छोटे किसान लगातार अपनी जातों से हाथ धोत जा रहे हैं और मजदूर बनत जा रहे हैं और बारी प्रांगी से बधुआ मजदूर की श्रेणी में

पहुँचत जा रह है, अपन मालिका के सेता म अपन का घटा रहे हैं ताकि मालिका का मुनाफा हा सब ।

दरअसल जिह बधुआ मजदूरा की जरूरत हाती है, व उह रपत हैं । यहाँ प्रस्तुत उदाहरण स बिहार का एक चित्र उभरता है

जमीन की जोत (व्यक्तिगत या पारिवारिक स्वामित्व)	बधुआ मजदूरों की संख्या
10 एक्ड	2 29
10 20 एक्ड	1 83
20 50 एक्ड	2 92
50 100 एक्ड	5 40
100 एक्ड और इसम अधिक	16 20

सर्वेक्षणा से पता चलता है कि 84 प्रतिशत बधुआ मजदूर हरिजन तथा आदिवासी हैं और 84 2 प्रतिशत भू-स्वामी सवण हिन्दू है । इस सिक्का का दूसरा पहलू यह है कि 11 6 प्रतिशत बधुआ मजदूर सवण हिन्दू हैं तथा 8 4 प्रतिशत भू स्वामी हरिजन एवं आदिवासी है । बधुआ मजदूरा म आदिवासिया की मख्या हरिजना स ज्यादा है । बधुआ मजदूरों का अस्तित्व उन इलाका म ग्रासतौर से ध्यान आकर्षित करता है जहाँ सवण महाजना एवं जोतदारा तथा गरीब अभाग हरिजना एवं आदिवासिया के बीच असमानता भयंकर सीमा तक है ।

आंध्र प्रदेश म माला सम्प्रदाय के कुछ हरिजा भू-स्वामियों के पास जो बधुआ मजदूर ह व भी हरिजन है लेकिन उनके बीच ऊँच नीचे का जा फरक है उसम व थोड़े नीचे पडत है । वस्तर म बधुआ मजदूरा के मालिक सुरिया और गाड ह जो खुद ही आदिवासी ह ।

देखा जाता है कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आन्ध्रामियों के वग चरित्र म भी तबदीली जाती है और व अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा म वद्धि की उम्मीद म सवण हिन्दुआ के तौर-तरीकों की नकल करने लगते ह ।

बधुआ मजदूरा को रखन के मामले म मालिका की स्थिति इस प्रकार है लगभग 50 प्रतिशत के पास एक बधुआ मजदूर है 41 प्रतिशत के पास 2 से 4 और 3 प्रतिशत के पास 10 स अधिक है । बर्नाटक म 12 8 प्रतिशत के पास 10 स ज्यादा मजदूर है । जसाकि हमन पहले कहा है इस स्थिति म कमी या वद्धि जमीन की स्थिति के अनुसार होती है । जलग अलग राज्या म बधुआ मजदूरों के मालिका की स्थिति पर एक नजर डालनी हागी

भारत भर मे

आदिवासी	5 9 प्रतिशत
हरिजन	2 4 „
निचली जाति	23 7 „
सवण हिन्दू	60 5 ,
मुसलमान	4 0 ,
ईसाई	0 1 „
अन्य	3 4 ,

आंध्र प्रदेश

आदिवासी	11 4 प्रतिशत
हरिजन	1 3 ,
निचली जाति	6 3 „
सवण हिन्दू	78 5 „
अन्य	2 5 „

बिहार

आदिवासी	6 5 प्रतिशत
निचली जाति	46 5 „
सवण हिन्दू	42 0 „
मुसलमान	5 0 „

गुजरात

आदिवासी	2 7 प्रतिशत
हरिजन	4 3 ,
निचली जाति	7 0 „
सवण हिन्दू	74 8 „
मुसलमान	11 2 „

कर्नाटक

आदिवासी	2 7 प्रतिशत
हरिजन	2 1 „
निचली जाति	2 7 „
सवण हिन्दू	82 1 ,

मुसलमान	1 4 प्रतिशत
अ-य	9 0 "

मध्य प्रदेश

आदिवासी	20 8 प्रतिशत
हरिजन	4 7 "
निचली जाति	12 9 "
सवर्ण हिन्दू	57 9 "
अ-य	3 7 ,

राजस्थान

आदिवासी	22 8 प्रतिशत
हरिजन	5 5
निचली जाति	11 7 ,
सवर्ण हिन्दू	55 9 "
मुसलमान	2 1 "
अ-य	2 0 ,

तमिलनाडु

हरिजन	2 8 प्रतिशत
निचली जाति	84 4 "
सवर्ण हिन्दू	0 5 "
मुसलमान	11 2 "
ईसाई	1 1 "

उत्तर प्रदेश

हरिजन	0 2 प्रतिशत
निचली जाति	19 3 "
सवर्ण हिन्दू	76 4 "
मुसलमान	3 4 "
अ-य	0 7 "

तमिलनाडु का छोड़कर शेष सभी राज्यों में बधुआ मजदूरों के मालिकों के रूप में सवर्ण हिन्दुओं का ही पहला स्थान है। बधुआ मजदूरों में हरिजनों और

आदिवासियों की ही सख्या सबसे ज्यादा है। यद्यपि पहले उल्लेख किया जा चुका है, फिर भी हम अखिल-भारत पैमाने पर बधुआ मजदूरों की सख्या का एक बार और उल्लेख करते हैं

आदिवासी	18 3 प्रतिशत
हरिजन	66 0 ,
निचली जाति	8 9 ,,
मुसलमान	2 7
ईसाई	0 4 ,,
सवण हिन्दू	2 7 ,,
अन्य	1 0 ,

जाति और वर्ग के भेद के कारण आदिवासी और हरिजन ही सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हैं। मालिकों की इस बात में दिलचस्पी रहती है कि उन्हें रुपये उधार देकर फँसा लिया जाये। चूँकि उन्हें निम्नतम श्रेणी में रखा गया है इसलिए उन पर ऊँची जाति के लोगों का मनावज्ञानिक रूप से दबदबा पहले से ही बना रहता है, जो इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। उनकी स्थिति इतनी असुरक्षित रहती है कि उन्हें और उनके बच्चों को कोई भी थोड़े से पैसे देकर गुलाम बना सकता है।

उनके अंदर एक महान गुण यह है कि वे कभी अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करते।

(3)

यह देखा गया है कि सभी मामलों में महाजनो की कोशिश यह रहती है कि वे खेतिहर मजदूरों को बर्बर बना लें और अपने चंगुल में फँसा लें। खेतिहर मजदूर अपनी लाचारी के कारण ही कर्ज लेते हैं। वे मुख्यतः हरिजन और आदिवासी होते हैं। उनके पास जमानत देने के लिए कुछ भी नहीं होता, फिर भी वे कर्ज लेते हैं। महाजनो को पता है कि इस ऋण की अदायगी कभी नहीं हो पायगी और यह चक्रवर्द्धि व्याज की दर से दिनोदिन बढ़ता जाता है—कभी-कभी तो व्याज की दर 100 प्रतिशत होती है।

आमतौर पर खेतिहर मजदूरों के पास जमीन नहीं होती और आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं होता जिससे वे कर्ज का भुगतान कर सकें। इसके अलावा वे अपढ़ होते हैं, इसलिए महाजन वे खात में उनके नाम जो भी रकम लिखी होती है उसे उन्हें मानना पड़ता है। लेकिन इन सारी बातों का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं।

महाजनों का मकसद पूरा होता है। उन्हें मस्ते दर पर मजदूर चाहिए जो वे

पा जाते हैं क्योंकि वधुआ मजदूर का लगभग कुछ नहीं दना पड़ता है। उट जा कुछ मिलता है उस पर एक नजर डालें

ऐसे मामले जहाँ कुछ भी नहीं दिया गया
10 रुपया प्रतिमाह का भुगतान
11 से 20 रुपय प्रतिमाह
21 से 40 रुपय प्रतिमाह
41 से 60 रुपय प्रतिमाह
61 से 80 रुपय प्रतिमाह
80 रुपय या इससे अधिक प्रतिमाह

20 0 प्रतिशत

8 5 ,

12 0 ,

24 0 ,

19 9 ,

8 3 ,

7 3 ,

ये भुगतान कागज पर दिखाय गए हैं। वास्तविकता इससे भिन्न है। घान के लिए उन्हें जो दिया जाता है वह बेहद अमानवीय है। फिर भी उस घान के घन्ते में बड़ा चढ़ाकर एक रकम लिख ली जाती है। माय ही भुगतान के रूप में जो दज किया जाता है उसे व्याज कहकर बराबर कर दिया जाता है।

सामान्य तौर पर एक मजदूर का प्रतिदिन 4 रुपय की दर से भुगतान किया जाता है। कभी कभी घाना भी दिया जाता है। इसके अलावा काम के घट सीमित ह। लेकिन वधुआ मजदूर पर इनमें से कोई बान लागू नहीं हानी और उनसे चौबीस घट काम लिया जा सकता है।

नियमित मजदूर का काम पर लगान के लिए 120 रुपय प्रतिमाह की 'यूनतम' मजदूरी देनी पड़ती है और वह निर्धारित घटा के अलावा काम नहीं करता। इसके विपरीत एक वधुआ मजदूर से बिना ज्यादा पसा खच किए 15 घट तक काम लिया जाता है। इसलिए वधुआ मजदूर रखन में मालिक को ज्यादा मुनाफा होता है।

व्याज के भुगतान के रूप में जो कटौती की जाती है उससे बज की मूल राशि में कोई कमी नहीं होती। इसका कारण महाजना के दिमाग से उपजा एक अनोखा गणित है। वधुआ मजदूर कभी भाग नहीं सकता और 60 प्रतिशत ऐसे मजदूर तथा उनके वंशज भी हमेशा के लिए गुलामी की ज़ंजीर में जकड़ जाते हैं। निम्नांकित आंकड़ों से उनकी गुलामी की अवधि का पता चलता है

एक वष या इससे कम
एक से दो वष
दो से तीन वष
तीन से चार वष
चार से पाँच वष

29 0 प्रतिशत

5 4

1 1 ,

0 4 ,

0 3 ,

पाच से छह वष	0 2 प्रतिशत
छह से सात वष	0 2 "
सात से आठ वष	0 3 "
आठ से नौ वष	0 1 "
नौ से दस वष	0 3 "
दस वष स अधिक्	0 2 "
आजीवन	2 3 "
वशजा का लेकर अनिशचित अवधि के लिए	55 7 "
अज्ञात	4 5 ,

कज लेते समय जो समझौता होता है उसका कभी पालन नहीं किया जाता । ममझौते का आधार कज को चुकता करना होता है और उस अवधि क पूरा हान पर जिसम कज की अदायगी हो जानी चाहिए, खाते म कज की राशि बढ़ चुकी होती है । इसलिए गुलामी की अवधि भी बढ़ जाती है ।

बधुआ मजदूरो म 60 प्रतिशत के पास अपनी काइ जमीन नहीं है—उनके पास खेत जोतन वोन के लिए हल बल भी नहीं है । जिनके पास एक दाएकड़ जमीन होती भी है वह कज क कारण महाजन के हाथ म पहुँच चुकी हाती है । उनम मे लगभग 20 5 प्रतिशत के पास रहन के लिए घर नहीं हाता और महाजन द्वारा बनवाय गय शोपडो म रहते हे । इस प्रकार महाजन उह घरेलू नौकर की तरह इस्तमाल कर सकते ह ।

यदि बधुआ मजदूर शादी करता है तो उसकी पत्नी महाजन क घर की नौकरानी बन जाती है, जिस कुछ भी मजदूरी नहीं मिलती ।

रगपुर म—जा अब बगलादश म है—मालिक लाग मजदूरो क लिए खाना बनान के नाम पर कुछ औरता को काम देत ह । दरअसल इन औरता को इसलिए काम पर रखा जाता है ताकि व मजदूरो को लुभाय रखें और व मालिक का काम छोड़कर भाग न सकें । इसके अलावा उन औरता के साथ अपनी कामवासना की पूर्ति से व इस शारीरिक जरूरत के पूरा होन के कारण ज्यादा क्षमता के साथ मजदूरी कर पाते ह ।

बधुआ मजदूर तब तक ही लाभदायक है जब तक वह काम कर सकता है । ज्यादातर इनके काम की उम्र 44 वष तक हाती है । इसके बाद उसके स्थान पर उसी क परिवार के किसी कम उम्र के व्यक्ति को रख लिया जाता है । निम्नांकित आँकड़े से स्थिति स्पष्ट है

15 वष या इसम कम
16 मे 20 वष

6 1 प्रतिशत
14 7 "

प्र	16 2 प्रतिशत
यं	19 2 "
यं	14 7 "
यं	12 3 "
इससे अधिक	16 8 "

२.

१। वर्ष की आयु के बीच वाले सबसे ज्यादा काम के होते हैं। सबसे ज्यादा काम होता है, क्योंकि इसी दौरान आदमी अपनी करता है। 15 वर्ष या इससे कम उम्र के मजदूर उतने लाभ-म कि उनसे काम निवाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कम है।

२। मास कानूनों के साथ इस बुराई को खामोशी के साथ बरदाश्त सी बुराई है जो तब तक कायम रहेगी जब तक भूमि सबधी बतन नहीं होता।

३.

४.

आंध्र प्रदेश

करीमनगर, महबूब नगर, मेडक, नालगाडा निजामाबाद और बारगल जिला म बीस हजार से अधिक बधुआ मजदूर हैं।

आदिलाबाद, अनंतपुर और हैदराबाद जिला म लगभग पंद्रह हजार बधुआ मजदूर हैं।

चित्तूर और पूर्वी गोदावरी जिलो म बधुआ मजदूरों की संख्या लगभग सात हजार है।

कुरनूल मे इनकी संख्या पांच सौ या इससे कुछ कम है।

(1) लिंगम एक हरिजन लड़का है। उसके पिता ने भू स्वामी से 450 रुपये उधार लिये थे और इसीलिए वह बधुआ मजदूर बना हुआ है। दलील यह दी जाती है कि उसे प्रतिमाह 28 रुपये दिये जायेंगे जिसम स कज की राशि का एक हिस्सा काट लिया जायगा।

ईश्वर ही बता सकता है कि कितने पैसे उसकी मजदूरी म से काटे जात है ? क्योंकि सूद की राशि दिनोदिन बढ़ती जा रही है। अगर लिंगम कभी काम पर नहीं पहुँचता है तो उसका मालिक प्रतिदिन उसकी मजदूरी से पांच रुपये काट लेता है। अगर लिंगम बीमार पड़ता है तो उसका मालिक उसके घर से घसीटता हुआ उसे खेत तक ले जाता है। 450 रुपये का का डेढ़ साल मे चुकता कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके अलावा मालिक न उसके बाप की जमीन भी हड़प ली है। लिंगम गुलामी करने के लिए मजबूर है।

(2) निजामाबाद जिले के दसनापल्ली गाँव के बलैया की पीड़ा को कौन समझ सकता है ? भू स्वामी ने उसकी गाय, भस और बछड़ा सब-कुछ हड़प लिया है। शहर के लोगो को यह समझने मे दिक्कत होगी कि भारत मे किसी ग्रामीण के लिए, जिसके पास जमीन नहीं है अथवा बहुत थोड़ी जमीन है, ये चीजें कितनी

बेचा जा सकता है। जुलाई के समय मवेशियों को बहुमूल्य हाती है। गाय का दूध गरीब लोग गाय, भैंस और बैलो पर काफी किराय पर दिया जा सकता है। गाय की उम्र 55 वर्ष थी। उसने एक भू-स्वामी से निभर करते हैं। 1977 म बत्त और बदले में उसके खेत पर काम करने के लिए दा सौ रुपये का कज लिया था जो लगा रखा था। सड़लू ने दिन रात जी-तोड़ अपन बारह वष व बेट सड़लू की ताकि कर्ज का भुगतान हो जाये, लेकिन एक मेहनत करके भू-स्वामी की सेव, भू-स्वामी ने बलैया को बताया कि उसकी तरफ वष की कठोर मेहनत के बाद हैं।

अभी भी चार सौ रुपये निकलते हुए और सड़लू को भू-स्वामी के घर से वापस बलया इस पर राजी नहीं ने बलैया की भैंस और एक बछड़े को ले लिया बुला लिया। बदले म भू-स्वामी 10 मीत आठ सौ रुपये होती है। दो सौ रुपये का और इन दोनों की मिली जुली व चार सौ रुपये हो जाता है और इसके बाद भी वज एक वष को गुलामी के बाद व्यक्ति आठ सौ रुपये वसूल लेता है।

भुगतान व रूप में वज देने वाला वीर है जहा तेलगाना का विद्रोह हुआ था, जहाँ

यह उस जाध्र प्रदेश की तसमिहीनो को सम्बोधित करने और उहे जमीन जनता पार्टी की विजय के बाद भूलब्ध अवसर का कम्युनिस्ट पार्टी ने फायदा देने का वायदा करने व प्रथम उमाक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जनता पार्टी ने उठाया। यही वह राज्य है जहा पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाने के बड़े-बड़े वायदे हरिजना और गिरिजनो व लिए 'निगम' के नाम से एक सरकारी सस्था है जो किये थ। इस राज्य म गिरिजन भाग और जमींदारो की साँठगाँठ से गिरिजनो जंगल के ठेकेदारो पुलिस वन वि। आध्र प्रदेश में पुलिस कभी भी—गलती से की जमीन पर कब्जा कर लेती है कार्रवाई नहीं करती। आध्र प्रदेश में पुलिस, भी—जमींदारो के खिलाफ कोई बकी बद्रूक की नली गिरिजनो, हरिजनो और जमींदारो और ठेकेदारो—इन सह।

जीताआ की जोर निशाना साधे गे में एक खबर छपी थी जिस पर ध्यान देने की निसम्बर 1978 म अखबारो पर गोली चला रही है जिन्होंने जमींदारो जरूरत है। पुलिस किसानो के गुमन के खिलाफ मिलजुल कर संघर्ष करने के लिए (जिहें डोरा कहा जाता है) के दा है। डोरा ही गाँव का मुखिया अर्थात् सरपच रयत कुली सगम की स्थापना की बाद पैदा होने पर वह बीच-बचाव का काम हाता है। दो गुटा क बीच काइ दिनो गुट उसे घर्षय अथवा शुल्क देते हैं। विवाद करता है और इस काम व लिए जम्मीब की जाती है कि उस व्यक्ति का पसा के हल हो जान के बाद उसस यह हुआ है और दोषी व्यक्ति के पैसे को गाँव के वह लौटा ग्या जो देगुनाह सादित। काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि डोरा विकास म अस्तमाल किया जायग लोग पसा का घाटाता करत हैं।

इस प्रकार उन्होंने गरीबा से लाखा रुपये लूटे हैं। चिन्नमथूपल्ली गांव के सरपंच ने सात लाख रुपये का गवन किया है। यह सरपंच कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी का प्रेजिडेंट था और कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक का चेयरमैन रह चुका है। इन सरपंच ने एक के बाद एक गांवों को लूटने का सिलसिला चला रखा है और इस लूट के धन से वे परती जमीन तथा पचायती जमीन की खरीद करते हैं।

कभी कभी ये लोग धन्य की राशि के बदले में जमीन ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में जमीन पर पूरा अधिकार होने के बावजूद जमीन का मालिक बहा जा नहीं सकता। सरपंच को पुलिस की पूरी मदद मिलती है। भविष्य में भी उनको यह मदद मिलती रहेगी।

(3) 33 वर्षीय भूमया और उसके परिवार के सदस्य त्रिंकोटक वधुआ मजदूर बने रहे। वे निजामाबाद जिले के लक्ष्मीदेवीपल्ली नामक गांव में रहते हैं। उसके चाचा ने बारह बरस तक जीता के रूप में काम किया था और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गयी। भू-स्वामी के पास में मात सौ रुपये का बज्र दिया गया। भू-स्वामी ने उस समय उनकी पंद्रह बीघा जमीन पर बंझा कर लिया, लेकिन इतना उसे पर्याप्त नहीं लगा। जसी स्थिति बनी थी उसके अनुसार यदि भूमया के पास पांच हजार रुपये होते तो शायद वह अपने बज्र से मुक्ति पा सकता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे और वह गुलाम बना रहा।

(4) 1977 में मेडक तालुक के शंकरपट गांव के टुडू रामुदू की उम्र 25 वर्ष थी। वह जाति से हरिजन हैं। तेलुगू भाषा में वधुआ मजदूर प्रथा को 'वेटी चाकरी' कहते हैं और वधुआ मजदूर को 'जीतागाडू' कहा जाता है। एक वधुआ मजदूर और मालिक के बीच हुए समझौते को जीतम कहते हैं। जीतम का अर्थ मजदूरी भी होता है।

रामुदू के पिता भूमया और उसकी मा की मृत्यु तभी हुई थी जब वह महज आठ वर्ष का था। उसके बड़े भाई ने उसे एक कोमाती अथवा वश्य जमींदार के यहाँ जीतागाडू बनाकर रख दिया था। जीतम के रूप में उसे प्रतिमाह पांच रुपये मिलते थे। रामुदू को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके बड़े भाई ने मानिक से कितना बज्र लिया है?

तीन वर्ष के बाद रामुदू वहाँ से रिहा हुआ। इसके बाद उसका भाई उन शंकर कमरम गांव के मुथम रेड्डी नामक भू-स्वामी के घर गया। वहाँ उसने पाँच सौ रुपये उधार लिये और रामुदू को जीतागाडू बनाकर बहा रखा दिया। यहाँ जीतम के रूप में प्रतिमाह 25 रुपये की राशि मिल गई। दादा मामला में रामुदू का अपनी तनख्वाह का दखल नहीं हुआ। उसके भाई ने बातें मलिय गये बज्र के अपनी शादी कर ली। उस नवविवाहित पत्नी ने भी मजदूर के रूप में काम शुरू किया। रामुदू दिन रात काम करता था और जान के लिए उसे नाममात्र

मिलता था। हर रोज उसे दोपहर म दो मील तक पैदल चलकर खाना खाने घर खाना पड़ता था। मालिक व हाथा उसे रोज मार खानी पड़ती थी। दो साल के बाद वह वहाँ से रिहा हो सका।

उसके भाई ने उसी गांव के माली पटल नगया नामक व्यक्ति से 24 प्रतिशत ब्याज पर तीन सौ रुपये उधार लिये। इस पैसे से उसने रेड्डी के कज का भुगतान किया और रामुदू अब नगया का जीतागाडू हो गया था। यहा जीतम के रूप म बीस रुपये प्रतिमाह की राशि तय हुई। हर शाम उसे खान के लिए एक बटोरा उबली हुई मक्काई मिलती थी। नगया के यहाँ उसने एक बरस तक काम किया।

इसके बाद उसके भाई ने बमारन गांव के वाला पुचया नामक व्यक्ति के यहा उसे रख दिया और अपना पिछला कज उतारने के लिए इस व्यक्ति स तीन सौ रुपये का ऋण लिया। रामुदू की एक साल की मेहनत को याज का भुगतान माना गया। उसने तीस रुपये प्रतिमाह के जीतम पर पुचया के यहा दो बरस तक मजदूरी की। तनप्वाट के जलावा उसे एक चपाती और एक बटोरा दलिया भी मिलता था।

अब रामुदू बड़ा हो गया था। उसके भाई ने पटवारी रामुलू से एक हजार रुपये की मांग की। रामुलू ने यह राशि दे दी, लेकिन बदले म रामुदू को उसने पन्द्रह बरस के लिए बधुआ मजदूर बना लिया। उसके भाई ने बकाया ब्याज के रूप म पुचया को दो सौ रुपये वापस किये। सौ रुपये और पच्चीस किला चावल के साथ उसने रामुदू की शादी यल्लामा नामक औरत मे कर दी। रामुदू को तीस रुपये जीतम के रूप म मिलते थे। पटवारी ने कहा कि उसे कोई ब्याज नहीं चाहिए।

नया मालिक रामुदू को खाना नहीं देता था। यल्लामा कभी कभी दानव मजदूर के रूप म काम करके एक दो रुपय कमा लाती थी और उसी से अपने और अपने पति के लिए कुछ खाने का इंतजाम करती। रामुदू का एक लड़का पदा हुआ। रामुदू रोज सवेर छह बजे से देर रात तक काम करता और प्रतिदिन खाना खाने के लिए दो मील पैदल चलकर अपने घर पहुँचता।

छह बरस के बाद उसके मालिक ने बताया कि कज की राशि बढ़कर 1,300 रुपये हो गयी है। रामुदू यह सुनकर हक्का तक्का रह गया, क्योंकि उसे न तो कभी मजदूरी मिली थी और न खाने के लिए ही कुछ दिया जाता था। अब वह पूरी तरह बदहवास हो चुका था और समय समय पर पैसे उधार लेकर शराब पिया करता था। उसने तय कर लिया था कि अपने बेटे को वह जीतागाडू नहीं बनने देगा। यह कहानी तेलंगाना के एक किसान की है जहाँ शापका के त्रिलाफ लडाई आज भी जारी है।

(5) मेडव ताल्लुक म जरुमुलुपल्ली गांव के सिद्दीरामुलू की उम्र 1977 म

21 वर्ष थी। 'स्वतंत्र तेलगाना' आंदोलन जब शुरू हुआ था और शिक्षा संस्थाएँ बंद हो गयी थी, उस समय वह छोटी कक्षा में पढ़ता था। उसने काम की तलाश शुरू की। एक वर्ष तक वह दैनिक मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। उसका बड़ा भाई भी इसी तरह अपनी जिंदगी गुज़ार रहा था। परिवार में एक बीघे से भी कम जमीन थी। उसके पिता उम्र थोड़ी सी जमीन पर ही खेती करते थे और अपने एक जोड़ा भूसे किराये पर देते थे। इससे उन्हें प्रतिदिन दस रुपये की आय हो जाती थी।

एक कहावत है—चार दिनों की चादनी फिर अँधेरी रात। सिद्दीरामुलू का बड़ा भाई जाड़े की एक रात में आग के अलाव की बगल में सो रहा था। उसके कपड़ा में आग लग गयी और वह जल कर मर गया। भाई की मृत्यु से परिवार की आय में काफी कमी हुई गयी। सिद्दीरामुलू पड़ोस के शहर में मजदूरी करता था। घर में जब खाने का सबूत पड़ा हो गया तो उसके पिता ने अपने भूसे बेच दिये।

अब इस परिवार पर मुसीबत के बादल भँडराने लग। सिद्दीरामुलू की दादी की मृत्यु हो गयी और उनकी अंतिम संस्कार के लिए घर में बिलकुल पैसे नहीं थे। सिद्दीरामुलू के पिता ने बैंकट्या से दो सौ रुपये उधार लिये और अपने बेटे को सात वर्ष के लिए उसके यहाँ जीतागाड़ू बना कर भेज दिया। उस समय इसकी उम्र 13 वर्ष थी। चार वर्ष तक उसने मालिक के मवेशियों को चराया। बाद में जवान होने पर उसे खेत जानने के काम में लगा दिया गया। यहाँ अविश्वसनीय रूप से मेहनत करनी पड़ती थी—कभी-कभी तो उसे एक सास में आठ घंटे तक हल खींचना पड़ता था।

सिद्दीरामुलू के लिए अब वे दिन जब वह स्कूल जाता था, जब उसके परिवार के लोगो को बड़ी मेहनत के बाद ही सही भरपेट खाना तो मिलता था अब अतीत की यादगार बनकर रह गये। उसके मालिक ने सात वर्ष के बाद उसे अपनी गुलामी से आजाद किया। इसके बाद वह पास के एक गाँव की चीनी मिल में काम करने लगा। यहाँ उस प्रतिदिन पाँच रुपये मिलते थे। उसके जीवन में यह सबसे सुखद दिन थे। लेकिन गन् की फसल के कटने के साथ ही उसका काम भी खत्म हो गया और वह बेरोजगार हो गया था।

उसके पिता ने उसकी शादी करने का फैसला किया। उन्होंने रमया कापू से चार सौ रुपये उधार लिये और राजम्मा नामक लड़की से उसकी शादी कर दी। सिद्दीरामुलू अब रमया का जीतागाड़ू हो गया था और कापू ने फैसला किया कि वह जीतम के रूप में उसे प्रतिमाह बीस रुपये देगा।

कुछ वर्षों बाद इस गाँव में 42 बधुआ मजदूरों के मसले को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने एक आंदोलन शुरू किया। जब आंदोलन चरमबिंदु पर पहुँच गया तब

सरकार की नींद टूटी। गांव में एक छड़ विनास अधिकारी और एक थ्रम अधिकारी पहुँचा। उन लोगों ने जमींदारों और वधुआ मजदूरों का बुनाया और इस बैठक में तमाम तथ्यों का उद्घाटन हुआ।

अब तक की प्रथा के अनुसार किसी व्यक्ति का दो सौ रुपये का बजट बढ़ते जाठ रुपये प्रतिमाह बतन पर सात रुपये के लिए जीतागाड़ बनाया जाता था। साल वष तक जीतागाड़ में काम न कर और उसे एक पैस का भी भुगतान न करके मालिक 6 720 रुपये बमाता था। साम ही अगर जीतागाड़ का उसके थ्रम के बढ़ते उचित मजदूरी दी जाये तो मालिक को साल से आठ हजार रुपये खर्च करने पड़ते।

अधिकारियाँ बनाया कि राज्य सरकार ने एक न्यूनतम वेतन कानून पारित कर रखा है। इस कानून के अनुसार दैनिक मजदूरी करने वाला का तीन रुपये पांच पैसे और मासिक बतन पर काम करने वाला मजदूर का 91 रुपये 63 पैसे प्रतिमाह था। 100 रुपये प्रति वष मिलने चाहिए। इन दरों को बाँफी पहले सरकारी तौर पर घोषित कर दिया गया था, लेकिन किसी भी भू-स्वामी ने इसी भी दरों पर भुगतान नहीं किया।

1971 की जागणना के अनुसार आंध्र प्रदेश में खेतिहर मजदूरों की संख्या 68,29,000 थी। 1954 में राज्य में पहली बार न्यूनतम वेतन कानून था। बाद में 1961, 1966, 1968 और 1974 में इसमें संशोधन किया गया। अंतिम संशोधन आदोलन से बाँफी पूरा हुआ था। जा भी हा जमींदारों सरकारी तौर के मुताबिक पैसे देने की बात मान ली।

सिद्दीरामुलू जैसे लोगों के दिमाग में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। थोड़े से पैसे का बतन के कारण वे मामूली-भी तनज्वाह पर जीतागाड़ बने रहना नहीं बरदाश्त करेगा। बहुत दिनों से वे मुताबिक कर रहे हैं—निश्चय ही उनके मद में जा पता इकट्ठा हुआ होगा वह उनका बजट उतारने के लिए बाँफी होगा।

पार्टी के लोग बिलकुल अच्छे हैं। उनके आदोलन की ही पजह से तो दोनों अफसर यहाँ नए आए। जमींदार भी उनकी बात मान गया। सभी जीतागाड़ खुशी में पागल हो रहे थे।

लेकिन यह एक झूठी खुशी थी। दो महीने बाद जमींदार ने सरकारी बतन दरों के मुताबिक पैसे दो से इबार कर लिया। जीतागाड़ों को अपने मन पसोने में ही बजट उतारना होगा।

हरिजन समुदाय के उड़े-बूढ़े न जमींदारों में बातचीत की जो आखिरकार सरकारी दर से आधी मजदूरी देने को तयार हो गये। दाना पक्ष इस पर राजी हुए कि मासिक बतन के रूप में 50 रुपये लिया जायेगा।

सिद्दीरामुलू बजट उतारने के लिए फिर महनत करने लगा। राजम्मा भी

दैनिक मजदूर की हैसियत से काम करने लगी। वह 3 रुपये रोजाना कमाने लगी। सिद्दीरामुलू का उम्मीद हो गयी कि वह चार महीने में बज्र चुकता कर देगा।

(6) भेडक ताल्लुक के कूचनापल्ली गांव के शिवराजया के बेटे रामचंद्र को यह याद भी नहीं है कि उसके पिता न नागया से बज्र लिया था। उसे बस इतना ही याद है कि वह मात बप की उम्र से ही नागया का जीतागाड़ू है। उसे जीतम के तौर पर प्रतिमाह 8 रुपया और दोना वक्त का खाना मिलता था। अपनी तनख्वाह उसे कभी नहीं मिली। वह नागया के साथ छह साल तक रहा। उसके पिता की मृत्यु हो गयी। उसके बड़े भाई उस अपन साथ ले गये और उहाने करनम रामुलू का यहा जीतागाड़ू बना दिया। उसके नये मालिक ने जोर दिया कि रामचंद्र की शादी कर दी जाये। रामचंद्र का बड़ा भाई भी यही चाहता था। रामुलू ने 37 प्रतिशत ब्याज पर 450 रुपये उधार दिये और जीतम की राशि बढ़ा कर 18 रुपये कर दी। दुन्हुन की कीमत 100 रुपये जदा करन क बाद रामचंद्र ने बैक्ममा से शादी कर ली।

450 रुपये पर सालाना ब्याज 166 50 रुपये था। रामुलू का पता था कि रामचंद्र कभी यह पमा नहीं दे सकता। वह हर रोज उसकी पत्नी बैक्ममा के सामने रामचंद्र का बजरतापूवक पीटता था और बैक्ममा असहाय नजरो से उसे देखती रहती। जब रामचंद्र के बड़े भाई ने इसका विरोध किया तो उसे भी खूब पीटा गया। इस दुदशा का दखवर हरिजन समुदाय के पड़ोसियों ने सुझाव दिया कि रामचंद्र को अपन दोना बैल बेचकर यह बज्र उतार देना चाहिए। रामुलू पैस नहीं चाहता था—उसकी निगाह उन दोना बला पर थी। अगर रामचंद्र बला को बेच पाता तो बज्र उतारने के बाद उसके पास कुछ पैस बचे रहत। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रामुलू ने जब उसे अनिम तौर पर अपने चगुल में छोडा तब तक वह कगान बन चुका था।

तेलगाना क विप्रात जिले में रामचंद्र को सचमुच गुलामी से कौन मुक्ति दिला पायगा? उस कोई उम्मीद नहीं थी। वह एक हरिजन था और जीतागाड़ू था। वह दीन हीन था।

बैक्ममा बीमार पड़ी और उसे लक्ष्मी रेडडी से बज्र लेना पडा। अब एक बार फिर वह जाल में फँस गया था। 1977 में वह पहले ही रेडडी के यहा चार सात बधुआ बनकर काम कर चुका था। ब्याज की दर 39 प्रतिशत थी। रामचंद्र का अपनी ना, पत्नी और पांच साल की एक बहन की देखभाल करनी पडती थी। दाना माहिलाएँ भी दो रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी करती थी। रामचंद्र को न तो एक पसा मिलता था और न उसे खाने को कुछ मिलता था। उसका परिवार 4 रुपया महीने की दैनिक आय पर चलता था।

क्या उसे याद है कि उसके पिता के पास कभी 4 एकड़ जमीन थी? शिव

राज्या के पास बसे यह जमीन थी रामचंद्र का नहीं पता। शायद 1960 के दशक में सरकार ने जो जमीन बांटी थी उस पर शिवराज का स्पष्ट अधिकार दिया गया था। शिवराज ने फिर सेत जातन-धाने के लिए सरकार में 600 रुपये का बज्र लिया। लेकिन सेती नहीं हो सकी, क्योंकि जो पूजी थी वह परिवार का पेट भरने में ही खच गई थी। इस बीच सरकार ने ब्याज की अदायगी के लिए दबाव डालना शुरू किया। एमी हालत थी और ऐसी हालत में जब कोई गरीब किसान कष्ट में हो बिठल रेडडी जसा धनी भू-स्वामी को चुनचाप यह देख सकता है? वह 100 एकर जमीन दो ट्रक्टर एक जीप, ट्रेक्टर ट्राइम्प्ट रेडिया का मालिक था और उसका गल में साने की एक मोटी ज़ोर लटवती रहती थी।

उसने शिवराज का भी जमीन ले ली और सरकार को मूल तथा मूद दाना चुकता कर दिया। शिवराज का 4 एकर उपजाऊ जमीन के बल में उसने 1 एकर बजर जमीन दे दी। उसे अपना जानवरा का चराने के लिए इस जमीन की सरत जरूरत थी। गरीब किसान का इसके लिए राजी होना पड़ा। बस बागज पत्र उसका नाम में रह गया।

1968 में रेडडी उस सत का जातने लगा। पिछले दस वर्षों में रेडडी इसी तरीके से अपनी जमीन बटाता रहा था और अब तक उसने कम-से-कम 20 परिवारों को बगल बना दिया था। ये सभी हरिजन थे। इसी तरह की परिस्थितियों में उन्हें सरकार द्वारा जमीन दी गयी थी और उन्होंने सरकार से बज्र के रूप में काय पूजी ली थी। बज्र की अदायगी के लिए उनकी जार से दबाव पड़ने पर वे बिठल रेडडी के शिकार बन और बिठल रेडडी ने उनकी आर से सरकार का बज्र उतार कर उनकी सारी जमीन हड़प ली। यह एक अजीब विडम्बना थी। जमीन के मानिक किसान थे पर फसल कट कर रेडडी के यहाँ जाती थी।

1977 में रामचंद्र ने जिला कलक्टर के पास अर्जी दी और अपील की कि उसे वह जमीन वापस दी जाये जिस पर उसके पिता का कभी स्वामित्व था। अधिकारियों ने उसे बताया कि अब उस जमीन का मालिक रेडडी है क्योंकि शिवराज का रेडडी के हाथों जमीन खेच दी है। रेडडी के पास अपने दावे की पुष्टि के लिए अँगूठे का निशान लगा एक दस्तावेज भी था। वह पिछले दस वर्षों से इस जमीन की फसल पा रहा था। रामचंद्र के पास जमीन सम्बन्धी बागजात थे, फिर भी जमीन पर उसका कोई हक नहीं था। रामचंद्र अब क्या कर सकता था? उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए उसके पास यह साबित करने का कोई तरीका नहीं था कि रेडडी के पास जो दस्तावेज है वह जाली है। अगर वह मामले को आगे बढ़ाता तो उसके परिवार के सदस्यों की जिन्दगी खतरे में पड़ जाती। वह किससे विरोध करता? कौन उसकी बात सुनेगा? अगर वह गांव के

स्थानों की आसू भरी कहानियाँ हैं।

जनता सरकार के पतन के बाद पारमवीषा, विपरा तथा अन्य स्थानों पर न जाने कितनी लाशें गिरी।

बिहार एक विशेष क्षेत्र है। नालंदा जिले के काइला में पुलिस ने जमींदार के गुंडा द्वारा हरिजनों का कत्लेआम चुपचाप देखा। बिहार में पुलिस और प्रशासन एक सदिग्ध स्थिति में हैं। उन्होंने जनता में अपने प्रति तनिक भी विश्वास का नाव नहीं पैदा किया। हरिजनों और आदिवासियों के दमन में पिछले 75 वर्षों में इनकी जाँ भूमिका रही है उस पर अलग में मुकम्मल रिपोर्ट लिखी जा सकती है। बिहार में जो घटनाएँ घटीं वे वहीं और देखने में नहीं आती।

26 जून, 1979 को राहतास जिले के ममहता गाँव में एक पुलिस इस्पेक्टर एक सब-इस्पेक्टर और हथियारबंद पुलिस की तीन टुकड़ियों ने जमींदारों के साथ साठ-गाठ करके हरिजनों की बस्ती पर धावा बोल दिया। उन्होंने यहाँ के लोगों को पीटा और सारा सामान लूट लिया। चार हरिजनों की हत्या के बाद, वे वहाँ से भाग गये।

क्या उन्हें कोई सजा मिली? दोनों जफतरों को बस मुअ्तिल कर दिया गया। सजा का सवाल बाद में पढ़ा होता है। ऐसा क्या होता है?

बोधगया बिहार के पवित्र स्थानों में से एक है। यहाँ के मंदिर का महत्त्व बिहार के सबसे बड़े जमींदारों में से है। उनके पास 30,000 बीघा बेनामी जमीन है। छात्रों के एक दल ने इस जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीनों के बीच बांटने की कांशिश की। महत्त्व के गुंडा न छात्रों पर बमों और बंदूकों में हंगला किया और उन्हें तितर-बितर कर दिया। इस बारदात में चार छात्र मारे गये और अनेक घायल हुए। यह घटना 9 अगस्त, 1979 की है।

बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त किये जान से सम्बंधित जो कानून है उसमें 'हलवाहा' शब्द कहीं नहीं आता है। यह प्रथा पटना जिले में प्रचलित है। बाढ़ सब डिवीजन में जमींदार लोग अपनी जमीन पर खेती करने के लिए हरिजनों का लगाते हैं। जो म्वतन मजदूर है उन्हें 'छुट्टा' कहा जाता है। हलवाहा का 'बधुआ हलवाहा' कहा जाता है क्योंकि वे बज्र से बंधित हैं।

(1) रामपुर डुमरा गाँव के हलवाहा भूमिहीन हैं और वे मामूली-मध्यम जमींदारों के नेता में काम करते हैं। उन्हें गाँव से बाहर किसी अन्य काम-चारी के लिए काम करने की अनुमति नहीं होती। उन्हें गाँव से बाहर निष्कलन की आज्ञा नहीं होती — शादी-प्याह जिस सामाजिक समारोह में भी भाग लेने वे गाँव से बाहर नहीं जा सकते। हलवाहे के परिवार के सभी सदस्य उस मालिक के गुलाम समझे जाते हैं। इस प्रकार एक आदमी का मामूली-मध्यम देकर पूरे परिवार में काम लिया जाता है। उन्हें बाहर स्वतन्त्र रूप से काम करने की

घोड़ा उकमाने के बाद राजस्व बोर्ड ने बताया कि जुलाई 1964 में राज्य सरकार से कहा गया था कि वह तेलंगाना में इस नियम को लागू करे। राज्य सरकार इस मसले पर चुप रही।

1975 में बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश लागू किया गया।

हमने 1977 से सम्बंधित कुछ मामलों का जिक्र किया है।

बिहार

पलामू जिले को सही अर्थों में बंधुआ मजदूर प्रदेश कहा जा सकता है। यहाँ ऐसे अभागा की संख्या 40 हजार में भी अधिक है। सारन चम्पारण मुंगेर और सयाल परगना में से प्रत्येक स्थान पर दस हजार से बीस हजार बंधुआ मजदूर हैं और गया और मुजफ्फरपुर में से प्रत्येक में पाँच हजार से दस हजार। पटना और भागलपुर में प्रत्येक स्थान पर इनकी संख्या पाँच सौ से पाँच हजार तक है। सहरसा और दरभंगा में इनकी संख्या कम से कम पाँच-पाँच सौ है।

बंधुआ मजदूर प्रथा का मूल कारण हरिजना और आदिवासियों की आर्थिक असहायता ही है। यह प्रथा तब तक जारी रहेगी जब तक आवादी का बहुमत सब कुछ छोड़ कर गरीबी की रक्षा सनीचे बना रहेगा और एक अल्पमत समूह पर निर्भर रहेगा जिसकी सारी जमीन पर मिल्कियत है।

पलामू में कई बार लोग का ध्यान आकर्षित किया है। हर बार खबरें गलत नहीं हो सकती। ध्यान देने की बात है कि ऊपर जिन जिलों का उल्लेख किया गया है उनमें भाजपुर शामिल नहीं है। ता भी 14 अप्रैल 76 के अगुवार में छपी एक खबर में पता चलता है कि इस इलाके में भी यह प्रथा प्रचलित है।

राज्य सरकार ने 1976 में पलामू में कुछ दूर-दराज के प्लानों का छोड़कर अन्य इलाकों में इस प्रथा को खत्म करने की योजना बनाई थी। उसी कुछ वानुजी शम्भूजी का कहना है कि इस प्रथा को खत्म करने की योजना में कुछ बंधुआ मजदूर बंधुआ मजदूरों को जायेंगे—उनकी यह स्थिति कुछ दिनों के कारण है।

वास्तविक तत्वावर बहुत बुरा लिय हुआ है। बिहार के अलावा दूसरा कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ सम्पत्ति का मार मान का बोझ हरिजना के साथ पड़ती बरता और अमानवीयता का साथ पड़ा थाया जाता हो।

बिहार के सबसे जमीनदार पर हमें बार्ड पत्र नहीं पता कि कितने में कितना भाग है। जनता सरकार के जिन में हरिजना का बर्बर पराहार हुआ और भागिनत गाँवों में जहाँ थोड़ा-थोड़ा का साथ बनाकर भी पता है। बसन्ती पम्पहोर, मुसामपुर निरहोनी, नरसपुर गाँव, उषापुर, जमना, स्पेडा, बिशमपुर, निरही, बार्दा, पानुर परवा, रिमई, अन्वारा तथा अन्य कई

स्थाना की औसत भरी बहानियाँ हैं।

जनता सरकार के पतन के बाद पारसबीघा रिपरा तथा अन्य स्थाना पर न जाने बितनी लाश गिरी।

बिहार एक विशेष क्षेत्र है। नालंदा जिले के काइलास पुनिम ने जमींदार के गुंडा द्वारा हरिजना का कत्लेआम चुपचाप देखा। बिहार में पुलिस और प्रशासन एक सदिग्ध स्थिति में हैं। इन्होंने जनता में अपने प्रति तनिक भी विश्वास का भाव नहीं पैदा किया। हरिजना और आदिवासियों के दमन में पिछले दस वर्षों में इनकी जो भूमिका रही है उस पर अलग से मुकम्मल रिपोर्ट लिखी जा सकती है। बिहार में जो घटनाएँ घटी हैं वही और देखने में नहीं आती।

26 जून 1979 का रोहतास जिले के समहता गांव में एक पुलिस इस्पेक्टर, एक सब इस्पेक्टर और हथियारबंद पुलिस की तीन टुकड़ियों ने जमोनाग के साथ साठ गांठ करके हरिजना की बस्ती पर धावा बोल ली। उन्होंने यहाँ के लोगों का पीटा और सारा सामान लूट लिया। चार हरिजनों की हत्या के बाद, वे वहाँ से भाग गये।

क्या उन्हें कोई सजा मिली? दोना जफ़सरा का बस मुआतिल कर दिया गया। मज्जा का सवाल बाद में पैदा हुना है। ऐसा क्या हुना है?

बोधगया बिहार के पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ के मंदिर का मृत बिहार के सबसे बड़े जमींदारों में से एक है। उसके पास 30,000 बीघा बेनामी जमीन है। छात्रों के एक दल ने इस जमीन का कुछ हिस्सा भूमिहीनों के बीच बांटने की वाशिश की। महंत के गुंडा न छात्रों पर बर्बाद और बंदूकों में हमला किया और उन्हें तितर-बितर कर दिया। इस बारदात में चार छात्र मारे गये और अनेक घायल हुए। यह घटना 9 अगस्त 1979 की है।

बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त किए जाने से सम्बंधित जा 'गानून है उसमें हलवाहा' शब्द वही नहीं आता है। यह प्रथा पटना जिले में प्रचलित है। बाढ़ सय-डिवीजन में जमींदार लोग अपनी जमीन पर बेती करने के लिए हरिजनों को लगाते हैं। जो स्वतंत्र मजदूर हैं उन्हें 'छुट्टा' कहा जाता है। हलवाहा का 'बधुआ हलवाहा' कहा जाता है क्योंकि वह बंधित है।

(1) रामपुर डुमरा गांव के हलवाहा भूमिहीन हैं और वे मायूनी से पैसे पर जमींदारों के खेता में काम करते हैं। उन्हें गाँव से राह में किसी अन्य काम चारी के लिए काम करने की अनुमति नहीं होती। उन्हें गांव से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती — शादी-ब्याह जस सामाजिक समारोहों में भी भाग लेने के गांव से बाहर नहीं जा सकते। हलवाहा के परिवार के सभी सदस्य उस मालिक के गुलाम समझे जाते हैं। इस प्रकार एक आदमी को मामूली में पैसों देकर पूरे परिवार में काम लिया जाता है। उन्हें बाहर स्वतंत्र रूप में काम करने की

इजाजत नहीं मिलती। वे चोरीसा घंटे अपने मालिक के लिए काम करने हैं। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दर से आधी मजदूरी मिलती है और वह भी अनाज के रूप में। यह प्रतिदिन लगभग 1.25 किन्तो मक्का या चाई और अनाज तथा थोड़ा-सा नाश्ता होता है। वे हलवाते कई पीढ़ियाँ से भूमिहारा व गुलाम हैं। उनके बीच एक कहावत चलती है कि अगर मालिक की मक्का या चाई ता हलवाह का लड्डवा भी बड़ा हो कर हलवाहा बनगा। सरकार की कानून निर्माताओं के अनुसार भेतिहर मजदूरों की तुलना में हलवाह बेहतर स्थिति में हैं।

रामपुर-डुमरा में मिडिल स्कूल और हाई स्कूल भूमिहारा द्वारा उलाय जाते हैं। भूमिहारा छात्र उन हरिजन छात्रों का पीछे हैं जो कानून जान की कोशिश करते हैं। प्रधानाध्यापक भुनेश्वर सिंह गाँव के मुखिया का भाई है और एक बदमाश जानदार है। उसने यहाँ मिहेश्वर पामवान नामक एक हलवाहा है जिसने 800 रुपये उधार लेने का कारण दिया किमी वतन का 18 वय उमकी गुलामी की। दस जादमी ने हाईस्कूल में एक भुक्त्मा दायर किया और जीत गया — अर्थात् न भुनेश्वर सिंह को आदेश दिया कि वह मिहेश्वर पामवान को 7300 रुपये दे। लेकिन अचानक मिहेश्वर की मृत्यु हो गयी और उमका एक मात्र उत्तराधिकारी 17-वर्षीय पुत्र हरपीत बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गया।

(2) शामली पासवान पिछले 15 वर्षों से उत्पन्न सिंह का हलवाहा है। पिता की मृत्यु के बाद उम 13 बेटा जमीन और बज्र का एक बाँझ प्राप्त हुआ था। उसका पिता ने अपने मालिक उदय सिंह से दामन मक्का उधार ले ली थी। वह उदय सिंह का हलवाहा बन गया और अपने मालिक की जमीन जानने लगा। फलस्वरूप उदय सिंह से जाता था। 1976 में शामली ने माँचा कि ऋण विमुक्ति आदेश न पुराने बज्र को रद्द कर दिया है और फिर उसने अपनी जमीन जानने-बाने की तयारी की। उदय सिंह ने उम मार डालने या किसी फौजदारी के मामले में फँसा देने की धमकी दी। शामली ने अपनी आज्ञा की सारी वाशिशें छोड़ दी।

(3) जमुना राम भुनेश्वर सिंह का पिता हृदय सिंह का हलवाहा है। वह एक महीने तक बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा रहा। हृदय सिंह के गुंडे उसके घर आय और उसके हाथ पर बांध कर एक डबे में टाँग कर ले गये। वे उसे नगा करके तब तक मारते रहे जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। वे उसे मरा हुआ समझ कर सड़क पर ही छोड़ गए — उसकी चोटा में लगातार खून बह रहा था। उसका बेटा शामली पाय के लिए पुलिस और जिलाधीश के यहाँ चक्कर लगाता रहा, पर कुछ भी लाभ न हुआ।

क्या सारे हलवाहे बंधुआ मजदूर नहीं हैं?

(4) पलामू के योगीखुरा गाँव के एक सवण हिन्दू की हरकतों से इस पाश-विक प्रथा की गम्भीर तस्वीर बहुत साफ उभर आती है।

यहाँ सेवकिया और कमिया जैसे कई तरह के बहुआ मजदूर हैं। इस व्यक्ति ने एक नये तरह के बहुआ मजदूर बनाये हैं जिसे घरमर कहते हैं।

1976 में राजनीतिक तौर पर उसका बड़ा दबदबा था। वह बिहार राज्य लाख विपणन सहकारी महासंघ में एक उच्च अधिकारी था। देश में जितना लाख पदा होता है उसका 50 प्रतिशत हिस्सा बिहार में होता है और इसमें से भी 34 प्रतिशत अकेले पलामू में होता है। लाख के नियात से पर्याप्त विदेशी मुद्रा की आय होती है। इसके उत्पादक हरिजन और आदिवासी हैं।

उनके हिता की रक्षा के लिए महासंघ को जिम्मेदारी दी गयी कि वह उत्पादकों से 3 रुपये प्रति किलो की दर से लाख की खरीद करें। इस व्यक्ति ने खरीद के लिए अपने एजेंट रखे जिन्होंने 25 पैसे से लेकर 50 पैसे प्रति किलो की दर से खरीद की। खरीद वाले रजिस्टर में 3 रुपये प्रति किलो की दर ही दर्ज की गयी और उत्पादकों के अँगूठे के निशान लेकर इसे एकदम दुरुस्त कर लिया गया। इस प्रकार इस व्यक्ति ने हर किनोग्राम पर लगभग ढाई रुपये बना लिये। उसकी आय का सबसे बड़ा साधन सिंचाई विभाग था। उसके मयुक्त परिवार के अनेक सदस्य इस विभाग में ठेकेदार के और उसका दामाद इस विभाग में ही एक उच्च पद पर था। उसके एक रिश्तेदार का जिले के शिक्षा बोर्ड पर नियंत्रण था हालांकि उसकी शिक्षा ऐसी थी कि वह ठीक से बात भी नहीं कर सकता था। जबरदस्त प्रभाव वाले इस महान व्यक्ति ने एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन भी किया जो उसके गुणगान करता रहता था।

अपने राजनीतिक प्रभाव, पैसे और सरकारी मदद से इस व्यक्ति ने हरिजनों और आदिवासियों की उस जमीन को लूट लिया जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली थी जिसे उन्होंने खरीदा था या भूदान, कोदवार और अधिभोजना के जरिए जिस पर उनका स्वामित्व था।

इस तरह की जमीन ग्रामीण किसान जोतते हैं।

उन्हें घरमर कहते हैं। फसल बटने के समय इस महापुरुष के रिश्तेदार जाते और उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा जबरदस्ती घरमरों में ले लेते। घरमरों से ये लोग अपने खेतों पर बिना मजदूरों के काम भी लेते।

इसके बाद सेवकिया और कमिया आते हैं जिनकी सख्या बहुत ज्यादा है। इस महापुरुष की केंद्रीय पत्नी के व्यापार पर भी इजारेदारी थी।

संभवतः पुलिस और वन विभाग पर भी उसकी इजारेदारी थी।

(5) खेत जोतने का काम हलबाहा करता है और चरबाहा भवेशियों को चराता है।

पलामू जिले के हरिहरगंज ब्लॉक में स्थित श्रीपालपुर गांव के श्यामा चमार ने पास के गांव मथुराना के राजपूत करीमन सिंह से चालीस रुपये उधार

लिया था। इससे एवज में उमन सबकिया के रूप में 14 साल तक मजदूरी की। शुरू में बज लेने के दो साल बाद उसने फिर 60 रुपये लिए। 14 साल तक काम करने के बाद उसका बेटे बासुदेव को 15 वर्ष तक काम करना पड़ा। उसी 15 वर्ष की गुनामी 1978 में पूरी हुई और वह अभी भी वही काम कर रहा था। इससे बावजूद वह अभी उत्तरा रही था। इसलिए बासुदेव के बेटे नरेण ने अपना पिता के साथ काम करना शुरू किया। उनकी उम्र 15 वर्ष है और अब तक कई साल उसने चरवाहे के रूप में गुजारा दिये हैं। नरेण को कुछ भी मजदूरी नहीं मिलती है। 1976 में एक अफसर उसे रिहा कराने आया था, लेकिन बासुदेव को रिहा नहीं किया जा सका। लेकिन उसके मालिक ने ज़रूर देखा कि उसका अधिारी इसमें काफी दिलचस्पी ले रहा है, तो उसने बासुदेव का मारना पीटना बंद कर दिया।

(6) बधु आ मजदूर प्रथा के प्रतीक का समिया मजदूरों का उत्थापन प्रासंगिक होगा। उनके नाम का पता नहीं है।

(7) एक बंनिये का बिल मर गया। उस बंनिये ने अपने समिया को जुए के नीचे धूल की जगह लगा दिया और बाजार तक गाड़ी पिचवात हुए ले गया।

(8) 1976 में पन्नामू के उपायुक्त ने वहाँ गये सर्वेक्षण दल को एक व्यक्ति के बारे में बताया। इस व्यक्ति ने केवल 56 पैसे काज लिये थे, इससे बदले में उसे जिन्गी भर सबकिया बनकर रहना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि बिहार और उड़ीसा में बधुआ मजदूर प्रथा 1920 में ही समाप्त कर दी गयी थी।

दादरा और नगर हवेली

1961-62 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में बलवा प्रणाली थी। आमतौर पर दुमला के आदिवासी बलवा होते थे। उन्हें 2 से 20 गुठ (जमीन की एक इकाई) जमीन दी जाती थी। मालिक बीज और बल सप्लाई करता था। इस जमीन की फसल बलवा ले सकते थे। उन्हें मालिक की जमीन पर अपने हाथों बनाने की भी इजाजत थी। बदले में उन्हें मालिक के रात में काम करना पड़ता था। अपने मालिक की अनुमति के बिना वे कहीं नहीं जा सकते थे। उन्हें प्रतिदिन 50 पैसे भी मिलते थे। पुरुष कृषि मजदूरों का प्रतिदिन एक रुपया 75 पैसे और महिलाओं को एक रुपया 25 पैसे मिलते थे।

1968-69 की एक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि बलवा प्रणाली सही जहाँ में बधुआ मजदूर प्रणाली नहीं थी। काज की राशि कम थी और इससे कोई धानूनी बदल नहीं उठाया गया।

गुजरात

धवोदरा और पचमहल जिला में ये प्रत्येक में बीस हजार से अधिक बधुआ मजदूर हैं। वलसाड, सुरे द्रागर, सूरत, राजकोट और महेसाणा जिलों में ये प्रत्येक जिले में दस से बीस हजार बधुआ मजदूर हैं। जहमदाबाद भंडा, पछ और साबरमती जिला में 5 सौ से दस हजार बधुआ मजदूर हैं। अमरेली, वाराणाठा, भावनगर, मेडा और दादरा जिला में पाँच सौ से पाँच हजार बधुआ मजदूर हैं।

गुजरात ने देश को महात्मा गांधी जी के बड़े उद्योगपति, सहकारी युग्म समितियाँ, एक अलग संस्कृति अपनी विनिष्कृति और बेशर्त आत्म राजनीति प्रदान की है। पाठना के सामान शायद हम बधुआ मजदूरों में अलग अलग उदाहरण न पेश कर सकें। इसकी जगह पर हम हरिजात पर हो रहे आगित्त अत्याचारों की दास्तान सुनाएँगे। ये हरिजात बधुआ मजदूर हैं जिन्हें हमारी माँ हलपति पट्टा जाता है।

1 जनवरी, 1975 का अहमदाबाद जिले में माराता नामक गाँव में 25 हरिजात अपनी जान बचाव के लिए रात के अँधेरे में गाँव से भाग गये। वे सुरिधी पहुँचे और पुलिस द्वारा पकड़े जाते तक वहाँ रहे। उन्होंने 6 अक्टूबर का 'इंडिया एक्सप्रेस' के सवाददाता का अपनी कहानी सुनायी। वे टकस चलपट्टर (गिरसदार) सुखरा नथुआ के भय से गाँव से भागे थे।

इस व्यक्ति ने 1 अक्टूबर की रात में दासा नामक एक हरिजात युग्म पर हमला किया था। मौते पर अचलगा के पहुँचे जाते थे वहाँ वह पीछे हट गया, पर वहाँ जान की धमकी दी गया। दूसरे रात हरिजात लोग गाँव छोड़कर भाग गये।

हरिजातों ने हमला ही इस आदमी के अत्याचारों को चुगताप करवाया लिया। उन्होंने हमारे लिए कुछ ग्रांटे और बगर मजदूरी पाय अपना श्रम लिया। इन्होंने कभी हमकी शिवायत नहीं की। गिरसदार एक सरकारी कर्मचारी होता है। उससे यही उम्मीद थी कि वह अत्याचारी होगा। अब पमल पट्टाई का समय नज़दीक आने पर उसका अत्याचार बढ़ता गया था।

21 9 78 का भावनगर जिले के कसलपुर गाँव में भूग्यामिया तीत बच्चा सहित नौ हरिजातों का मार्ग पीटा। पमलपट्टा आठ महीने मार गये।

8 8 77 का अग्रवाला में यह घटना छपी थी कि उमरिया भावगर, गांधी नगर और वाराणा जिला में मरण हिन्दुओं ने हरिजातों का पीटा। पचमहल जिले में मलगात गाँव में पुलिस ने हरिजातों की शिवायत दी पर गिरफ्तार कर लिया। 1974 में सुरद्रागर जिले में रोमापुर गाँव में आठ हरिजात मारे गये।

1977 में भी हरिजनों को सरकारी कुआ और नला से पानी लेने की इजाजत नहीं मिली। होटल और रेस्तराँओं में उनके लिए अलग प्लेटें हाती थी। सरकार द्वारा चलाये जाने वाले 'सावजनिक' वाहनों में चढ़ते समय अपमानित किया जाना उनके लिए आम बात थी।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन राज्यपाल ने प्रशासन पर जार दिया था कि वह रनमलपुर हृत्पाकाड के अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने हरिजनों का मदिरा और रेस्तराँओं में घुसना, सावजनिक कुआ से पानी लाना और सबके साथ बैठकर खाना सभ्य बना दिया था। इस पर सबण हिंदू नाराज हो उठे थे। छुआछूत बरतने के लिए 41 सरपंचों का निलम्बित किया गया था। इस राज्यपाल ने अनेक अच्छे काम किये, पर उन्हें हिंदुओं की नफरत मोल लेनी पड़ी।

जनता पार्टी के सत्ता में आते ही हरिजनों पर अत्याचारों की सैकड़ा घटनाएँ हुई। यह कहना ठीक नहीं होगा कि केवल जनता शासन काल के दौरान ही अत्याचारों की ऐसी घटनाएँ हुई। 1974 में तो जनता पार्टी नहीं थी। बहुत मृत्यु यह है कि गुजरात में हरिजनों पर हमेशा ही अत्याचार हुआ है। अपने कायकाल में एक राज्यपाल ने उन्हें समान अधिकार देने की कोशिश की और उसे सबण हिंदुओं का बोप झेलना पड़ा।

एक बार फिर हरिजनों को सावजनिक कुआ से पानी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रेस्तराँओं में उनके लिए अलग बरतन रखे गए। उन हरिजनों पर सूदखार महाजन बेहद क्रोधित हुए जिन्होंने सरकारी अधिकारियों की सलाह पर कज से राहत के लिए अर्जें दी थी।

पंचायत के मुखिया ने फैसला किया कि यदि एक भी भूस्वामी ने हरिजनों को काम दिया तो उस पर 51 रुपया जुर्माना किया जायेगा।

हरिजनों को इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें अपनी जमीनों व भी वापस नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि सहकारी दुग्ध समितियों ने भी उनमें दूध खरीदना बंद कर दिया।

हरिजनों का हमेशा गले निचले स्थान पर रहना पड़ता है और बचा के दिनों में हमेशा उनके झोपड़ा में पानी भरा रहता है। वे पाखाना साफ करते हैं और घर पर मूला ढोते हैं। गांधी जयंती में उनकी किस्मत सुधारने की चर्चा खूब चलती है। अगले दिन वे फिर भुला दिये जाते हैं।

गुजरात में कोई जुझारू आन्दोलन नहीं चल सकता। महात्मा गांधी के अनुयायी हरिजनों के नेता हैं। वे संविधान की दुहाई देते हैं। इस आदोलन में कोई भी जुझारू मौजवान नहीं है। और इसीलिए सभी जिलों में हजारों हरिजनों और आदिवासी गुलामी की जिन्दगी बसर करते हैं।

1939 में विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए राज्य के समाज

कल्याण मंत्री १ एतान किया था कि हलपति आदिवासिया में बाई भी बधुआ मजदूर ही है। वेशभूषण यह सही है बज्र तान के बाद ही बहली बनते हैं और बज्र दन वाले के यहाँ मजदूरी करते हैं।

उन्होंने चाहे जा भी कहा हो, लेकिन हाली लाग बधुआ मजदूर ही है। थोड़ी खाज करन से यह भी पता चल जायेगा कि हलपतिया के अलावा अन्य हरिजन भी हानी ही है।

1917 में इस बार में एक समिति का गठन हुआ था। 1948 में सूरत में यह प्रथा समाप्त हो गयी थी। फिर भी 1978 में देखा गया कि यहाँ 10 से 20 हजार बधुआ मजदूर थे।

यह कहना गलत है कि कानून अशक्त है। जिस राज्यपाल का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उन्होंने कानून को ही बड़ाई से लागू करके एक हद तक छुआछत का पालन किया था।

बधुआ मजदूर प्रणाली का वही मानसिकता जिंदा रखे हुए है जो हरिजनों पर अत्याचार की बहाल करती है।

दमनकारी जानते हैं कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश

दूर-दूर बसे गाँव वाले पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में राजाआ और जमींदारों के पास निर्विराध सत्ता थी। आज तक इन इलाकों का उचित ढंग से सर्वेक्षण नहीं हो सका है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समझें बिना बधुआ मजदूर प्रणाली का अध्ययन नहीं किया जा सकता। 1948 में मुख्य आयुक्त द्वारा बधुआ मजदूर प्रथा का गैर कानूनी धांपित किया गया और सरकारी दावा यह है कि यह प्रथा अब ही ही नहीं।

हमने देखा है कि कानून बेकार है। यह व्यवस्था वही फलफूल रही है जहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल एक उदाहरण है। खासतौर से यह भूतपूर्व दशौं रियासतों में खूब पनपता रहा है। उड़ीसा में गोतिआ इसका उदाहरण हैं। हिमाचल प्रदेश में इसका फलना फूलना बहुत स्वाभाविक है। इस लिए जब सरकारें जोर शोर के साथ इसे प्रचारित कर रही हों तो हम खामोश ही रहेंगे।

शिमला जिले में चोपल तहसील में और सिरमौर जिले में रेणुका और राजगढ़ इलाकों में वैध प्रणाली है। हरिजन लोग थोड़ी सी जमीन के लिए जिंदगी भर अपने मालिकों को गुलामी करते हैं।

मुठ्ठी भर अनाज और थोड़े से कज के लिए राज्य में गुलामी की प्रथा बेहद

जम्मू कश्मीर

वधुआ मजदूर प्रणाली का नगा रूप पिनीनपा के साथ प्रकट हो सकता है लेकिन यह परदे के पीछे छिपा भी रह सकता है। मिसाल के तौर पर पश्चिम बंगाल की माहिंदर प्रणाली को मले ही सरकारी तौर पर वधुआ मजदूर प्रणाली न माना जाय पर वास्तव में यह वधुआ मजदूर प्रणाली ही है।

पश्चिम बंगाल और कर्ल राजनीतिक तौर पर जागरूक राज्य है। इनकी तुलना में जम्मू और कश्मीर पिछड़ा राज्य है। इसके अनेक गाँव राज्य के भीतरी इलाकों में काफी दूर-दूर बसे हैं।

1961-62 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि पूछ जिले में हाना माझी और लझारी नाम से कई तरह की वधुआ मजदूर प्रणाली प्रचलित है। यहाँ भी इस प्रथा की पृष्ठभूमि वही है जो अन्य राज्यों में है। धनी जमींदार कज देकर गरीब हरिजन और आदिवासियों को अपने जाल में फँसा लेते हैं। अपने मालिकों के खेत में माझिया को मुपन में काम करना पड़ता है और कगाली में हो मर जाना पड़ता है। इसके बाद उस माँची का बेटा अपने गाँव के स्थान पर गुलामी करता है। 1976 में जख्यारा में छती खबरा में बताया गया था कि लद्दाख में वधुआ मजदूर प्रणाली है और कश्मीर में कारीगरों के रूप में लड़कों को वधुआ बनाकर रखा गया है। अनन्तनाग जिले में भी यही स्थिति है। वधुआ जिले के हरिजन वधुआ जिले में विता रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला—दोनों ने वधुआ मजदूर प्रथा पर प्रतिबन्ध लागू किया था।

सरकार ने कश्मीर में हस्तशिल्प का विकास करने की कोशिश की, लेकिन इसने बुद्धिजीवियों के दिमाग में कुछ शक ही पैदा किया है। हस्तशिल्प एक बड़ा व्यापार है और अनेक धनी व्यापारी इस क्षेत्र में अपनी पूँजी लगा चुके हैं। लेकिन हस्तशिल्प के सामान तैयार कौन करता है?

इनमें से अधिकांश बच्चे हैं। इनकी मर्यादा 1,08,000 है और इनमें से अधिकांश निजी मालिकों के यहाँ नौकरी करते हैं। हालाँकि 14 वर्ष से कम आयु के लड़कों का नौकरी पर रखना गैर कानूनी है पर अनेक लड़के अपनी कामवाजी जिले में 6 वर्ष से ही शुरू कर देते हैं। जहाँ वे काम करते हैं उन कारखानों में रोशनी हवा या स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का कोई पालन नहीं होता। फलस्वरूप वे टी० बी० जखवा आघात के रास्ते से पीड़ित हो जाते हैं। उर्दू ऐसी स्थितियों में इसीलिए काम करना पड़ता है, क्योंकि वे बेहद गरीब हैं। मालिका द्वारा उनके साथ कसा सलूक किया जाता है इसकी मिसाल बिलाल अहमद के मामले से दी जा सकती है।

बिलाल अहमद न श्रीनगर के अली माहम्मद बजा न कालीन बनान क बार खाने म 6 बष की उम्र से ही काम शुरू कर दिया था। उन दिना उसे प्रतिदिन 25 पैसे मजदूरी मिलती थी। 1980 म उसकी उम्र दस बष थी और उसे चार रुपये प्रतिदिन मिलते थे। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी ह। मा भाइया और बहना की देखभाल उस ही करनी पड़ती है।

4 मई, 1980 को उसकी एक उँगली कट गयी और वह अगले दिन काम पर न जा सका। 7 मई को जब वह काम पर गया तो बजा और उसके बेटे मुश्ताक न बिलाल अहमद को बुरी तरह पीटा। इसके बाद मुश्ताक और उसके भाइ माजि न लोह की छड़ गरम करके उसके शरीर का मात जगह दागा और फिर एक बमर म बद कर दिया। रात होने पर बिलाल घिड़की कूद कर भाग निकला और अपन घर जा पहुँचा। अब यह मामला अदालत म है।

बिलाल और उसकी तरह के तमाम लोग गुलाम ह, न कि मजदूर, हातावि उह जाना, माझी या तक्षारी नहीं कहा जा सकता। महत्वपूर्ण बात है, मालिक का खया। उसका मालिक समझता ह कि बिलाल उसका गुलाम है आ उसक कारखाने का उत्पादन बढ़ान के लिए ही पैदा हुआ है।

यह बबर खैया ही बधुआ मजदूर प्रणाली को बनाए हुए ह। दश के अ य हिम्मा की तरह जम्मू कश्मीर भी इस पाणविक प्रथा को बरकरार रखे हुए ह।

कनाडा

बगलौर आर शिमोगा जिला म से प्रत्येक म 20 हजार से अधिक बधुआ मजदूर ह।

बीजापुर, चित्रदुर्ग, गुलबर्गा, कोलार मैसूर उत्तर कानड और रायचूर जिला म से प्रत्येक जिले म दस से बीस हजार बधुआ मजदूर है।

धारवाड, हसन और मांड्या जिला म से प्रत्येक मे बधुआ मजदूरों की संख्या पाच से दस हजार है।

बेलारी और बेलगाम मे इनकी तादाद पाच सौ स पाच हजार है। कुर्ग, चिकमगलूर, दक्षिण कानड और तुमकेन जिला म से प्रत्येक मे एक सौ मे पाच सौ बधुआ मजदूर ह।

बधुआ मजदूरों के बारे म सरकारी रिपोर्ट का जायजा ले।

1961 62

मसूर (अभी कर्नाटक नहीं कहा गया था) के कुछ इलाका मे तो बधुआ मा दूर है उह जीया कहते है। मुमकिन है कि अलग-अलग नामा से कुछ और बधुआ मजदूर ह। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह जल्दी से जल्दी इस विषय पर

कारवाई करे।

1963 64

हसन जिले के सक्लेसपुर और बेलूर इलाकों म बधुआ मजदूर प्रथा कायम है। यह अनिवार्य है और वंश परम्परा के रूप म (बाप के बाद बेटे की बारी) प्रचलित है। इसका मूल कारण यहाँ की गरीबी है। 10 से 35 वर्ष की आयु तक के लोग जीया के रूप म है। उनके पिता और उनकी पत्नियाँ भी उन्हीं के साथ गुलामी करती हैं। सबलापुर ताल्लुब म सूदखार महाजन 144 प्रतिशत व्याज वसूलते हैं। अनेक कजदार लोग 15 से 40 वर्ष तक जीया बने रहते हैं। बलूर ताल्लुब म जीयाआ को खाना और कपड़े के अलावा वेतन के रूप म भी कुछ दिया जाता है। लेकिन वेतन के रूप म इन्हें इतना कम पसा मिलता है कि उससे वह व्याज भी नहीं दे पाते। फलस्वरूप बाप और बेटे अनेक दशका तक गुलामी करते रहते हैं।

1965 66 म प्रकाशित रिपोर्ट म पिछली दाना रिपोर्टों का ही विवरण संकलित था। इस रिपोर्ट के परिशिष्ट म कहा गया था कि बधुआ मजदूर प्रथा का मुख्य कारण कज है। इस प्रथा को समाप्त करने का एक मात्र तरीका जिये गये कजों को रद्द करना और कजदारों की स्थिति म सुधार लाना है।

उस वर्ष के दौरान गुलामी के एक और रूप का पता चला। कर्नाटक के अनेक स्थाना म और खासतौर से बेल्लारी जिले म गुलाम-वेश्याआ का एक बग पाया गया। हरिजना और वेदारा की औरता को दूसरी जाति के लोग बसावी (वेश्या) बना लेते हैं और इस धंधे से वे काफी पैस कमाते हैं। 1963 में सिरगुप्पा शहर की दस हजार की आबादी म 600 औरतें बसावी के रूप म सक्रिय थी। उसी वर्ष म देखा गया कि बुदलागी शहर की दस हजार की आबादी म 1,500 बसावी औरतें थी। इस सारे धंधे को एक धार्मिक पुट दे दिया गया है। हरिजन और वेदार जाति की खूबसूरत लड़कियाँ को मंदिरा में रख कर एक अनुष्ठान क जरिए मंदिर के देवता के साथ ब्याह दिया जाता है। एक सान या तमगा—जिसे ताली कहा जाता है—इन औरता के गले म बाँध दिया जाता है जो इस बात का प्रतीक है कि उनकी मंदिर के देवता से शादी हो गयी है। चूँकि इन लड़कियाँ को देवताआ के साथ ब्याह किया गया है इसीलिए वे अब नश्वर प्राणी मनुष्य के साथ नहीं ब्याही जा सकती। इसके बाद इनसे वेश्यावृत्ति करवायी जाती है। ये गरीब लड़कियाँ इतनी असहाय होती हैं कि अपने लिए कुछ कर भी नहीं सकती।

1965 66 म सरकार ने बुदलागी में इन बसावी औरता के बच्चा के लिए एक स्कूल खोला।

1969 70 म प्रकाशित एक रिपोर्ट क जरिए राज्य के दूर दराज के इलाकों

में जीया प्रणाली का एक और रहस्योद्घाटन हुआ। जाहिर था कि अत्यंत प्रगतिशील रिपोर्टों के जरिए और भी सूचनाएँ सामने आ रही थी। अनक गावा में प्राचीन जातियाँ व लोग गुलामी की जिंदगी बिता रहे थे। व कर्नाटक की और द्रविड जाति व पुरातन नस्ल में से थे।

कर्नाटक के सवण हिंदुआ के रबैय का अनुमान निम्नांकित घटनाओं से लगाया जा सकता है। 27 मई 1972 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अगस्त 1974 में एक हरिजन की बारात दूल्हा और दुल्हन के साथ उस सड़क से गुजर रही थी जो सवण हिंदुआ की वस्ती से होकर जाती है। हिंदुआ को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने दूल्हा दुल्हन सहित प्रत्येक बाराती का बुरी तरह पीटा। यह घटना कलिचुर गांव की है।

दरअसल गडबडी की शुरुआत उस वर्ष मई व शुरू के दिनों में ही हो गयी थी। हरिजनों और जातिवादियों पर संगठित हमले किए गये थे। उनके मकानों में शिंया, भेडा और बकरियाँ चुरा लियी गयी। अगर उन्हें कोई आयातन करना चाहता तो बाली की लाइन काट दी गयी।

मई 1975 में इन अत्याचारों में और तेजी आयी। शादी-व्याह के लिए हरिजनों द्वारा बनाये गये पडाला और शामियाना में आग लगा दी गयी। 21 मई को नौ हरिजनों के मकान जला दिये गये, उनमें रहने वाला का पीटा गया, उनके जेबरात और अनाज लूट गये और डडा तथा कुल्हाड़ा से प्रहार करके तीन लोगों का बुरी तरह घायल कर दिया गया। एक नौजवान को काफी पीटने के बाद तालाब में फेंक दिया गया।

यह प्यार 27 मई 1975 की थी। उसी दिन 'राष्ट्रीय छायाचित्र श्री जगजीवनराम ग्वालियर में अत्याचार निवारण सम्मेलन' में भाषण देते हुए हरिजनों से अहिंसा का पालन करने की अपील कर रहे थे। उन्होंने हरिजनों से हर अत्याचार दूरदाशन करने की अपील की और उन्हें आश्वासन दिया कि आने वाला दिन में उनके बर्तन को हिंसात्मक कार्यों का निशाना नहीं बनाया जायगा।

कर्नाटक की कुछ ऐतिहासिक विशिष्टताएँ हैं। कुछ दशक पूर्व, जय रामका नाम मसूर था, एक परमाणु जारी हुआ जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मणों का छोड़कर सभी जातियाँ पिछड़ी जातियाँ हैं। इसके फलस्वरूप एक प्रभावकारी गैर ब्राह्मण समुदाय बकबलिगा का काफी महत्व मिला। उनके और ब्राह्मणों के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हो गयी। 1956 में राज्य का पुनर्गठन के बाद निम्नलिखित जाति के लोगों की ताकत बढ़ी और अब निम्नलिखित रूप में हुआ। यह नामगर्भित गौड आयोग के फैसले का नतीजा था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव दिया कि आयोग द्वारा पिछड़ी जाति का जाति वर्गीकरण किया गया है वह मविधान के साथ धारा है।

1963 में राज्य सरकार एक बंदम और आग बढ़ गयी। इसने ऐलान किया कि 1 200 रुपय सालाना में कम आयवाले किसानों शिल्पियों, छोटे व्यापारियों, शारीरिक थम करने वाला और घरेलू नौकरों जैसे लोगों का भी पिछड़ी जाति का माना जायेगा। इस प्रकार ग्रामीण बकूलीया और लिंगायत महत्वपूर्ण हो गये। हरिजन और आदिवासियों की स्थिति पहले जसी बनी रही।

1972 में गठित ह्यानुर आयोग ने उस समय उल्लेखनीय काम किया जो उसने 3,55,000 व्यक्तियों और 200 गांवों का सर्वेक्षण करने के बाद एक सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट तैयार की।

इस रिपोर्ट के निष्कर्ष इस प्रकार थे

1) वर्ग विभेद एक वास्तविकता है। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ऐसे किसी उचित सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया गया कि किस आधार पर जाति और वर्ग सम्बन्धी विभेद का समाप्त किया जाना प्रभावित हुआ है।

2) सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर सदन को प्रभुत्व तथा निम्न जातियों की उत्पीड़ित अवस्था में साबित कर दिया कि जाति का मतलब वर्ग है।

3) शिक्षा और सरकारी नौकरियां में हरिजन और आदिवासियों का 70 प्रतिशत प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे किसी बंदम में ग्राम पालिका अडचन डाल देती। इसीलिए शुद्ध में केवल 18 प्रतिशत नौकरियां सुरक्षित की गयीं तथा और भी 32 प्रतिशत को सुरक्षित करना जरूरी था। उल्लेखनीय है कि ग्रामपालिका ने आयोग का पहले ही सूचित कर दिया था कि अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिए 50 प्रतिशत से ज्यादा स्थान सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

मुख्य मंत्री श्री देवराज जनन आयोग की रिपोर्ट का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद आयोग की सिफारिशों का लागू किया जायेगा। बुभाग्यवश नौकरियों में जायदाद की यात्रा का समाचार सुनने के बाद सभी घरों और समुदायों में प्रभावशाली लोग अपने-अपने समुदायों का पिछड़ी जाति घापित करने में व्यस्त हो गये।

आयोग ने 200 जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में चुना। इसमें राज्य की आबादी का 45 प्रतिशत हिस्सा और हिंदुओं का 51 प्रतिशत हिस्सा था। फिर भी कुछ जातियां आयोग के दायरे से बाहर रह गयीं। इस रिपोर्ट में मजदूर हिंदुओं में वर्गीकृत घणा बढ़ गयी। इसमें हरिजन और भी ज्यादा जमावदार हो गए।

मिश्रारिक्तों का लागू करने के लिए 18 मई 1977 का एक अधिनियम पारित हुआ। उस समय तब जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस के शासन-काल में

आयी रिपोर्ट की उपेक्षा कर दी गयी। जुलाई, 1978 में राज्य विधानसभा के एक कांग्रेसी सदस्य भीमना खडारे ने आयाग की रिपोर्ट में आग लगा दी। लिगायता तथा अन्य प्रभावशाली समुदायों के लोग रिपोर्ट का विरोध करने लगे। फिर भी 18 अप्रैल, 1979 की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि भूमि सुधार, ऋण राहत, बधुआ मजदूर मुक्ति खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि तथा अन्य प्रशमनीय कदम उठाये गये।

अप्रैल 1976 में कानून मंत्री श्री हवानूर की पहल पर मसूर जिले में 12,250 और समूचे राज्य में 24,500 मजदूर मुक्त किये गये। लेकिन उनकी आर्थिक समस्याएँ आसानी से हल होने वाली नहीं थी, क्योंकि उनके भूतपूर्व मालिकों ने उन्हें खेतिहर मजदूर रखने से इकार कर दिया था।

1979 की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि शिमोगा जिले में 40,000 से अधिक जीया हैं।

कनाटक की स्थिति अच्छी नहीं है। जीया लोग को वही आने जाने की आजादी नहीं है। 1966 में माडया जिले के मददुर गांव की एक औरत चिन्नम्मा ने अपनी बहन की शादी के लिए 300 रुपये का कज लिया था। इस कज के कारण वह जीया बन गयी। वह 1976 में एक बार अपनी बहन से मिलने गयी। जब वह लौट कर आयी तो उसके मालिक ने उसे गरम छड़ से दाग कर यह एहसास करा दिया कि जीया का मतलब क्या होता है।

वे दाग हमेशा चिन्नम्मा को उसकी हैसियत का एहसास कराते रहेंगे।

करन

बधुआ मजदूर प्रथा के सद्वर्तन में हम दो बातों पर ध्यान देना होगा, जो हर राज्य पर लागू होती हैं। प्रथम, हमें देखना चाहिए कि इनमें मालिकों का क्या है और दूसरे, गरीब भूमिहीन, आदिवासियों तथा हरिजनों के प्रति उनका रवैया क्या है? असल में मालिक बनने की यह मानसिकता है जिसने बधुआ मजदूरों को जन्म दिया है जिसमें किसी व्यक्ति की जमीन को जबरन अथवा छल-कपट के जरिए हड़पने, याज की वेतद भारी दर पर उसे कज देने की घटनाएँ शामिल हैं।

अंग्रेजों के शासन काल से ही अनेक राज्यों में बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त करने के कानून पारित किये। इस तरह के कानूनों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन्हें बर्ती लागू नहीं किया गया। और, उसे लागू करने का भी कोई लाभ नहीं था। जहरत की जमीन के स्वामित्व में तबदीली लाने की। अगर जमीन थोड़े लोगों के हाथ में बनी रहती है तो वे लोग जिनके पास कम जमीन है जयवा बिलकुल जमीन नहीं है जमीन के उन मुठ्ठी भर मालिकों के दमन और उत्पीड़न

का शिकार होते रहें। यह उत्पीड़न बधुआ मजदूर प्रथा का जन्म देगा। यदि यह बुनियादी ढांचा ज्या-का-त्या बना रहता है तो कोई भी राज्य सरकार, भले ही वह किसी पार्टी की ही क्या न हो किसी तरह का उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं ला सकती। पश्चिम बंगाल में यह बात देखी गयी है।

केरल में पिछले 20 वर्षों में वाम मोर्चे में सरकार में हिस्सा लिया है। मर कारी प्रचार। और विज्ञापना व जरिए इसने कई बार अपना ही अभिनय किया है। वास्तविकता क्या है? 1979 में किसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक लेख में इसकी दूसरी ही तस्वीर देखने को मिली। संयुक्त मोर्चा सरकार की प्रगतिशीलता का ढिंढारा पीटने वाले प्रचारों व कारण समाज के कमजोर वर्ग की दयनीय अवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी मिल सकी। सचचाई यह है कि पिछले 20 वर्षों में केरल में गाँव, हलक और विविध तरह के लाल रंग वाली वाम मोर्चा सरकार के बावजूद हरिजन का बहुमत आज भी गरीबी की रेखा में नीचे रहता है। एक लाख लोगों के लिए भूमि-व्यवस्था और आवास-योजना की बहु-चर्चित योजनाओं से शामका को महज प्रचार ही मिला है। भूमिहीन गरीब आज भी पहले की ही तरह जिंदगी गुजार रहे हैं।

अलेप्पी के पास अवलुकुनु नामक एक हरिजन बस्ती है जिसमें लगभग 160 व्यक्ति रहते हैं। प्रगतिशील केरल राज्य में यह बस्ती अंध जातियों की बस्ती से दूर बनायी गयी है। यहाँ हरिजन के साथ अकेले और सामूहिक बलात्कार की घटनाएँ आम बात हैं। अपने सामाजिक स्तरे, पैसे और पुलिस की मदद के बल पर अपराधी बेदाग निकल जाते हैं। हरिजन पुरुष जो जंगल में पड़े रहते हैं शिकायत की हिम्मत नहीं करते। इन शिकायतों से उन्हें प्याय नहीं मिलेगा—सचचाई तो यह है कि उल्टे अपराधी लोग इनसे बदला लेने लगे हैं।

कोचुपनु नामक एक हरिजन लड़की का उसके पिता की आँख के सामने 1979 में अपहरण किया गया और मनालाकुनु ले जाया गया जहाँ बदमाशों के एक गिरोह द्वारा उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किया गया। इसके फल-स्वरूप उसकी शांति की बातचीत टूट गयी। कुछ दिनों बाद पश्चिमी नामक लड़की का बचा लिया गया जब उसने और उसकी माँ ने गिरोह का मिलकर प्रतिरोध किया। 27 मार्च 1979 को भक्तन की झोपड़ी इसलिए जला दी गयी, क्योंकि उसने अपनी भतीजी को बदमाशों को सौंपने से इंकार किया था। चौदह वर्षीय सुगदम्मा को भी भयानक अनुभव झेलना पड़ा।

कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के कारण यह घटना प्रकाश में आयी। इस पर भी अलेप्पी के जिला कलेक्टर ने तथ्यों का मानने से इंकार कर दिया। बाद में वह एक पुलिस दल लेकर घटनास्थल पर पहुँचे।

पुलिस द्वारा धमकाव्य जान के बाद भी हरिजन ने कोई बात नहीं बतायी।

क्लकटर ने दिखावे के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया।

बेदर में जिन दिनों जनता पार्टी की सरकार थी कम्युनिस्ट संसद सदस्य गोविंद नाथर कई दिनों के विज्ञापन के बाद 1978 में केरल से नई दिल्ली गए और वहां उन्होंने दो घंटे का अनशन किया। मार्च-अप्रैल 1979 में अवालु कुन्नु के हरिजनो पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ किसी दूसरे कम्युनिस्ट नेता ने इतना भी शारीरिक कष्ट उठाने की कोशिश नहीं की। उन दिनों केरल के मुख्य मंत्री भी कम्युनिस्ट थे। इसके अलावा केरल सरकार यह दावा भी करती थी कि उसके शासन-दाल में हरिजन बहुत खुश हैं।

इस तरह की घटनाओं से पता चलता है कि सरकारी पंचार और असली स्थिति के बीच कितना फर्क है।

कन्नानूर जिले में उत्तरी वायनाड में और कोजीकाड जिले में दक्षिण वायनाड में तथा मालापुरम जिले में बहुआ मजदूर प्रथा का काफी चलन है। वायनाड में पनियां और अदियानों को जमींदारों द्वारा बहुआ मजदूर बनाकर रखा जाता है। ये दोनों जनजातियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं। जमींदारों को गौदन कहा जाता है। ये लोग कर्नाटक में आये थे और जंगली क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद इन्होंने पनियां को से बहुतों को मजदूर बनाया। एक समय ऐसा भी था कि जब पनियां को कुछ रुपये लेकर खरीदा-बेचा जाता था।

आज भी पनियां और अदियान अद्वितीय स्थिति में हैं। बल्लीयूर कावू के समारोह के दौरान गौदन लागू प्रत्येक परिवार का 25 से 30 रुपये तक देते हैं। जो परिवार इस राशि का स्वीकार कर लेता है उस अपने सभी सदस्यों के साथ उस जमींदार के क्षेत्र पर बिना कोई मजदूरी लिए एक साल तक काम करना पड़ता है। इस वजह से बल्लीयूर कावू पानम और निलपूमानम कहा जाता है। जो अपना धर्म नहीं दे सकने वाले व्याज सहित पैसे वापस करने पड़ते हैं। बहुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति के लिए बधित धर्म पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के पारित किये जाने के बाद यह नियम खत्म हो गया।

लेकिन 1976 में प्रकाशित अखबारी खबरों से पता चलता है कि इस प्रथा का फिर भी काफी प्रचलन था। दो दशकों तक एक के बाद एक वाम मोर्चा की सरकारें बनीं, लेकिन इस दिशा में कोई आवश्यक कदम उठान में वे हमेशा नाकामयाब रही। दरअसल इस बुराई को बर्तनी में नहीं दिया गया। केरल और पश्चिम बंगाल के उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि केवल वाम मोर्चा सरकारों के मता में आने से ही जमींदारों का यग चरित्र नहीं खत्म होता। उह गता है कि इन सरकारों में उन पर कोई प्रतिबल असर नहीं पड़ने वाला है।

लक्षदीव

1968-69 की एक सरकारी रिपोर्ट में बताया गया है कि ऋण सराधान एवं ऋण अनुदान अधिनियम, 1964 में लक्षदीव मिनीकाय और अमनतीव द्वीपों के लिए पारित हुआ। 1 अक्टूबर, 1968 से इसे लागू किया गया। ऋण का परिमाण कम करने तथा बजट का भुगतान करने के लिए सरकारी तौर पर उसे उधार देने के बारे में एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया।

यहाँ पर नदपू प्रणाली का प्रचलन था। इस प्रणाली के जगिए रैयता को जमींदारों के खेत पर बिना मजदूरी लिये काम करना पड़ता था। 1965 में पारित एक कानून द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और 1968 में दम कानून को लागू किया गया।

1971-72 और 1972-73 की रिपोर्टों से पता चलता है कि केन्द्र शासित लक्षदीव में यह प्रथा अब खत्म हो गयी है।

मध्य प्रदेश

शहडोल, सतना और वस्तर जिला में बहुआमजदूर प्रणाली का काफी प्रचलन है। इनमें से प्रत्येक जिले में इनकी संख्या चालीस हजार से अधिक है। बिलासपुर सरगुजा निदिशा और रायगढ़ जिला में से प्रत्येक में बीस हजार से भी अधिक बहुआमजदूर हैं। बाताघाट छतरपुर मनुवा, सागर, रोना, गुना और मुरना जिला में से प्रत्येक में इनकी संख्या दस से बीस हजार है। धार इंदौर, रायसन रतलाम सिहोर शाजापुर, खरगोन, उज्जैन, ग्वालियर और शिवपुरी में से प्रत्येक जिले में बहुआमजदूरों की संख्या पाँच से दस हजार है।

बेतुल, पूर्वी निमाच जबलपुर, रायपुर छिन्वाड़ा, टीकमगढ़, मदनसौर और देवदास जिला में से प्रत्येक में पाँच सौ से पाँच हजार तक बहुआमजदूर हैं।

1960-61 की एक सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि आजादी से भी पहले से विध्य प्रदेश और ग्वालियर में महिदारी नामक बहुआमजदूर प्रणाली प्रचलित रही है। अगर महिदार भागों की कोशिश करता था तो उसे पकड़ कर उसके मालिक तक पहुँचा दिया जाता था। यह प्रणाली आजादी के बाद समाप्त कर दी गयी, लेकिन शिवपुरी गुना और दरिया में शहरिया जानि के लोगो के बीच यह प्रणाली अभी भी प्रचलित है।

महिदार खुद लिये हुए कच्चा का शिकार बनता है और उस मामूली-मी राशि पर किसी तरह काम चलाते हुए मजदूरी करनी पड़ती है। वह दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, भले ही किसी अन्य काम में उसे ज्यादा पैसे कमा न मिलें।

हजिजन लोग कम उम्र में ही अपने बच्चा की शादी कर देते हैं। शादी के

लिए उह महाजन से पसे कज के रूप मे लेने पडते है। उन मामूम नडका को जिनके कारण कज लना पडा है, महिदार बना दिया जाता है और मालिका के खेत पर भेज दिया जाता है।

1961 62 की एक रिपोर्ट म बताया गया है कि गोड जनजाति के लोगो को बिना कुछ नियो काम करना पडता है—कि हो कि हो मामलो म उह काम के बदले खाने को मिल जाता है।

1962 63 की रिपोर्ट म महिदारी प्रथा के बारे म अपेक्षाकृत विस्तृत जानकारी दी गयी है। एक महिदार का तब तक काम करना पडता है जब तक उसका कज चुकना न हो जाये। उसे प्रतिदिन तीन किचोश्राम अनाज मिलता है और उसके जलावा रोज की खुराक तथा सात मे एक जोडा कपडा भी प्राप्त होना है। यह प्रणाली शिवपुरी गुना और दतिया जिला क शहरी समुदाय क बीच ज्यादा प्रचलित थी। इसी तरह की प्रथा बिंध्य प्रदेश और महाकोशल म भी रही है। शहडोल जिले म इस प्रथा के कारण काल जाति के लोगो तथा अगरीव हरिजनों को बहुत यातनापूर्ण जीवन बिताना पडता है। यहा इस प्रथा को हरवाही हाली कहत है। हरवाहा को बहुत कम मजदूरी मिलती है। अस्सो रुपय या सो रुपय का कज चुकना करने के लिए उह पट्टह से जटठारह बप तक मजदूरी करनी पडनी है। काम करन म इतना करन पर उह पीटा जाता है और मूल राशि का दागुगी रकम उनसे वसूली जाती है।

मिलासपुर जिले म इस प्रथा को कमिया कहत हैं। एक कमिया को होनी के पांचवें दिन से काम पर लगाया जाता है। यह अनुबंध एक साल के लिए होता है। उसे चालीस स साठ रुपये तक का भुगतान किया जाता है। उसे प्रतिदिन ढाई किलोग्राम धान भी मिलता है। नकद राशि और धान के मूल्य को यदि मिलाकर देखें तो उह साल भर म एक सौ चालीस रुपये से एक सौ पचास तक की राशि मिलती है। इस पैसे से कोई भी कमिया अपने परिवार क खच नहीं चला सकता। वह अगली होली तक काम करता रहता है। साल भर म उसे केवल चार छुट्टियाँ मिलती हैं। अनेक कमिया भयना और गाड जनजातिया क पाये जाते हैं।

1965 66 मे एक रिपोर्ट सामने आयी जितम देश के विभिन्न भागा म और खासतौर स मध्यप्रदेश तथा मद्रास म प्रचलित एक अजीबोगरीब प्रथा का उल्लेख किया गया था। इसके अनुसार किसी भी सवण हिंदू की मृत्यु होने पर अनुमचित जाति के किसी व्यक्ति का चिता तयार करने का काम दिया जाता था। जब तक साश जल नहीं जाती थी उसे लगातार ढान बजाते रहना पडता था। यह काम क बदले उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती थी।

1971-72 और 1972 73 म प्रकाशित रिपोर्टों म उल्लेख किया गया था

वि रतलाम, मुर्ना शबुआ और मदसौर जिनो में एक भीमा तब बधुआ मजदूर प्रणाली का प्रचलन है, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में यह प्रणाली खत्म हो चुकी है।

हरिजन और आदिवासियों के प्रति मध्य प्रदेश के सवण हिंदुओं का क्या रवैया है?

10 नवम्बर 1975 के समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर से इन क्षेत्रों की बड़ी दुखद तस्वीर सामने आती है। छत्तीसगढ़ जिले के ससबल गांव के एक धनी जमींदार शिवराम कुबेर न पुत्र की प्राप्ति के लिए अनर्हित सधावन नामक एक आदिवासी लड़के को विभी देवी को बलि चढ़ा दिया। इस जिले की विचित्रता यह है कि सवण हिंदुओं में भी ऐसे अधविश्वासों का प्रचलन एक आम बात है। अपनी गुप्त इच्छाओं की प्राप्ति के लिए आदिवासी लड़कों को बलि चढ़ाये जाने की अनक घटनाएँ यहाँ सुनने का मिलती हैं।

मुख्य मंत्री के अपने जिले दवास में 26 अगस्त 1977 को अनेक हरिजनों के मकान जला दिये गये। 25 फरवरी 1978 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि 1977 में माच और नवम्बर माह के बीच राज्य में 105 हरिजनों की हत्या की गयी। अगस्त 1977 में एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसमें सवण हिंदुओं ने हरिजनों के मैदानों में अपने मवेशी छोड़ दिये और खड़ी फसल को बरबाद कर दिया। हरिजनों के विरोध करने पर बड़ी बेशर्मी से उन्हें मार डाला गया।

5 अप्रैल 1978 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1978 में मध्य प्रदेश में 966 हरिजन और आदिवासी मारे गये। इसमें सवण हिंदुओं को इसके लिए दायी ठहराया गया था। लगभग एक हजार हरिजन और आदिवासी औरतों की बलात्कार का शिकार होना पड़ा। कौन भी जिला इस तरह के अपराधों से मुक्त नहीं था। शबुआ जिले में 189 और बस्तर जिले में 174 लोग मारे गये। इसमें यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा कि 1977 से पूर्व इस राज्य में हरिजन और आदिवासियों की हत्याएँ नहीं हुईं।

इस तरह की घटनाएँ ही बधुआ मजदूर प्रणाली की पण्डूमि का निर्माण करती हैं। 1978 में सतना जिले के छुवरानोठू गांव में बादू नामक एक बोल बुद्ध रहता था जिसकी उम्र 32 वर्ष थी (उत्तर-पूर्व बिहार में बोल नामक एक जनजाति है। मध्य प्रदेश में बोल जाति के लोग अनुसूचित जाति माने जाते हैं)। सतना के इस क्षेत्र में बधुआ मजदूरों का लगुआ रहता था।

बादू ने बताया भी लगुआ थे। जिस समय बादू सात साल का था, एक शुभ दिन में (नव साल के अवसर पर अथवा बड़े बरसान पर्व के समय) उसे उपहार के रूप में कुछ नये कपड़े और एक जाड़ी चप्पल प्राप्त हुए। उसने राधा उग अपनी पीठ पर बठा कर शान्तिनाम कुरमी नामक जमीन्दार के घर ले गया। बादू हक्का

बकवा था। वह जमींदार के सामने रठा था और खाने के लिए उसे कुछ सामान दिया गया था। सचमुच कादू के लिए यह बड़ा शानदार दिन था। फिर उसने देखा कि जमींदार शांतिदास ने उसके चाचा का 150 रुपये दिये।

इसके बाद से ही कोदू लगुआ बन गया। उसके चाचा उसे लेकर एक दूसरे मकान पर गए और वहाँ उन्होंने एक व्यक्ति को सौ रुपये दिये। एक पाँच बप की लडकी के साथ कादू की शादी हुई। उसी दिन कोदू पति और लगुआ दोनों बन गया। उसके जमे अय लागा की जिंदगी भी उस दिन बड़े नाटकीय ढंग से बदल चुकी थी।

उम बच्ची उम्र में कादू का लगुआ शब्द का जथ नहीं मालूम था। अत्र 32 बप की उम्र में वह इस शब्द का भली भाँति समझ चुका है। अपना जसली नाम वह भूल गया है और लगुआ के रूप में ही उसकी पहचान बच रही है। 25 बप की बड़ी मेहनत से भी एक सौ पचास रुपये का कज चुकता नहीं कर पाया है। एक बक्क का खाना खाकर वह सबर से रात तक काम करता है। जमींदार ने कज के बदले उसकी पत्नी का अपना गुलाम बना लिया है। कादू और उसकी पत्नी को मजदूरी के रूप में कुछ भी नहीं मिलता। उनसे बताया गया है कि कज उतारने के लिए बहुत पैसा की जरूरत है। दोनों को पता है कि यह कज कभी नहीं उतरेगा। उ ह गाँव छोड़न की भी इजाजत नहीं है।

(2) रतलाम कस्बे से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दलानपुर गाँव में बिजली है। राजपूत तथा अन्य सबण हिंदू जमींदार चमारा को हाली बनाकर रखते थे। बिजली का पंप लगने से खेती ग्राडी का काम और तजी से होने लगा। इसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए हालियों की कमी पड़ गयी और जमींदार लोग 1,500 से 2,000 रुपये तक कज देकर उह वधुआ बनान की कोशिश करने लगे।

हाली जाति का एक नौजवान थोडा शिक्षित था। वह कज के भुगतान का हिसाब रखन लगा। इससे जमींदारों के हाथ-पाव फूलने लगे। उह यह भय सतान लगा कि चमारा लोग भी अब अपन अधिकारों के बारे में सजग होन लगे। उन्होंने फसला किया कि दूसरी जगह के मजदूरों को लाकर काम दिया जाय और इन चमारों का सबक सिखाया जाये। उनके चारा ओर पहाडों और जंगलों में भील जाति के लोग रहते थे।

जमींदारों ने भीलों के पास अपने दलाल भेजे जिन्होंने इन भूखे और सक्की जादिसिया को कज, नौकरी और मकान दिलान का वादा किया। उनके आने से मजदूरों की सप्लाय में वृद्धि हो गयी और जमींदारों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। इन नये मजदूरों के रहने के लिए तमाम छोटी छोटी झापड़िया खड़ी हो गयी।

पजा भील को कौन मुक्त करायेगा ? 1976 में उसकी उम्र 22 बप थी।

उसके पिता जीवा भील न मोती जाट से 300 रुपये का बज लिया था और हाली बन गया था। जब उसका लडका बटा हुआ ता उसन रुपसिंह नामक राजपूत से 600 रुपये बज लिय, मोती जाट से लिया बज चुता किया और अपन बेटे को रुपसिंह के यहा हाली बना दिया।

सुद पजा न 6 वष के दौरान रुपसिंह स 700 रुपया और 460 किलाग्राम मक्का लिया था। इस प्रकार रुपसिंह ने पिता और पुत्र को 1,300 रुपय का बज लिया था। मक्का की कीमत 460 रुपय लगायी गयी थी। इस प्रकार बज की राशि 1,760 रुपय हो गयी। इस पर 24 प्रतिशत ब्याज लगा। इस प्रकार मूल राशि और ब्याज मिलाकर मुल 2,062 08 रुपय का बज हुआ। यह माना गया था कि रुपसिंह पहले दो वष तक पजा को 40 रुपय प्रतिमाह, तीसर वष 50 रुपये प्रतिमाह और चाथे वष से 65 रुपये प्रतिमाह वेतन के रूप म देगा। इस प्रकार छह वष मे पजा को 3 900 रुपये मिलते। उसे 2,062 08 रुपये वापस करन थे। पजा का कभी अपनी तनखाह नही मिली। यह मान लिया गया कि तनखाह का पसा कज म मुजरा हाता जा रहा है। खाता के मुताबिक पजा का 1,837 रुपये 92 पैसे और मिलन चाहिए थे, लेकिन जमीदार न वनाया कि उसके ऊपर अभी भी 1 000 रुपय का बज चढा हुआ है।

उसके अलावा पजा को प्रतिदिन 4 रुपये 50 पैसे की सरकारी दर स मजदूरी मिलनी चाहिए थी। छह वष म उसे 9 855 रुपये मिलने चाहिए थ। बज की राशि को काटन के बाद उस 7,792 रुपये 92 पैसे मिलना चाहिए था।

लेकिन न तो उसे पस मिलेंगे और न वह आजादी ही पायेगा।

रुपसिंह के अनुसार उसके ऊपर अभी भी एक हजार रुपये बज के रूप म हैं।

वह भील चार वष से फूलमिह का हाली है। उसने नकद और मक्का के रूप म 1 800 रुपये की राशि के बराबर बज लिया था। मक्का की कीमत प्रति क्विंटल 100 रुपये लगायी गयी थी। उसन 600 रुपये नकद लिये और 12 क्विंटल मक्का लिया था। उस प्रतिमाह 60 रुपया वेतन मिलना था जिसे बज के बदले मुजरा होना था। चार वष म बज का 2 880 रुपया चुकता हुआ, लेकिन बज अभी बना ही रहा। भुगतान न की गयी राशि के रूप म 100 रुपया अभी भी पडा दिखलाया गया। निरक्षर बहुरू न अपन मालिक से कभी इस सिलसिले म कुछ नही पूछा। हर साल वह एक सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगा ता है। बहुरू का कोई तनखाह नही मिलती। उसकी पत्नी दैनिक मजदूर के रूप म काम करती है और उसे प्रतिदिन पौन दो रुपये म द्वाई रुपये तक मिलते हैं। इसी वमाई पर चार सदस्या के परिवार का जियागी गुजारनी पडती है। एक सतिहर मजदूर 9 घंटे तक काम करता है लेकिन बहुरू को 16 घंटे काम करना पडता है। एक सतिहर मजदूर के रूप म उसे ओवरटाइम के लिए 4 50 रुपये या 5 25

रूप में मिलना चाहिए था। उसकी दैनिक आय 9 75 रुपये होती। आज भी, कानून विभाग के विद्वानों के अनुसार हालियों की स्थिति काफी ठीक है।

जमींदार लोग हालिया में फूट डालने के लिए कागज पर यह दिखाते हैं कि उनके कुछ साधियों को ज्यादा मजदूरी मिलती है और इस प्रकार तथाकथित कम मजदूरी पाने वाले दूसरे से ईर्ष्या करने लगता है। सच्चाई यह है कि किसी को ज्यादा पैसे नहीं मिलते। वज्र दिनादिन बढ़ता चला जाता है।

चूँकि भीलो को मामूली पैसे पर हाली रखा जा सकता है, चमार हालियों का बाजार खत्म हो गया।

बहुरू को बताया गया कि केन्द्र सरकार न हाली प्रथा समाप्त कर दे और राज्य सरकार ने सारे ऋण ऋद्द कर दिये। अब वह अपनी मर्जी के मुताबिक काम कर सकता है। उसने बड़े शांत भाव से जवाब दिया कि उनकी सरकार तो फूलसिंह है और उहान्त ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।

पंजा और उसके जैसे लोग अपने मालिक के अलावा और किसी की सत्ता को नहीं जानते।

9 फरवरी 1979 के समाचार-पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया था कि बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त किये जाने से संबंधित कानून को मध्य प्रदेश में उचित ढंग से लागू नहीं किया गया है। इस प्रथा को बर्नाये रखने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। अनुमूचित जातियाँ और जनजातियाँ के कमिश्नर ने रिपोर्ट दी थी कि वस्तर, रायगढ़ और जगली क्षेत्र के गाँवों में आदिवासियों का बिना मजदूरी दिये वन विभाग के लिए वर्ष में 140 दिन काम में लगाया जाता है।

बेगार नामक इस प्रथा को इसलिए लागू किया गया था, क्योंकि सरदार ने इन लोगों को जंगल की जमीन दी थी।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में अहमदनगर सचमुच बधुआ मजदूर प्रदेश है। यहाँ 40,000 से अधिक बधुआ मजदूर हैं। जलगाव, घुलिया और नासिक में इनकी संख्या उल्लेखनीय रूप से ज्यादा है। ये तथ्य 23 फरवरी 1979 के समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे।

1961-62 की एक सरकारी रिपोर्ट में यह रहस्योद्घाटन किया गया था कि थाने और नासिक में घोरकोली, कतकरी, बर्ली और भील आदिवासी बट अथवा बेगार नामक बधुआ मजदूर प्रणाली के शिकार हैं। व मुख्यतया मेतिहर मजदूर थे जिन्हें वज्र लेने के कारण बधुआ मजदूर बनने के लिए मजदूर किया गया था। प्रशासन के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा इस प्रथा को

समाप्त करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। दरअसल इन आदेशों का प्रसारित नहीं किया गया और आदिवासियों में संबंधित विभागों का अथवा जादिवसियों को इनकी कोई जानकारी नहीं थी।

1964-65 की एक रिपोर्ट 1 थान में प्रचलित व्यापक वधुआ मजदूर प्रथा का विस्तृत विवरण दिया। 22 रुपये में लेकर 300 रुपये तक के ऋण के कारण अनेक आदिवासी 3 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए वधुआ मजदूर बन चुके थे।

1971-72 और 1972-73 की सरकारी रिपोर्टों में दावा किया गया था कि महाराष्ट्र में वधुआ मजदूर प्रथा के होने का कोई प्रमाण नहीं है। इस विषय में कोई कानून नहीं था पर श्रम कानूनों के मुताबिक यह प्रथा ग़र कानूनी है।

ध्यान देने की बात है कि राज्य सरकार ने इस प्रथा के हटाने की बात स्वीकार नहीं की। लेकिन इससे हरिजन और आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में अपनी जड़ जमा ली थी। जो लोग गरीबी की रस्ती के नीचे रहते थे, वे बच लेने के लिए मजबूर थे।

इस तरह के लोग अल्प थे और सबके हिंदुओं से आतंकित थे। उन्हें गुलाम बनाना आसान था। राज्य सरकार के दावे पर विचार किया जा सकता था यद्यपि हरिजन और आदिवासी सम्मान के साथ जीवन बिता रहे होते।

लेकिन उन्हें पेट भरने शादी ब्याह करने तथा अपने परिवार के मृत सदस्यों के अंतिम सम्कार के लिए बच के लिए भागते रहना पड़ता था। यदि उनके दावे में सच था तो दलित आदालत क्या शुरू हुआ?

1973 में डा० गोरे और शिरभान लिमचे ने अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के बीच एक सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण में पता चला कि अनुसूचित जाति के 90 प्रतिशत लोग गाँव की चौहद्दी से बाहर रहते हैं 50 प्रतिशत को कुछ पानी लेने की इजाजत है और 25 प्रतिशत को रेस्तराँ में खाने नहीं दिया जाता। जिन्हें रेस्तराँ में खाने की इजाजत मिलती भी थी उन्हें अलग बैठकर अपने लिए निर्धारित अलग प्लेट में खाना खाना पड़ता था। इनमें से अधिकांश भूमिहीन और गरीब थे।

15 मार्च, 1975 की एक खबर में बताया गया था कि किस तरह थान जिले के आदेगाँव के एक दूकानदार रतिलाल ने दो पुलिस कांस्टेबलों की मदद से एक आदिवासी युवती भगलीवाई के घर पर धावा बोला था। उसने उस युवती से कहा कि वह दोनों कांस्टेबलों के साथ सहवास करे। युवती के इस्वार करने पर उसकी झपड़ी जला दी गयी। 1974 से 1975 के बीच अखबारों का देखें तो हरिजन और आदिवासियों पर होने वाले इस तरह के अत्याचार की अनेक घटनाएँ मिलती हैं।

1976 में भूमि सेना ने थाने जिला के पालघर ताल्लुक में 100 वधुआ

मजदूरा से बातचीत की। इस सर्वेक्षण से जनक तथ्य प्रकाश में आय। एक सच्चाई का पता चला। भेंटकता ने, जो खुद भी आदिवासी था, देखा कि आदिवासी बधुआ मजदूर साहूकारों और महाजना से इतने आतंकित हैं कि उनके खिलाफ बज्रबान भी नहीं खोलते। वे सवण हिंदुओं से डरते थे। यदि वे इतने आतंकित थे कि अपनी बिरादरी के आदमी से भी कुछ नहीं कह पाते थे तो किस तरह वे दूसरों से कुछ कहते? इसलिए यह मानना गलत होगा कि चूकि वे खामोश हैं, इसलिए वहाँ बधुआ मजदूर प्रथा है ही नहीं।

राज्य सरकार ने इस मामले का ज्यादा महत्व नहीं दिया। 1977 के आस पास यह पाया गया कि बधुआ मजदूरों की सट्टा, खासतौर से कोलाबा, नासिक, धुलिया और चंद्रपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में बहुत ज्यादा है। कज लेने के मामले में अनक है। कभी कभी सरकारी दबाव के कारण कजदार व्यक्ति को सरकारी कज चुकता करने के लिए पैसे लेने पड़ते थे और इस प्रकार वह बधुआ मजदूर बन जाता था। रत्नागिरि में अनेक दलित और कुबी बधुआ मजदूर थे।

पालघर ताल्लुक के कुछ बधुआ मजदूरों के उन्नाहरण से यह तस्वीर कुछ साफ उभर सकेगी।

(1) गावाड गांव में जेठया राघो बनगा अपनी पत्नी के साथ पिछले 13 वर्ष से महाजन का बधुआ मजदूर था। उस यह नहीं पता था कि—

(क) उसने कितना कज लिया था?

(ख) ब्याज की दर क्या है?

(ग) कितना भुगतान हो चुका है और कितना बाकी है? उसे केवल इतना पता है कि अपनी शादी के समय उसने कौन-कौन से सामान लिए थे। सामानों की सूची इस प्रकार है—

सामान	मात्रा	1965 में मूल्य	1977 में मूल्य
धान	10 मन	150 रुपये	500 रुपये
घोती	एक	10 रुपये	20 रुपये
कुर्ता	एक	7 रुपये	15 रुपये
साड़ी	तीन	45 रुपये	75 रुपये
अय कपड़े	तीन	9 रुपये	15 रुपये
नकद	—	12 रुपये	12 रुपये
योग		233 रुपये	637 रुपये

इस कज ने दा लागा को गुलाम बना लिया।

(2) 1969 में बिरात गांव के किशन गनपत बालेकर ने महाजन साड़ी, तीन कपड़े, एक कमीज और एक घोती ली थी। इन चीजों की

90 रुपये से अधिक नहीं थी। वह और उसकी पत्नी आठ वष तक बधुआ बन रहे। उसे यह नहीं पता है कि कब तक कज चुकता होगा और कब तक वह गुलाम बन रहूँगा। उह बाई मजदूरी नहीं मिलती। उह महज रोज का खाना, चाय आर बीड़ी मिलती है। साल में उह दा लेंगोटी, दा जाधिय, दा ब्याउज और दा साडी भी मिलती हैं।

(3) गावद्या गांव में काशीनाथ बिटठल तुम्बादा और उसकी पत्नी 197 रुपये के ऋण के कारण 12 वष से बधुआ बन हुए हैं।

अमृत लदावा बडक न 400 रुपये कज लिय थे आर 13 वष से बधुआ है। रघु पाण्डुपवार 500 रुपये के ऋण के कारण 16 वष से मालिक की गुलामी कर रहा है। बेंगवाव में बल्वा चैतय मादर और उसकी पत्नी न 300 रुपये के एवज में एक बरारनाम पर जंगूठे का निशान लगाकर 21 साल तक गुलामी करने की पास लगा ली। 9 साल गुजर चुके हैं। अभी 12 वष और गुलाम रहना है। बिटाल जानु ने 300 रुपये का कज लिया था और अपनी पत्नी के साथ 21 वष तक गुलामी करने की रजामदी दे दी। उसे यह भी पता नहीं है कि कितने वष बीत चुके। लौद्या लट्या पाडकर न 800 रुपये अपनी शादी के समय लिये थे। वह अपनी पत्नी के साथ बधुआ मजदूर के रूप में आठ साल बिता चुका है। इस बात पर सहमति हुई थी कि उह प्रतिदिन 450 ग्राम चावल और प्रतिवष 20 रुपये दिये जायेंगे। रुपये को कज में चुकता किया जायेगा। इस प्रकार वह चालीस साल से गुलाम है। बेचारे लौद्या न धीमती गांधी के बीस-सूत्री कार्यक्रम पर यकीन कर लिया और राहत के लिए अपील की, लेकिन उसकी अपील पर कोई जवाब नहीं आया।

(4) विश्रामपुर गांव में रमेश बाबू मादर न 111 रुपये 75 पस कज लिये थे। उसके बदले में उसे और उसकी बहन का बधुआ मजदूर बनना पड़ा। 9 महीने की गुलामी के बाद एक दिन किसी लोहार के जवसर पर वह काम पर नहीं जा सका। इससे नाराज होकर महाजन न उसे और उसका बाप को बहुत पीटा। रमेश डर गया और भाग खड़ा हुआ। उसके मां बाप न महाजन का 300 रुपया और 150 रुपये मूल्य का तीन मस धान देने को कहा लेकिन महाजन न यह कहकर लेन से इकार कर दिया कि उस 1,200 रुपया पाता है। 1975 से ही रमेश भाग गया है। उसने 15 नवम्बर 1976 को तहसीलदार के नाम एक अर्जी देकर राहत की मांग की। मई 1977 तक उसकी अर्जी का कोई जवाब नहीं आया था। रमेश अपनी जान बचाने के लिए गांव से बाहर ही है।

राज्य सरकार ने थान जिले के बधुआ मजदूरों को छुड़ाने की कोई काशिश नहीं की। दिसंबर 1976 में भूमि सेना न तहसीलदार के पास 120 अर्जियां दी थीं। लेकिन प्रशासन न कुछ भी नहीं किया। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां

पुलिस भाग हुए बधुआ मजदूरों का पकड़कर पहले पीटती है फिर उन्हें उनके मालिकों के हवाले कर देती है। यहाँ पुलिस जमींदारों के हितों की रक्षा में लगी रहती है।

उडीसा

उडीसा में खामतौर में कोरापुट जिला और गजाम जिला में गांधी प्रणाली देखन का मिलती है। प्रत्येक स्थान पर इसका स्वरूप भिन्न है। ग्रहण की राशि 50 रुपये से 200 रुपये तक है। गोठिया को प्रतिवर्ष 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक मिलते हैं तथा उन्हें खाना या अनाज और कपड़ा दिया जाता है। उन्हें बड़ी खरीदों के लिए भी प्रति सप्ताह 6 से 12 पैसे तक दिया जाता है। उनके मालिक उन्हें ग्रामीण पुनर्वास कार्यों में भी लगाते हैं जो राज्य सरकार समय समय पर चलाती रहती है। उनके वेतन उनके मालिकों की जेब में चले जाते हैं। हालांकि गोठिया प्रणाली काफी प्रचलित है पर यहाँ टडामुलिया और दारोमसिया प्रथा का भी चलन है।

केन्द्रीय आदिवासी विभाग ने 1962 में काय और पराजा आदिवासियों वाले नौ गांवों का सर्वेक्षण किया था। इससे पता चला कि कुल आबादी में 10 प्रतिशत गोठिया हैं। गुलामी की अवधि 10, 19 और यहां तक कि 30 वर्ष भी है। एक व्यक्ति ने 60 रुपये उधार लिये और उसे गोठिया बनना पड़ा और बाद में उसके दाना घट भी गोठिया बन। इन्होंने कुल 22 वर्ष तक गुलामी की।

ध्यान देने की बात है कि 1948 में वन एक कानून के जरिए उडीसा में ग्रहण के एवज में गुलामी की प्रथा समाप्त की जा चुकी है।

इसके अलावा एक और प्रथा का चलन है। जब कभी किसी बड़ी परियोजना का निर्माण-कार्य शुरू होता है तो ठेकेदारों के एजेंट जिन्हें खानादार या मरदार कहा जाता है, 25-30 मजदूरों का एक दल बनाते हैं जिनमें 12-13 साल की लड़कियां भी होती हैं। ये एजेंट इन मजदूरों की मजदूरी पहले ही ठेकेदार से लेते हैं, मजदूरों का पस कभी नहीं मिलता। इन पैसों का रख रखा जाता है और काम खत्म होने पर देन का वादा किया जाता है। एजेंटों का यह डर रहता है कि यदि मजदूरों के हाथ में पैसा आ जायेगा तो वे घर लौट जायेंगे।

इन अभाग मजदूरों को डाइन मजदूर कहा जाता है। काम की समाप्ति पर ठेकेदार एजेंटों में हिस्सा करता है, न कि मजदूरों में। नतीजा यह होता है कि मजदूरों का ठेका समाप्त होने के बाद भी रुके रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास घर लौटने का पस नहीं होता। उनमें जिन भुगतान होता है ता रनव गिवट का अलावा उन्हें नन्द के रूप में मामूली राशि दी जाती है। उनका दाना तराई से घाटा होता है—पैसे का मामले में भी और बिना किसी काम के समय बरबाद

करने से। काम के दौरान उनकी सेवाएँ समाप्त किए जाने पर भी कोई मुआवज़ा नहीं मिलता।

उनके काम के घंट भयंकर होते हैं। वे सवेरे छह बजे से रात के बारह बजे तक काम करते हैं—बीच में एक घंटे के लिए खान की छुट्टी मिलती है।

कोड़े लगाने की घटना तो आम बात है। इतने चोट से कुछ मर भी जाते हैं। जा भगान की कोशिश करते हैं उन्हें पकड़े जाने पर और भी बबरता का सामना करना पड़ता है। अनेक डाइन मजदूर उड़ीसा से बाहर काम करते हैं। खुदा सब डिवाइजन के पांच मजदूरों की पिटाई के कारण मृत्यु हो गयी। 1974 और 1975 में कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश में काम करते समय 15 से ज्यादा मजदूर मारे गये।

1976 में उड़ीसा सरकार ने डाइन मजदूरों का काम पर लेने, ठेके की शर्त तय करने और मजदूरों की दर निर्धारित करने के बारे में एक कानून पारित किया। यह कानून कभी लागू नहीं किया गया। डाइन प्रथा जारी है और यह सचमुच दुख की बात है कि अनेक लोगों का यह पार्श्विक प्रथा ही जीने का एक मान उपाय देती है। इसीलिए वे आज भी खातादार के आन पर उसके प्रस्तावों को खामोशी से सुनते रहते हैं। खातादार उन्हें तीन महीने का ठेका देने, 210 रुपये मजदूरी तथा घर लौटने के लिए रेलवे भाड़ा देने का वायदा करता है। उन्हें यह भी पता है कि मजदूरों के रूप में उन्हें बहुत कम पैसे दिए जायेंगे। खाना और रेलभाड़ा के अलावा वे कोड़ा की भी उम्मीद करते हैं। वे जानते हैं कि उनमें से कुछ मर भी जायेंगे। जिन्होंने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा वे कश्मीर, दिल्ली या मध्य प्रदेश में एक अजनबी मौत के शिकार बनेंगे। उन राज्यों के समाज का नगा चेहरा बारीकी से देखने की जरूरत है जहाँ वधुआ मजदूर प्रथा का जबरदस्त चलन है। बगलत दमन के बिना वधुआ मजदूर प्रथा का अस्तित्व नहीं हो सकता।

फरवरी 1976 में आयोजित नारायणगढ़ शिविर में इसी मुसले पर विचार किया गया। सबलपुर में स्थानीय आदिवासियों का ज़मीन नहीं मिलती। उनको बड़ा देते समय बड़े बेतहाशा ब्याज लेते हैं। यदि वे भुगतान नहीं कर पाते हैं तो सरकारी सस्थाएँ उनकी ज़मीनें जब्त कर लेती हैं और बेच देती हैं, हालाँकि आदिवासियों की ज़मीन को खरीदना बेचना सर-कानूनी है। वन-विभाग के लिए जो आदिवासी बंदू की पत्तियाँ इकट्ठी करते हैं, उन्हें दैनिक मजदूरी के रूप में दो रुपये मिलते हैं। उड़ीसा में न्यूनतम मजदूरी रानून के अनुसार कम-से कम मजदूरी चार रुपये होती है।

बलकट और आस-पास के गाँवों में आदिवासियों की ज़मीन को तहसीलदार सर-आदिवासियों में बाँटना है। इस तरह की ज़मीन—जिसे परंपरा में भूमि कहा

जाता है—आदिवासियों के लिए ही है। 14 गांवों में, जहां खोमर नामक आदिवासी रहते हैं सारी जमीन का गर आदिवासियों ने हड़प लिया है।

पुणे जिले में पिंपली खानान्तगत मंगलपुर गांव में हरिजन मजदूरों और सवण हिंदुओं की बस्ती के बीच एक बाड़ा लगाया गया है। पांच मंदिरों में से चार खासतौर से सवणों के लिए हैं। सवणों के बंधुओं से हरिजन पानी नहीं ले सकते। मजदूरों में दावग है—होलिया और माधारण मजदूर। होलिया दावग के मजदूर बंधुआ मजदूर है। किसी होलिया को भू-स्वामी 200 से 300 रुपये और ढेढ़ बीघा सेत उधार देता है। इससे एक वर्ष में उसे पूरे साल उस व्यक्ति के खेत पर काम करना पड़ता है। लगभग सभी भू-स्वामियों के यहां होलिया मजदूर होते हैं।

पुरुष और महिला मजदूरों को प्रतिदिन नमक ढाई रुपये और दो रुपये मिलते हैं। लगभग सभी पर बज्र चढ़ा होता है। ब्राज की दर 100 प्रतिशत साताता है। आश्चर्य नहीं कि बज्र लेने वाला बंधुआ बन जाता है।

(1) जोनु येहाना नामक हरिजन विमान के परिवार में सात सदस्य हैं। उसके पास एक छोटी झोपड़ी और गोशाला है। उसके पास अपनी ढेढ़ बीघा जमीन है जिससे वह लगभग एक बिंदल धान पैदा कर लेता है। उसने बटाई के आधार पर भू-स्वामी से और ढेढ़ बीघा जमीन तथा इस पर होने वाले खर्च के लिए 250 रुपये नकद लिये थे। फलस्वरूप उस बिना मजदूरी लिये भू-स्वामी की जमीन पर आधा महीना काम करना पड़ता है और शेष दिन वह अपने खेत पर काम करता है या सेतिहर मजदूर बना रहता है। जानु को उन तमाम कानूनों की जानकारी नहीं है जो उसके जैसे लोगों के लाभ के लिए बनाए गए हैं। उसे केवल यही पता है कि सहकारी संस्था के पास कर्ज के लिए वह जब भी गया उसे निराश हाकर लौटना पड़ा। जोनु कभी ट्रेन पर नहीं चढ़ा। उस बचल इतना ही पता है कि उठीसा उसकी जन्मभूमि है और इंदिरा गांधी सारी दुनिया की नेता है।

वह जानता है कि सरपंच और ग्रामीण स्वयंसेवकों का सब पर शासन है लेकिन न गरीबों के उत्थान के रास्ते की सबसे बड़ी खानटे है। उस पता है कि उसके गांव में 75 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक के पास 600 बीघा जमीन है। मिट्टी का तेल, चीनी और गेहूँ बचन वाली दुकानें भी हैं, पर जोनु ये चीज नहीं खरीद सकता। वह सोचना है कि अगर वह डाढ़न मजदूर बन जाये और घर छोड़ दे तो उसकी जिंदगी बहुत ही जायगी। लेकिन अपने परिवार को कैसे छोड़ें ?

अजला के जमान में देसी रजवाडों में बंधुआ मजदूर प्रथा की जगह बेठी, बगार और बहवरा जैसे कई नाम थे। 1923 और 1929 में कानून के जरिए इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन इन जिलों में अन्य अलग नामों में यह प्रथा

बनी रही।

इसके अलावा एक गुटिया प्रणाली थी जिसमें गुटिया के नाम से प्रचलित जमींदार मजदूरों को कच्चा देकर अनिश्चित समय के लिए उन्हें वधुआ मजदूर बना लेते थे। 1956 में यह प्रथा भी समाप्त कर दी गयी, पर व्यवहार में इसका कोई असर नहीं पड़ा। दूरदराज के गावा में गुटिया जमींदारों ने वेनामी जमीनों खरीद ली और प्रत्येक के पास 400 से 500 बीघा जमीन है। वे सब हिंदू हैं, पचायतो के नेता हैं और बड़े-बड़े अक्सर उनके दोस्त हैं। वे हरिजना और आदिवासियों की जमीनें हड़प लेते हैं। अनेक मामला में उनके वधुआ मजदूर अगर उनकी इजाजत लिये गांव में बाहर नहीं जा सकते।

(2) घाटपाडा गांव का रसिया दीप एक आठ वर्ष का हरिजन लड़का है। एक वर्ष की उम्र से ही वह एक सबण हिंदू के यहाँ वधुआ मजदूर है। उसकी सालाना तनखाह 10 रुपये है। उसे दो पैट और एक कमीज भी मिलती है। उसे दिन में दाना पहर खाना मिलता है जिस पर उसका मालिक का एक रुपया से ज्यादा खर्च नहीं होता। फिर भी उस हफ्ते में दो दिन खाना नहीं दिया जाता। वह हर रोज 12-14 घंटे काम करता है।

(3) सीमाचल पतरी एक हरिजन है। उसकी उम्र 30 वर्ष है और वह समीगढ़ ब्लॉक के एक गांव में रहता है। वह पिछले 15 वर्ष से वधुआ मजदूर है और सबण हिंदू है। उसकी सालाना तनखाह 200 रुपये है और साथ में उसे तीन सेट कपड़े भी मिलते हैं। उसे हर सप्ताह बहुत घटिया किस्म का 21 किलो धान मिलता है। इसे कूटन-बनान के बाद वह साढ़े दस किलो ग्राम चावल पिला लेता है। इस तरह का चावल उधर के गांव में एक डेढ़ रुपये किलो मिलता है। फरवरी में जून तक उसके पास कोई काम नहीं होता। इन चार महीना में उसे धान भी नहीं मिलता।

परिवार के एक सदस्य को मामूली से पैसे देकर पूरा परिवार को गुलाम बनाने की प्रथा का उड़ीसा में काफी चलन है।

उड़ीसा भारत का हिस्सा है। गरीबों का गुलाम बनाने के सभी हथियार यहाँ इस्तमाल किये जाते हैं।

कानूनी और सरकारी नियम यहाँ हरिजना तथा आदिवासियों के लिए नहीं है।

राजस्थान

राजस्थान के विभिन्न जिला में वधुआ मजदूरों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है

जिला

बालवाड कोटा

बूंदी, सवाई माधोपुर उदयपुर,
गगानगर अजमेर भीलवाडा

भुधुनू

नागौर शिकार टाक, चित्तौडगढ़

सह्या

10 000 20 000

5,000 10,000

500 5 000

कुल बधुआ मजदूरों में से 56 प्रतिशत इस प्रथा को समाप्त करने से
संवधित विधायक के पारित किये जाने के तीन वर्ष के भीतर बधुआ बनाये गये।

(1) उदयपुर जिले के ब्राह्मण की हुंदार गाँवों में जीवा नामक 20 वर्षीय
एक युवक रहता है जो एक सागरी है अर्थात् बधुआ मजदूर है। जब वह पाँच
वर्ष का था उसके पिता की मृत्यु हो गयी और उसकी माँ किसी दूसरे आदमी के
साथ चली गयी। जीवा के पास कुछ बीघे ज़मीन थी जिसे उसके चाचा ने
जातदार रूपसिंह को 100 रुपये में बेच दिया था। फिर उसने एक ब्राह्मण
जातदार शिवराम से 80 रुपये क़र्ज लिया और जीवा को उसका सागरी बना
दिया। तनरवाह की भी कुछ बात हुई थी पर जीवा को कभी कोई तनरवाह
देखन को नहीं मिली। उसने शिवराम के सागरी के रूप में तीन साल बिताये।

जल्दी ही उसके चाचा की और रुपया की ज़रूरत पड़ी। उसने कुबेरलाल
नामक एक ब्राह्मण से 200 रुपये उधार लिये, शिवराम का पसा चुकता किया
और जीवा को कुबेरलाल के सागरी बना दिया। उस समय जीवा आठ वर्ष
का था।

कुबेरलाल एक क्रूर व्यक्ति था। वह जीवा को पीटा करता था और दिन
भर में 15 घंटे काम लेता था। जीवा को दिन में दो बार थोड़ा खान को दिया
जाता। आखिरकार जीवा ने जब बरदाश्त नहीं हाँसता वह भाग गया, पर
कुबेरलाल के आदमियों ने उसे पकड़कर वापस पहुँचा दिया। उसे इतना पीटा
गया कि वह बेहोश हो गया। कुबेरलाल का जब लगा कि इस लड़के का रखना
अपनी परेशानी बढ़ाना है तो उसने जीवा के चाचा से कहा कि वह पसा वापस
करे और जीवा को ले जाय।

फिर जीवा के चाचा ने उस एक दूसरे किसान के हाथ 300 रुपये में बेच
दिया और कुबेरलाल का पसा चुका दिया।

जीवा ने कुबेरलाल के साथ पाँच वर्ष तक काम किया और फिर दूसरे
मालिक के साथ काम करने लगा। इस समय वह दूसरे मालिक की गुलामी में है।
उसका सालाना बतन 150 रुपये है, पर उसे कभी एक पसा भी नहीं मिला।

जब उससे कहा जाता है कि बधुआ मजदूर प्रथा समाप्त हो गयी है तो
मुमकिन है और खामोश रहता है।

उसने जैसे लाखा और जागा में जन यह बात बही जानी है ता व भी चुप ही रहते हैं।

(2) पनिया गांव में 1961 में एक भीत औरत के बारे में जानकारी मिली जो महज 25 रुपये वज्र के कारण 20 वर्ष से गुलामी कर रही थी। बाद में उसके पति ने और ऋण लिया। वह औरत अभी भी सागरी है। उस अनाज पोसन के काम में लगाया गया था। उसने अपना मालिक को रुपये दान चाहे, पर मालिक ने पैसे लेने से इस्कार कर दिया। 1961 में उसने विद्रोह कर दिया और काम बंद कर लिया।

1961 में सागरी प्रथा खत्म कर ली गयी। इस प्रथा के तहत कज लेने के कारण किसी हरिजन या सागरी को गुलाम बना लिया जाता था। जीवा के मामले से दबा जा सकता है कि कजदार व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य को भी सागरी बना सकता था।

1968-69 की एन रिपोर्ट से पता चलता है कि यह उन्मूलन कारगर नहीं हुआ है। 122 लागा स बातचीत में पता चला कि केवल 16 सागरिया को इस प्रथा के समाप्त किये जाने की जानकारी थी। उनमें से सबन यही कहा था कि कज चुकता करने का एकमात्र तरीका सागरी के रूप में काम करना है।

1975 में वधुआ मजदूर प्रथा को कानून के जरिए समाप्त कर दिया गया।

इस बीच सागरिया की संख्या में वृद्धि हुई है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु के उत्तर व दक्षिण आर्कोट जिले सचमुच वधुआ मजदूरों से भरे गिने हैं। यहां 40,000 से अधिक तादाद में वधुआ मजदूर हैं। धर्मपुरी जिले में ही 20,000 से अधिक वधुआ मजदूर हैं।

चंगलपेट, मदुर, तंजौर त्रिचनापल्ली और तिरुनेल्वेलि जिला में से प्रत्येक में दस से बीस हजार तक की तादाद में वधुआ मजदूर हैं। कोयम्बतूर में पांच में लेकर दस हजार तक, रामनाथपुर और सेलम में पांच सौ से लेकर पांच हजार तक की तादाद में वधुआ मजदूर हैं। 1967 में प्रकाशित एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार यह पद्धति नीलगिरि में भी चालू है। यद्यपि 1969-70 में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि तमिलनाडु में यह पद्धति प्रचलित नहीं है। 1971-72 तथा 1972-73 में प्रकाशित दो अन्य रिपोर्टों में यह बताया गया कि नीलगिरि जिले के गुडालूर तारलुक् में शहरी रघतवारान पनिया और वटटुयावना जो दोनों ही जनजातियाँ हैं, व लोग का ठेके पर खेती में लगा रखा है। राज्य सरकार ने यह दावा किया कि जनजातियों के ये लोग अपनी मजदूरी

से ही काम करते हैं और उन्हें अपनी तनखाह के जलावा खाना और कपड़ा भी मिलता है। इन दाया की सत्यता के प्रति सदेह व्यक्त किया गया है। 1979 में अरमुगम की कहानी प्रकाश में आयी। वह अनुसूचित जाति का एक गरीब आत्मी था। आठ बघ की उम्र में उसे एक सवण हिन्दू न पडियाल के तौर पर काम पर रख लिया। 1979 में उसे सत्रह माल काम करते हुए हा गया थे। तब उसकी उम्र पच्चीस बघ थी।

उसके पिता ने 100 रुपये उधार लिये थे और उसे पडियाल बनवा दिया था। उसके मालिक ने उसे प्रति बघ 300 किलो धान देन का वादा किया था। इसके बावजूद उसने सिर्फ 60 किलो धान और 37 पैसे प्रतिदिन दिये। अरमुगम सवेर 6 बजे से रात के 9 बजे तक काम करता था। उसके मालिक के पास 27 एक्ड जमीन कई खेत जोतने वाले पशु, बीस गायें और 6 बधुआ मजदूर थे। किसी ने अरमुगम को बताया कि पडियाल पद्धति को खत्म कर दिया गया है। वह अपने मालिक के पास गया और उसने यह मांग की कि उसका वेतन बढ़ाकर एक रुपया प्रतिदिन कर दिया जाये। उसने यह भी कहा कि पुराने ऋण को चुकता माना जाये। उसने स्वतन्त्र किय जान की मांग की।

उसका मालिक गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि 500 रुपये अब भी पानना बाकी है। उसे आजाद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

अरमुगम भाग गया। उसके मालिक ने सोचा कि इस मामले को एक मिसाल बना देना चाहिए अथवा दूसरे पडियाल भी सिर उठाने लगेंगे। उसने अपने चालीस गुडो की एक टोली का भेजा और अरमुगम का पकड़ मँगाया। उसे उन्होंने एक बिजली के खम्भे से बांधकर नशमनापूवक पीटा। भोजन और पानी के बिना उस चिलचिलाती धूप में बिजली के खम्भे से बंधा रहने दिया गया। उसकी जमीन का टुकड़ा भी छीन लिया गया और उसका वेतन घटाकर 30 पैसे प्रतिदिन कर दिया गया।

1979 में तमिलनाडु में संभवतः 2,50,000 पडियाल थे। अरमुगम को अभी तक उनमें ही गिना जा रहा है।

(2) 1976 में पनियान आदिवासियों की दुख-दुदशा की बातें सुनी गयीं। शेद्री जाति के महाजनो ने उन्हें खाद्य-वस्तुएँ खरीदने के लिए बज्र दिया। बदले में पनियाना न बिना वेतन के उनके खेतों में काम किया। कार्तिकेयन कमटी ने उनकी दुख दुदशा के बारे में जाँच-पड़ताल की। पता चला कि बज्र लेते वक्त पनियाना ने एक साद कागज पर अँगूठे के निशान लगाय थे। इस प्रकार के बघन में बंध गये। एक महाजन ने एक पनियान को 900 रुपये बज्र दिया था और एक बघ बाद मूल-मूद समेत उससे 10,000 रुपये की माँग की। अभाग पनियान के पास बधुआ मजदूर बनने के सिवा कोई चारा न था।

तमिलनाडु में ऐसे हालात की मौजूदगी विलकुल स्वाभाविक है क्योंकि तमाम राज्या की तरह तमिलनाडु पर भी सवण हिंदुओं का शासन है। जब कामराज मुख्यमंत्री थे तो रामनाड जिले में सवण हिंदुओं द्वारा हरिजनों का कत्ले आम किया गया था। वहाँ में, 1968 में जब अनादुर मुख्य मंत्री थे तो जिलेवारी की सवण हिंदुओं ने कम से कम चौवालीस हरिजन मर, औरतो और बच्चा को झोपड़िया में बंद कर आग लगा दी और उन्हें ज़िंदा जला दिया। मुख्य मंत्री अपराधियों को कानून के बंधन से छुड़ाने तक लाने में नासामयाब रह।

तमिलनाडु के सवण हिंदुओं को इस बात पर अटूट विश्वास है कि उन पर कोई आंच नहीं आ सकती। 1978 में विल्लुपुरम के एक व्यापारी ने एक हरिजन युवती के सामने एक अश्लील प्रस्ताव रखा और उस मुहल्ले, जिसे पेरिया कहते हैं के हरिजन युवकों ने 23 मार्च 1978 को प्रतिवाद किया। उस घनी व्यापारी ने उनके मुहल्ले पर 24, 25 और 26 तारीख को हमले किये और उनकी झोपड़िया जला डाली। 12 अप्रैल के लड़के और 35 वर्षीया महिला समेत बारह लोगों को पीट पीटकर मार डाला गया। यह घटना 27 जुलाई 1978 को हुई। इसके पहले, तीन दिन के अग्निवाडा में जने हुए सत्तर व्यक्तियों को सरकारी अस्पताल में भर्ती किया जा चुका था। प्रशासन और पुलिस विभाग निष्क्रिय बंठ रह।

27 तारीख की घटना के बाद अचानक एक मंत्री एक पुलिस दल को साथ लेकर विल्लुपुरम में शांति कायम करने के लिए पधारे। पर इसके एक हफ्ते पहले ही हरिजनों के पेरिया में शमशान की शांति छा चुकी थी।

(3) जनवरी 1978 में पांडिचेरी के निकट पुरानसिंग पालयम के हरिजनों ने पौराणिक राजा हरिश्चंद्र की एक बड़ी बनान की कोशिश की। शमशान भूमि में उनके लिए नियत क्षेत्र में यह वेदी बनायी जा रही थी। सवण हिंदू उसी स्थान पर अपना दाह-सत्कार की बात सपन में भी नहीं सोच सकते। उन्हें हरिजनों की गुस्ताखी जरूरत पड़ी और उन्होंने उनके घर ढा दिये। दूकानदारों ने हरिजनों को खाने पीने की चीजें देने से इन्कार कर दिया, और हरिजनों को खाना पर भी काम करने से रोक दिया गया।

सरकार मजबूर थी।

(4) रजति नामक एक हरिजन युवती की मृत्यु दिसंबर 1978 में हुई और यह घटना 20 मार्च 1979 का सामने आयी जब उसके पिता ने तीन महीने तक प्यास पान के लिए निष्फल ढोड़ धूप करने के बाद मक्खी घटना प्रकट कर दी।

रजति नल्लिपालयम के पेरियाना गोडार की गाँव चराती थी। 19 दिसंबर 1978 का प्यासी रजति ने पशुओं की नाँद से पानी निकालकर पी लिया। उस निंद्यतापूर्वक पीटा गया, क्योंकि नान पवित्र गायों के लिए रखी गयी थी, अपवित्र हरिजन के लिए नहीं।

उस शाम वह घर नहीं लौटी और बाद में उसकी मृतदेह गोडार के कुएँ में मिली। शव परीक्षण में पता चला कि उसे जबरदस्ती डुबो दिया गया था। सेलम के पुलिस अधीक्षक ने इस मृत्यु को आत्महत्या करार कर दिया। गोडार पर रजार्त के पिता को रूपया देना चाहिए, पर यह हत्या का प्रमाण नहीं था।

1979 की एक आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि तमिलनाडु में हरिजनों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। विभिन्न पार्टियों के शासन में यह हमेशा एक मजदूर चीज रही है। यह तत्सवीर कामराज, अनादुर और जनता पार्टी के शासनवालों में एक सी रही।

हमने यह पहले ही बताया है कि बधुआ मजदूरों और हरिजनों पर अत्याचार, दोनों की जड़ में एक ही मनोवृत्ति है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के बलिया, हमीरपुर, हरदोई, खेरी सीतापुर, विजयनगर और बरेली जिलों में बीस हजार से अधिक बधुआ मजदूर हैं।

एटा, कासी, मिर्जापुर, सहारनपुर, बस्ती, बुलंदशहर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, शाहजहाँपुर, सुलतानपुर, मेरठ, वाराणसी और देवरिया जिला में दस हजार से बीस हजार के बीच की तादाद में बधुआ मजदूर हैं।

बादा, बदायूँ इटावा, जालौन, गाजीपुर, मथुरा पीलीभीत उन्नाव और नतीताल जिला में पाँच हजार से दस हजार के बीच की तादाद में बधुआ मजदूर हैं।

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, मैनपुरी और गाढ़ा जिलों में पाँच सौ से पाँच हजार के बीच की तादाद में बधुआ मजदूर हैं।

देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल उत्तरकाशी, रामपुर और पञ्जाबाद जिलों के बारे में कोई जानकारी सुलभ नहीं है या प्राप्त नहीं की जा सकती।

कानून की 386वीं धारा के अनुसार बधुआ मजदूर नियुक्त करना दंडनीय अपराध है।

देहरादून जिले के जौनसार-बाबर क्षेत्र में कोल्हा और बाजगी लोग बधुआ मजदूर हैं। वे हरिजन हैं। उनके मालिक राजपूत हैं। यहाँ जिन रिवाजों का चलन है उन्हें 'भाट' 'खंडित मंडित' और 'सजयेत' कहते हैं। उन्नाव जिले में इन 'साग-बाँध' कहा जाता है।

जौनसार-बाबर में कोल्हा और डोम-कोल्हा लोग का पचायना बाग 'गुमरी' नामक पद्धति के सहारे वन में रखा जाता है।

नीचे कुछ मिसालें दी जा रही हैं।

लेते हैं। बाद में इस ऋण को चुकता करने में अममय होने पर उन्हें ऋणदाताओं द्वारा चलाये जा रहे वेश्यालयों में अपनी पत्नियाँ को अर्पित कर देना पड़ता है। चंद वर्षों में ऋण को रकम दिन दूनी रात चौगुनी हो जाती है और लड़की की हेसियन बर्दिनी की हो जाती है। यह जघन्य व्यापार चलाने में भूस्वामियों को ग्राम पटवारियाँ और सरकारी अधिकारियों में मदद मिलती है।

इस सामाजिक पृष्ठभूमि में दौलती की करुणकथा को अच्छी तरह समझा जा सकता है।

(1) जौनसार बाबर के करीब सभी कोल्टा परिवार वधुआ मजदूर हैं। कमला उर्फ दौलती घोरा गाँव की एक औरत थी। उसके पिता ने अनाज खरीदने और अपनी सबसे बड़ी लड़की की शादी करने के लिए 1,200 रुपये का ऋण लिया था।

जब दौलती की उम्र 16 वर्ष थी तब उसी गाँव के एक ब्राह्मण ने उसके पिता के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह उसका समस्त ऋण चुका देने का तयार है बशर्ते दौलती को उसके सुपुत्र को दे दिया जाय। उसने कहा कि उसका उद्देश्य मर्यादापूर्ण है, क्योंकि वह दौलती से शादी करना चाहता है।

यह ध्यान रहे कि इस पहाड़ी अंचल की औरतें बड़ी खूबमूरत होती हैं और यहाँ की स्थानीय कहावत है कि लड़की के जीवन के पहले दस वर्ष हँसी-पुशी भर रहते हैं और उसके बाद आँसू बहान की शुरुआत होती है।

दौलती का पिता राजी हो गया। उसका ऋण चुका दिया गया और दौलती का भरठ ले आया गया तथा एक वेश्यालय में रख दिया गया।

दस वर्षों तक उसने एक वेश्या का काम किया और ब्राह्मण उसकी समूची आमदनी को ऋण के भुगतान स्वरूप लेता रहा। वह उसकी वधुआ मजदूरिन बन गयी। जब वह तीस वर्ष की उम्र के निकट पहुँची तो उसका सौंदर्य चुका लगा और उसका रट पट गया क्योंकि शहर के ग्राहकों का ताज़ी देह चाहिए। तब उसे वापस घोरा ले आया गया, जहाँ वह पैदा हुई और बड़ी हुई थी, और वहाँ उसने अपनी टूटी देह में ग्रामीण ग्राहकों की सेवा करनी शुरू की।

उस ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसके लड़के ने उसकी जिम्मेदारी ममाली और उसकी आमदनी हथियाना शुरू किया। उसके लिए एक छोटी-सी झोपड़ी बना दी गयी जहाँ उसने अपना व्यापार जारी रखा।

दौलती यह नहीं जानती कि बीस वर्षों की वस्यारूति में उसका ऋण चुका पाया कि नहीं, अथवा उसका ऋण कभी चुका पायेगा या नहीं। वह अभी भी जिन्दा है, अपना घधा चलाती है, और अपनी आमतो मालिक को दे दती है।

(2) जौनसार बाबर क्षेत्र दहरादून और उत्तरकाशी दोनों अंचल में आता है। हम दूसरे अंचल की एक रिपोर्ट पढ़ रहे हैं

ग्राम	ऋणी	ऋणदाता	कारण	राशि	बचन की अवधि
सटटा	मीनू	कुलीलाल	अनाज	500 रु०	17 वष
सटटा	मीनू	लालसिंह	अनाज	300 रु०	17 वष
सटटा	सुखा	हुक्मा	शादी	300 रु०	18 वष
सटटा	सुखा	ठाकुर	भेड़ खरीदना	35 रु०	5 वष
सटटा	सुखा	सुल्कू	लडकी का बक्सा		
			खरीदना	20 रु०	10 वष
मटटा	नंदा	दर्रासिंह	अनाज	100 रु०	12 वष

तीना ऋणी हरिजन हैं और ऋणदाता राजपूत है। सभी समझौते मौखिक रूप से हुए हैं।

(3) उत्तरकाशी के पुरोला प्रखंड में जीप के जलावा जय शिपी वाहन का जाना संभव नहीं है। पुरोला के बाहर सड़का मील तक पहाड़िया है। यहाँ ग्राम पटवारी टक्स-तहसीलदार और पुलिस दोन्ना की भूमिकाएँ साथ साथ निभानी हैं। वे मजबूतमान हैं। यहाँ से औसतन पचास लड़कियाँ हर साल अपने पिताओं, भाइयों और पतियों को ऋण से छुटकारा दिलाने के लिए मर्यादा इलाका के बंधालया को जाती हैं।

कुआँ ग्राम जो डमटा-नौगाँव सड़क पर स्थित है, के ब्राह्मण सरपंच माया राम ने 1961 में पानू नामक एक हरिजन युवती को विभिन्न बंधालया के हाथों चार बार बचा है। हर बार वह किसी दलाल से शादी के लिए गी जान वाली रकम ग्रहण करने की रस्म अदा करता है और शादी की रस्म का मुआयना कर लेने के बाद उसे उसके हाथों बच देता है। जब वह कुछ समय वहाँ काम कर चुकी होती है तो फिर वह उसे खरीद लेता है केवल दुबारा बेचने के लिए।

(4) 27 जुलाई 1974 को पुरोला गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रोफेसर प्रेमदत्त शर्मा ने श्यामा देवी नामक एक हरिजन लड़की को दिल्ली और देहरादून के बंधालया के हाथों बेच दिया।

ऐसी सभी घटनाओं में ग्राम पटवारी शामिल रहते हैं। एक पटवारी ऐसी औरत से आमदनी बढ़ाने के लिए दिल्ली जाता रहता है।

जानकी नामक एक लड़की का वयान निम्नलिखित है

पुरोला की औरतों के लिए बंधावर्ति का कहीं जत नहीं है। पुलिस और सरकार तो केवल तमाशा ही करते हैं।

‘हमारे आत्मियों को ऋण से मुक्ति दिलाओ। उन्हें जमीन दो। केवल पुरोला के सेतो में आजान् आत्मियों के हाथों उपजायी गयी हरी भरी फसले ही औरतों को मुक्ति दिला सकती हैं।

"और कोई उपाय नहीं है।"

पश्चिम बंगाल

हम 1975 के बधित श्रम पद्धति उत्सादन अध्यादेश व शब्द 'मुनीश पद्धति' नोट कर लेना चाहिए। य दा शब्द पश्चिम बंगाल म बधुआ मजदूरों का अस्तित्व जाहिर कर देते हैं क्योंकि आधिकारिक रूप म इनका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन अय रूप म यह निश्चय ही मौजूद है। य रूप है— धातुआ, माहिंदार, वाराभासिया और मुनीश पद्धति जिमम क्रम देकर अथवा ठेके पर बधुआ मजदूर नियुक्त किए जाते हैं।

1976 म कुछ अधिकारियों न एक रिपोर्ट म बडवा तथ्य कह डाला है। देहाती क्षेत्र म श्रमण बढती तात्वाद म लोग अपनी जमीन ग्राब कर रहे थ और इसका शुद्ध परिणाम था सेत मजदूरों की तादाद म वृद्धि होना। पूर्ण मौसम का पीछे छोड़ रही थी और परिणामस्वरूप तनखाह घट रही थी। गंग मजदूरों के लिए तय की गयी न्यूनतम मजदूरी के नियमों के अनुसार कोई भुत्तामी बतन नहीं दे रहा था। पश्चिम बंगाल म जोनदार ही महाजन थ। उन्होंने मजदूरों को अन्य बतन के साथ खाना भी देकर बधुआ बना लिया।

1961 म 1971 के बीच मिर्नापुर म भूमिहीन मजदूरों की तादाद 23 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गयी। पूरे पश्चिम बंगाल के आधार पर य औसत 15 प्रतिशत और 25 प्रतिशत है। इन दम वर्षों म फामरा की तादाद घट गयी। जोनदार लग पूरी भूमि का इन्फेक्शन ले रहे थ। यत स्वाभाविक था कि तत मजदूरों को उतक द्वारा बधुआ मजदूर बना लिया जाता।

भूमे के इलाके बाकुडा, पुरलिया और मिर्नापुर जिला म, जहाँ मान म केवल एक ही फमल हाती है मजदूर साल भर म बाँठ महीन जोनदार महाजन से मिलन वाल बज पर जिया रहते हैं। इन तीन जिला म मजदूरों का तन बका जातदार के सेना म बुआई, रोसाई और कटाई के दौरान काम करने की मौयिक शर्तों म बध जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि य उन पता जिया बतत के काम करते हैं जब उनकी आमदनी हो सकती थी। बाकुडा और पुरलिया के शरीर, पिछड़े जिला म मजदूर मान भर तन जातदार के लिए धातुआ अथवा वाराभासिया के शीर पर काम करते हैं। वष की समस्या पर हर मजदूर का उसकी उम्र के अनुसार पाँच से नकर बारह मन तक भावन मित्रता है। जातदार के ही घर म रहने वाले मजदूर का गारा-बारा मित्रता है।

पुरलिया के मिर्मा और बापमुटी म एक दूसरी पद्धति है। म्दाते आधारों 5 गंग प्रति बीघा की दर पर आर्थियासिया म जमीन 1977 पर 1 है। य उत बीघा और गंग भी देता है। आर्थियामी मान उमर म्दमता

और फसल होने पर व्यापारी उसे लेकर बेच देते हैं।

पश्चिम बंगाल में बहुआमजदारी की पद्धति का प्रचलित रिवाज के सदृश में ममयना हागा। जहाँ मजदूर राजनीतिक रूप से सचेत है, वेतन थोड़ा अधिक है। भातुआ बार बारोमासिया लोग थोड़ी अच्छी हालत में हैं। लेकिन यह दृष्टांत विरल है। कहा जाना है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक चेतना अधिक सजीव है। पर यही परता बहुआमजदारी की पद्धति का सबसे जानदार तरीका में जारी रखा गया है।

(1) बीरभूम जिले के इलाम बाजार थान में भादुरबुनी गांव में गनी मंडल नामक एक जोतदार है। वह 200 बीघा जमीन एक बड़ी परचून की दुकान और आटा पीसाई की मशीन का मालिक है। इलाम बाजार में उसके दो पक्के मकान हैं। उनमें पशुओं के व्यापार में दो लाख रुपये और सूदघारी में 6 लाख रुपये लगा रखे हैं। वह पांच माहिंदार रखता है।

उम से एक का नाम इरफान शेख है। उसके पास चार बीघा जमीन है। उसके परिवार में आठ सदस्य थे। उसने एक बार गनी से थोड़ा धान कज पर लिया था। गनी का नियम था कि अगर एक मन उधार लिया जाय तो दो मन वापस करना होगा। इस कृण के कारण इरफान का अपनी जमीन गनी को सापनी पड़ी और तीस वर्ष की उम्र में वह गनी का माहिंदार बन गया। बारह वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गयी और कज चुकाने का भार उसके लड़के रहमान के कंधा पर आया। उसे गनी से प्रतिदिन एक बार का भाजन मिलता था और प्रतिमाह 37 किलो चावल। पांच वर्ष तक माहिंदार रहने के बाद रहमान के पेट में जलसर हा गया। वह काम नहीं कर पाया और गनी ने उसका मरना भी ल लिया।

रहमान भाग गया। बाद में वह वापस लौटा और उसने शादी कर ली। गनी ने उसमें उसकी पत्नी को छीन लिया जिसने बाद में गनी के बच्चे का जन्म दिया। रहमान ने प्रतिवाद किया। उसके खिलाफ अपराध का एक फर्जी मुकद्मा खड़ा किया गया। वह मुकदमा अभी तक चल रहा है।

रहमान अभी तक मजदूरी करता है। पिता और पुत्र ने मिलकर मजदूरी के सत्रह साल पूरे कर दिये। अब भूत, जो इरफान का दूसरा लड़का है गनी का माहिंदार बन गया है। दो वर्ष तक काम करने के बाद, उसने एक बार गनी द्वारा एक नौकरानी पर बलात्कार करने के खिलाफ प्रतिवाद किया था। गनी ने उसे निकाल बाहर किया।

(2) उसी गांव में एक और जोतदार है जिसका नाम इरफान शेख है। उसके पास 65 बीघा जमीन है और उसने सूखोरी में एक लाख रुपये लगा रखे हैं। उसके पास तीन माहिंदार हैं। उनमें से एक शमसुल हसन है। अभी उसके पास

डेढ़ बीघा जमीन थी। एक बार इरफान न शमसुल के पिता को दामन धान उधार दिया था। उसने ऋण के एवज में शमसुल के परिवार का अपना माहिन्दार बना लिया। वह परिवार के केवल एक सदस्य को भोजन देता था और हर सदस्य से काम कराता था। दरअसल, उसके पास तीन माहिन्दार नाम मान लिए थे। वह सिर्फ एक को वतन देता था और दूसरों से उगने मुफ्त में ही काम कराया। शमसुल के पिता और बरदाश्त न कर सके और वे भाग गये। शमसुल और उसका परिवार अभी तक वधा हुआ है। जब इरफान के अपन खेतों में काम नहीं रहता तो वह उन्हें दूसरे के खेतों में काम करने भेजता है और उनकी आमदनी खुद हथिया लेता है। ऋण देन पर वह 240 प्रतिशत सूद लेता है।

(3) इलाम बाजार थाने के नाचनशा गांव के रामकृष्ण वधोपाध्याय से मिलिये। वह कोई साधारण आदमी नहीं हैं। वह फारवड ब्लॉक (भावसवादी) पार्टी का नेता है और बिलाती गांव की पंचायत का उपप्रधान है। ऐसा सुना जाता है कि 1980 के मई महीने में कभी फामरो न पंचायत कार्यालय को घेर लिया था और कार्यालय के अधिकारियों से पंचायत के काय की राशि 90 000 रुपये का हिसाब मांगा था। सभी अधिकारियों ने कब्ज कर लिया कि रामकृष्ण के ज़िम्मे गबन की राशि थी 5,700 रुपये।

वह 60 बीघा जमीन का मालिक है। उसका कोई बगदार (बटाई पर जमीन जोतने वाला) नहीं है और नीना माहिन्दार बीस बीघा जमीन जोतते हैं।

घुमू लोहार उन माहिन्दारों में से एक है। वह 28 वर्ष का है। खाना, 200 रुपये, दो लुगिया, तीन धोतिया, सालाना एक वनियाइन और एक दिन में पांच बीडिया—यही उसका वेतन है। वह भोर चार बजे में लेकर शाम के सात बजे तक खेत में या घर पर काम करता है।

जब रामकृष्ण पंचायत का उपप्रधान बन गया तो उसने माहिन्दार और गौरानिया को वतन देना बंद कर दिया। इसके बजाय वह उन्हें पंचायत को काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत मिले भंडार से गेहूँ देता है।

वीरभूम में प्रचलित वतन दर के अनुसार घुमू लोहार के काम का वेतन 11 रुपये प्रतिदिन होना चाहिए। जिले का वतन दर आधिकारिक सरकारी दर से बहुत कम है। घुमू के परिवार में लगभग सात सदस्य हैं। उनमें से सिर्फ उसका ही खाना मिलता है। अपने परिवार को खिलाने के लिए उसे रामकृष्ण से उधार लेना पड़ता है।

इस प्रकार उसके कज का पट्टा बढना जाता है।

यह अंतिम दृश्य सच्चे मायना में पश्चिम बंगाल की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। यह वही राज्य है जहाँ हर जिले में हजारों तथाकथित व लोग प्रश्नहीन रूप से जमीन के मालिक हैं। व फर्जी नामा से इस जमीन

कब्जा जमाय रखते हैं जो तय की हुई सीमा से अधिक होती है।

पचायत बन जान से उनके हाथों में बेशुमार शक्तियाँ आ गयी हैं। वे प्रखंड विकास पदाधिकारियाँ, अनुमंडल दंडाधिकारियाँ और पुलिस अधिकारियाँ जैसे पिटठुओं पर हुकूम चलाते हैं। वे भातुआ, माहिंदार बारोमासिया तथा मुनीश पद्धतियाँ को जिलाय रखते हैं। वे बधुआ मजदूरों के पसीने से मुनाफा कमाते हैं। उनकी भूमि में उत्पन्न अनाज के बगदारी के अनुसार बेंटवार का दज नहीं किया जाता। राज्य सरकार के ग्रामीण दम्तों में निलज्ज रक्तशायक शामिल हैं। सरकार ने इन लोगों पर गांव के निवासियों का भाग्य सुधारन की जिम्मेदारी सौंप रखी है। अथ राज्या में जैसा होता है वसा ही यहा भी होता है। उनकी शक्तियाँ असीमित हैं। आधिकारिक पुस्तिकाओं में वर्णित पश्चिम बंगाल का कहीं अस्तित्व नहीं है।

जो लोग सत्ताधारी पार्टी का पक्षपायक बनन की तयार हैं उन्हें सत्ता भी मिलेगी सुयोग भी।

जितने आंकड़े मिल सके हमने प्रस्तुत किये हैं। अब यह ज्ञात हो चुका है कि बधुआ मजदूर प्रणाली चारों ओर फैली हुई है। निम्नलिखित सात जगहों की स्थिति खास तौर पर निरूपित है

- 1 उत्तरी तमिलनाडु—धमपुरी उत्तर व दक्षिण आर्कोट, चेंगलपेट।
- 2 आंध्र प्रदेश—तेलंगाना, हैदराबाद, आदिलाबाद मंडक, करीमनगर महबूबनगर नातगाडा, निजामलड बारगल।
- 3 गुजरात और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र—गुजरात में बतसाड सूरत, बडौला, पंचमहल। महाराष्ट्र में नासिक, धुलिया और तालगाव।
- 4 मध्य गुजरात—मेहसना, सुरेद्रनगर, काठिया में लेकर राजकाट तक।
- 5 समूचा उत्तरी मध्य प्रदेश—महाकोशल, राजगड, रतलाम विदिशा, गुना, मुरना, सागर, छतरपुर सतना, रीवा, शहडाल मरगुजा रायगड, बस्तर।
- 6 पश्चिमी उत्तर प्रदेश—बिजनौर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरली, खेरी, सीतापुर।
- 7 उत्तर प्रदेश और बिहार का उत्तरी सीमांत क्षेत्र—उत्तर प्रदेश में बलिया और देवरिया। बिहार में चम्पारन और सारन।

निम्नोक्त प्रत्येक जिले में 40,000 से अधिक बधुआ मजदूर हैं—तमिलनाडु में उत्तर व दक्षिण आर्कोट, आंध्र प्रदेश में नातगाडा और करीमनगर कर्नाटक में शिवमोगा, महाराष्ट्र में अहमदनगर गुजरात में बडौला, मध्य प्रदेश में सतना,

शाहडाल और वस्तर, बिहार में पलामू और उत्तर प्रदेश में देवरिया ।

बधुआ मजदूर प्रणाली का पूरा बयान करना असंभव है । यह बिहार में हलवाहा के छदमवेश में छिपी रहती है, ता पश्चिम बंगाल में भातुआ-माहिंदार-चारोमासिया के छदमवेश में । कौन जानता है कि अथ छदमवेश कौन-सा है ?

स्वतंत्र किया गया बधुआ मजदूर और अथ आदिवासिया का ठेकेदारा द्वारा 'पुरान' मजदूरों के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है और उन्हें औद्योगिक क्षेत्रों परियाजनाआ, कोयला खानों और चाय बागानों में काम पर लगाया जा रहा है । उन पर अभी तक जुल्म ढाये जा रहे हैं । इस तरह पुरानी पद्धति में एक नया लबादा आट लिया है । इस परिदृश्य पर अब तक कोई रिपाट नहीं तैयार की गयी है ।

उत्तर प्रदेश के गारखपुर और देवरिया जिला में चमार हलवाहा का 'गोबरी' पद्धति के तहत भोजन दिया जाता है । ऐम मजदूरों का आमतौर पर खाना मिल जाता है । मगर यहाँ सवण हिंदू मजदूरों का खाना नहीं दन ।

धान झाड़ने के दौरान पशु दाना भूमा खाता है और जा अश पचना नहीं वह गोबर के रूप में बाहर निकल आता है । हलवाहे उसे साफ करत हैं, गुग्यान हैं और उस पीसकर अपना भोजन तैयार करत हैं । पर इस घाथ का भी मूल्य आँका जाता है और इस उनके वेतन से घटा लिया जाता है । पाँच या छह बला के गोबर से एक मन अनाज या दाना निकल आता है ।

जब तक बहुसंख्यक लोगों को अल्प संख्यकों की व्यवस्थाओं जैसे 'गोबरी' पर निर्भर करना पड़ता है, तब तक बधुआ मजदूरों की पद्धति मौजूद रहगी ।

हम अब भी यह नहीं जानते कि देश के तमाम हिस्सों में क्या हो रहा है ? हमारे सामने महज आंशिक तस्वीर है । जब तक उत्पीड़ित लोग आवाज नहीं उठाते तब तक हम नहीं जान सकेंगे ।

य आवाज उठा पायें, इसके लिए बाड़ी कुछ करना बाड़ी है ।

28 अक्टूबर, 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद ने बहुआ मजदूर प्रणाली को समाप्त करने से संबंधित 'बधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम' पर हस्ताक्षर किये। इस अधिनियम का परिशिष्ट में प्रस्तुत किया गया है। उस वष जुलाई में श्रम मंत्रियों की बैठक में इस विषय में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। उनके अनुसार 22 राज्यों में से 18 राज्यों में इस प्रथा का काफी चलन था। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किये।

राष्ट्रपति के अध्यादेश में कहा गया था कि

1 इस अध्यादेश के जरिए देश में विद्यमान बधित श्रम के सभी रूपा को समाप्त किया जाता है। ये रूप हैं आदियामार, बारोमासिया, बसहया, बंधू भगेल, चेरुमार, गारुगल्लू हाली, हारी हरबइ हालया, जावा, जीता, वमिया खुडित मुडित, कुधिया, लेछेरी, मुझी, भट, मुनीन पद्धति नित मजूर पलेर पडियाल, पनाइलाल सागडी सजी, सजावत सेवक सेवकिया सरी बटटी। इसके जरिए अब से सभी बहुआ मजदूर स्वतंत्र किये जाते हैं। पेशगी रकम दकर अब कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता।

2 उन ऋणा को रद्द किया जाता है जिनकी वजह से बहुआ मजदूरों को काम के लिए मजबूर किया जाता था।

3 मुक्त किये गये मजदूरों का जमीन से हटाया नहीं जा सकता।

4 यदि कोई जमीन किसी महाजन के पास बंधक रखी गयी हो तो यह जमीन मुक्त हुए बहुआ मजदूर को वापस कर दी जायेगी, जिसका इस जमीन पर पूरा अधिकार होगा।

5 अब से कोई भी महाजन पुराने बकाया कज के आधार पर जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकता। यदि इस तरह के दावे किये जाते हैं तो उक्त महाजन पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा तीन वर्ष की जेल या दाना

सजाएँ दी जा सकती ह ।

एक सतवता समिति का गठन किया जाना था जो यह देखेगी कि अध्यादेश के सभी प्रावधानों को लागू किया जा रहा है । इसका काम मुक्त किये गये बधुआ मजदूरों के आर्थिक पुनर्वास की भी देखरेख करना था ।

इस मामले म भी कानून और इसे लागू किये जाने के बीच काफी बड़ा अंतर था । बड़े-बड़े सामंता के निहित स्वार्थ कानून को चलन नहीं दे सकते थे क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक हानि होती थी । इसलिए जानबूझ कर इन कानूनों म कोई-न-कोई खामी छाड़ दी गयी ताकि इन्हें आसानी से न पाटा जा सके । राज्य सरकारों न अध्यादेश की उपेक्षा की । उन्होंने जानबूझ कर मौजूदा बधुआ मजदूरों की संख्या को कम करके दिखाया और समय-समय पर बड़ी हठधर्मिता के साथ कहा कि उनके राज्य मे एक भी बधुआ मजदूर नहीं है । इसीलिए उनके द्वारा प्रर्णित आकड़ों के अनुसार यह तादाद महज 1,20,000 थी ।

लेकिन राष्ट्रीय श्रम सत्यान ने अपने सर्वेक्षण म यह साबित कर दिया कि देश मे लगभग 23 लाख बधुआ मजदूर हैं । पश्चिम बंगाल सरकार न दावा किया कि उसके राज्य मे एक भी बधुआ मजदूर नहीं है । हमें पता है कि बारोमसिया, माहिंदार, भतुआ जादि के नाम से ज्ञात बधुआ मजदूर इस राज्य म हैं और हर वष उनकी संख्या म वृद्धि होती जा रही है । बधुआ मजदूरों का अस्तित्व बना हुआ है, पर पश्चिम बंगाल सरकार अपनी खामोशी के जरिए और अपने उपेक्षा पूर्ण रण के द्वारा इस प्रणाली के प्रसार म मदद पहुँचा रही है ।

कोई भी व्यक्ति इसके लिए राज्य सरकार की उदासीनता, अफसरा की अधमता आदि का दोषी ठहरा सकता है । सच्चाई यह है कि सरकार घरलू और विदेशी दोनों सामंतों तथा पंजीपतियों के हितों पर ध्यान देकर ही शासन चलाती है । सरकार ऐसे कानूनों को लागू कर ही नहीं सकती जो इनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुँचायें । लेकिन कानूना का पारित किया जाना जरूरी था वरना किसान लोग विद्रोह कर देते । सरकार जानती है कि ये कानून निरर्थक हैं और इनसे उन किसानों का कोई भला नहीं होगा जो गरीब हैं और दूसरे पर आश्रित ह । अदालत मे जाने का मतलब ह बेहद खर्च । साथ ही किसान उन महाजनों और जोतदारों का नाराज करना भी नहीं चाहते जो खेत म काम न होने के दिनों म भी उन्हें कर्ज देते हैं और इस तरह के कर्जों पर किसान आश्रित रहत हैं । यदि वे नाराज हो जायेंगे तो भविष्य म कर्ज नहीं मिल सकेगा । इसका दुखद पहलू यह है कि ऐसे ही कर्जों को लेकर उन्हें बधुआ मजदूर बनना पड़ता है । वे कोट-बचहरी म जा नहीं सकते । अगर वे अदालत का सहारा लेते हैं तो भविष्य म क्या वे फिर कर्ज ले सकेंगे ?

सरकारी विभाग भी पर्याप्त रूप से सन्निय नहीं हैं और उनमें स ज्यादातर

ग्रामीण क्षेत्रों में महाजना तथा जोतदारों के प्रभाव में है।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि जिन वधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया था, वे फिर महाजना के चंगुल में पड़ गये।

नवम्बर 1977 में रक्षामंत्री श्री जगजीवनराम ने वधुआ मजदूर प्रणाली पर आयोजित तीन दिन की कार्यशाला में अपने लिखित भाषण में बताया कि इस समस्या की जड़ में आर्थिक स्थितियाँ हैं। हजारों लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताते हैं और ऐसे ऋण लेने के लिए मजबूर होते हैं जिनके कारण उन्हें वधुआ मजदूर बनना पड़ता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें साधारण मजदूर से बहुत कम मजदूरी दी जाती है और उन्हें अपनी इच्छा के विपरीत काम करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कानून बना देना ही काफी नहीं है। लोग की चेतना का विकसित करना और व्यवस्था के खिलाफ उन्हें खड़ा होने में मदद देना भी जरूरी है।

1975 में अध्यादेश पारित हुआ और 1976 में संसद में बताया गया कि आंध्र प्रदेश में 14 और बिहार में 581 वधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया।

क्या किसी को विश्वास होगा कि इन दोनों राज्यों में वधुआ मजदूरों की सच्चा वस यही थी? श्री जगजीवनराम ने कहा कि जब तक सामाजिक तौर पर स्वीकृत वण-व्यवस्था को दूर नहीं किया जाता, भयंकर गरीबी दरिद्रता और रोजिंदारी मजदूर प्रथा को नहीं समाप्त किया जा सकता। वण व्यवस्था का असर गरीबों में भी है। इसकी वजह से ही वे निम्नतम मजदूरी पर काम करने को विवश होते हैं। उनकी गरीबी ने उन्हें वधुआ मजदूर का दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बिताने का निवश किया।

एक उदाहरण प्रस्तुत है

8 अक्टूबर, 1977 को बिहार सरकार के धर्म सचिव ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों के नाम एक सर्कलर (सं. ए. ए. सी. 10140 एल. ३० 813) भेजा। इस सर्कलर के जरिए जिलाधिकारियों का निर्देश दिया गया था कि जहाँ वे यह महसूस कर रहे हैं कि जमींदार और रैयत एक दूसरे के खिलाफ हैं और उनके बीच झूठभेड़ की आशंका है, वे निम्नतम वतन कानून लागू करें। यह निर्णय निकाला जा सकता है कि कुछ जमींदार और जोतदार निम्नतम मजदूरी देने के बारे में अनिच्छुक थे।

जुलाई 1975 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा ने वधुआ मजदूर प्रणाली समाप्त करने में सम्बंधित विधेयक का विधान सभा में पेश करते हुए कहा था कि वधुआ मजदूरी कराने वाला कृषि विभाग की इस्तेमाल किया जा सकता है। तत्कालीन धर्ममंत्री श्री राजमंगल पांडेय ने कहा था कि हम विल से इस बात की गारंटी देंगे कि एक एकड़ वाले छोटे किसानों

से लेकर वधुआ मजदूरी करन वाल सभी लोगो को स्वतन कर दिया जायेगा । वास्तविकता यह है कि कुछ भी नहीं हुआ और साल दर-साल वधुआ मजदूरा की सपना बढती हो गयी । ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वधुआ मजदूरी कराने वाला के गिलाफ मीसा का इस्तमाल किया गया हो । अक्तूबर म राष्ट्रपति के अध्यादेश के बाद भी स्थिति म कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

जून 1976 की एक सरकारी रिपोर्ट म बड़े श्व के साथ दावा किया गया कि आठ राज्या म 48 636 वधुआ मजदूरो का स्वतन कराया गया और जयो का मुक्त कराने की कोशिश की जा रही है । जिनको मुक्त कराया गया है, उह जमीन दवर या पशुपालन, मुर्गीपालन, ग्रामीण कला व शिल्प जाति म लगाकर फिर स बसाया जा रहा है । सरकारी विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण बैंक और सामाजिक कार्यकर्ता—सभी उनकी जरूरतो पर ध्यान दे रह है । उनकी आर्थिक अवस्था पर विचार किया जा रहा है । मुक्त किये गये मजदूरा मे से 14 आंध्र प्रदेश स 581 बिहार स 27195 कर्नाटक मे 19000 उत्तर प्रदेश से, 10112 राजस्थान से 481 तमिलनाडु से 243 मध्यप्रदेश से और 10 उड़ीसा स थे ।

उस वष सितम्बर माह म केन्द्रीय समीक्षा समिति की रिपोर्ट म बताया गया कि आठ राज्या म 75,000 वधुआ मजदूरा का पता चला है । उनम से 55,000 को मुक्त करा दिया गया है । इन मुक्त कराये गये लोगो मे से तीन हजार मजदूरा का फिर से बसाया गया है ।

बिहार सरकार न भी वधुआ मजदूरा का पता लगान उह मुक्त कराने और उनक पुनर्निर्माण के लिए सतकता समितिया और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की । कानून का उल्लंघन करन के लिए दा व्यक्तियों को सजा दी गयी और उह एक वष के लिए जेल भेज दिया गया । आज प्रदेश म भी ऐसी ही व्यवस्था की गयी जहाँ वधुआ मजदूरा को स्वतन कराया गया और खेती करन तथा रहने के लिए उह जमीन दी गयी । तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान मे भी यही हुआ । उपरांत सभी मामलो म और छासनीर से जादिवासी इलाका म कानून को अमल म लान म ढिलाइ देखी जा सकती है । फलस्वरूप मुक्त कराये गये वधुआ मजदूर नरवारी मन्द के लिए अनिश्चित काल तक इतजार नहीं कर सकते थे । साथ ही अध्यादेश क जा जान स जोतदारा महाजना तथा मजदूरा के बीच सबध कटु हो गये थे । इस बात की संभावना नहीं रह गयी थी कि मुक्त कराये गये वधुआ मजदूरा का मातिका के येन पर फिर काम मिल सकेगा । इसका नतीजा यह हुआ कि मुक्त कराये गये मजदूर एक बार फिर वधुआ बनन के लिए मजबूर हो गये ।

1978 के आकडा स पता चलता है कि 56 प्रतिशत वधुआ मजदूर पिछले

तीन वर्षों म और 33 प्रतिशत पिछन एक वर्ष म बधुआ बनाय गय ।

अनक राज्य सरकारें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण स इस प्रथा के उन्मूलन को अपन यहाँ स्वीकार नहीं कर सकी । जो भी कदम उहनि उठाय वे महज केन्द्र सरकार के दबाव के कारण थे । जस ही श्रीमती गांधी चुनाव हार गयी और जनता पार्टी सत्ता म आयी, उहान अपन सार प्रयास छाड़ दिय । हजारों मजदूरों का जिह मुक्त कराया गया था, भूखे भेडिया के सामन थाक दिया गया । राजस्थान का दृष्टांत उल्लेखनीय है । यहाँ वास्तविकी कानून और जागीरदारी प्रथा के समाप्त हान के बाद जवरन मजूरी प्रणाली समाप्त हा गयी थी । लेकिन बधुआ मजदूर (जिह सागरी कहा जाता था) का अस्तित्व बना रहा । छोटे छोटे वर्जों क कारण हजारों खेतिहर मजदूरों को गुलामी के लिए मजदूर किया गया । श्रीमती गांधी के शासन-काल म 5,384 बधुआ मजदूरों को मुक्त किया गया । उनके पुनर्वास का जिस समय प्रयास किया जा रहा था जनता पार्टी सत्ता म आ गयी और राजस्थान म हरिदेव जाशी की सरकार ने जोतदारों और महाजनों के खिलाफ जा भी मामल धे, वापस ले लिय । इसक बाद यहा की सरकार का पतन हो गया और राज्य म राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और तब तत्कालीन राज्यपाल न पिछली सरकार द्वारा लिये गये फसला का पालन करन का फसला किया । सागरी मजदूरों के 693 मालिकों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया जिनम से 77 को सजा हुई और मृत के अभाव म 77 को रिहा कर दिया गया । अपन खिलाफ मामले वापस ले लिये जान के बाद इन सभी न एक बार फिर नये जाश के साथ अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी ।

मध्य प्रदेश का उदाहरण लें । यहा राज्य सरकार बधुआ मजदूरों का पता नहीं लगा सकी बल्कि यह कहना ठीक हागा कि इसन बधुआ मजदूरों का पता नहीं लगाया । इसलिए उनको मुक्त करान और उनको फिर स बसाने के मिलसिल म भी कुछ नहीं किया जा सका । केन्द्र सरकार द्वारा दिय गय दा कराड रुपय का कोई दस्तमाल नहीं हुआ और बन् तिजारी म पड़ा रहा । 1978 म राष्ट्रीय श्रम सन्धान न एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसम कहा गया था कि राज्य म बधुआ मजदूरों की संख्या 5 लाख है । 42 जिलों के 172 गावों म बधुआ मजदूरों की मौजूदगी तलायी गयी थी जिनमे अधिकांश हरिजन तथा आदिवासी थे । इम से विशेष रूप से उल्लेखनीय जिले हैं—बिलासपुर, शहडोल, सरगुना, विदिशा सतना, रायगढ़ और बस्तर । इनम म प्रत्येक जिले म 20,000 से अधिक बधुआ मजदूर थे । इसके बाद बालाघाट छतरपुर, माडला राजगढ़ सागर, रीवा गुना और मुरना का स्थान ह । इम स प्रत्येक म 10 000 स 20 000 बधुआ मजदूर थ । इसके बाद तीसरे स्थान पर है—धार इन्दौर रायसन रतलाम सेहोर शाजापुर खडगोन, उज्जैन, ग्वालियर और शिवपुरी । इनम से प्रत्येक म

5,000 से 10,000 बधुआ मजदूर थे। अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों के आयुक्त की विभिन्न रिपोर्टों तथा मध्य प्रदेश हरिजन सेवक संघ द्वारा किये गये प्रयासों के जरिए भी इन आकड़ों की पुष्टि की जा सकती है। फिर भी राज्य सरकार इन बधुआ मजदूरों की शिनायत नहीं कर सकी—बंशक आपातकाल के दौरान हमने महज यह स्वीकार किया कि राज्य में बधुआ मजदूर हैं। घड़ी आसानी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसके पीछे कोई गहरी चाल थी। बाद में, जिन बधुआ मजदूरों को आजाद कराया गया था वे एक बार फिर बधुआ बन गये, क्योंकि उन्हें कोई मदद नहीं दी गयी।

इस अध्याय का महाराष्ट्र की स्थिति पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राज्य सरकार ने यह मानने से इन्कार किया कि उसने यहाँ बधुआ मजदूर हैं। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में अध्याय का लागू करने का सवाल ही नहीं पड़ा हुआ और मामला के हित बरकरार है।

फिर भी सर्वेक्षणों से पता चलता कि यहाँ बधुआ मजदूरों की समस्या उल्लेखनीय थी। इस संभव में बुर्यात जिले थे—धान, बालावा, नासिक, धुलिया और चंद्रपुर। 1976 में अगस्त से अक्टूबर के बीच भूमि-मनाआ में पानघाट तालुका के 190 गाँवों में से 20 का सर्वेक्षण किया जहाँ आदिवासीयों की संख्या काफी थी। केवल 20 गाँवों में इन्होंने 261 बधुआ मजदूरों का पता लगाया। इन सबसे मिल पाना संभव नहीं था और इनमें से अधिकांश मजदूर नाहूकारों और महा-जनों से इतने भयभीत थे कि जुवान भी नहीं खाते थे। लगभग सभी लोगों से बातचीत की गयी और बातचीत के दौरान पता चला कि इनमें से 50 प्रतिशत लोगों को इसलिए बधुआ बनना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने बज लिया था और बज की यह राशि 600 रुपये से कम ही थी। शेष लोग 600 रुपये से 1500 रुपये के बीच की राशि बजने के रूप में वेतन के कारण बधुआ बन गये। लगभग 33 प्रतिशत लोग छह घण्टे से भी कम समय से बधुआ रूप में काम कर रहे थे। शेष 6 वर्ष से लेकर 21 वर्ष से बधुआ बने हुए थे। जिन 100 लोगों से बातचीत की गयी उनमें से 35 लोगों का यह याद भी नहीं था कि उन्होंने कितने रुपये बज के रूप में लिये थे। 87 लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनका ऊपर अभी कितना बज बाकी है। 70 लोगों का अपना बज की व्याज दर का पता नहीं था।

100 मजदूर ऐसे थे जो प्रतिदिन 11 घंटे काम करते थे। 21 लोगों का बचपन से ही बधुआ था और शायद वे बाद भी उसकी यही स्थिति बना रही। 79 लोग ऐसे थे जिन्होंने शादी के बाद इस दुभाग्य का शिकार होना पड़ा। इन 100 में से एक मजदूर ऐसा भी था जिसे नकद या अन्य रूप में कोई बचत नहीं मिलता था—उसने बस पीने के पानी मिलता था। दो मजदूर एक घंटे प्रतिदिन

दो रुपये मिलते थे। 97 मजदूरों का वतन के रूप में आज दिया जाता था। 71 मजदूर ऐसे थे जिन्हें प्रतिदिन 1 प्याली (600 ग्राम) चावल मिलता था। 26 लोगों का हर महीने 20 प्याली वतन के रूप में मिलते थे—रहू अतिरिक्त रूप से 20 प्याली और दिया जाता था जिससे इनका कज बराबर होता था। महिला मजदूरों का प्रतिदिन एक प्याली चावल मिलता था। इन सौ लोगों में से 13 मजदूर अकेले थे और 43 दम्पति थे।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य में वधुआ मजदूरों की मौजूदगी से इकार किया। फिर भी अक्टूबर 1975 में हरिजन सेक्टर में न मिरमार जिले के पुण्डु तातुब में 12 गाँवों का सर्वेक्षण किया और 63 वधुआ मजदूरों का पता लगाया। ये काली और डाम जाति के थे—गाना जातियाँ हरिजन हैं। इन पर सौ रुपये से लेकर तीन हजार रुपये का कज था। इन्हें अपनी गुलामी के बदले में थोड़ा सा चावल और पुराने कपड़े मिलते थे। अनुभव लगाया जा सकता है कि अजय जिला में भी यह प्रथा प्रचलित थी।

सरकार ने चूँकि इस प्रथा के अस्तित्व से ही इकार किया था इसीलिए इसका उन्मूलन का सवाल भी नहीं पड़ा हुआ। इस प्रकार निहित स्वार्थी तत्वा ने इससे सबद्वे अध्यादेश का लाकाम कर दिया।

सितम्बर 1976 में नयी दिल्ली के सूत्रों से पता चला कि 73,909 वधुआ मजदूरों की शिनायत की गयी थी। इनमें से 55,555 का मुक्त कराया गया और 3,039 का फिर से बसाया गया। वधुआ मजदूरों के बारे में सरकारी तौर पर जा आकड़े एकत्रित किये गये थे इनमें आंध्र प्रदेश में 826, त्रिहार में 581, उड़ीसा में 285, मध्य प्रदेश में 243 राजस्थान में 4,974 तमिलनाडु में 2,416, कर्नाटक में 33,584, और उत्तर प्रदेश में 39,000 थे।

उस वर्ष राष्ट्रीय प्रतिचयन सर्वेक्षण के 27वें चक्र में जो सर्वेक्षण हुआ, उससे एक अलग ही तस्वीर उभर कर आयी। रिपोर्ट में कहा गया था कि नियमित वतन पान वाला कमचारियाँ और वतन भोगी मजदूरों में भी वधुआ मजदूर थे। इनका प्रतिशत हिमाचल प्रदेश विहार तथा अन्य राज्यों में क्रमशः 0.74, 5 और 2.3 था। देश में कुल कामकाजी लोगों की संख्या 24 करोड़ थी जिसमें से 70 लाख वतनभागी कमचारी और मजदूर थे। इन आँकड़ों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ के आयुक्त ने भी समर्थन दिया था।

सरकारी आँकड़ों और सर्वेक्षणों से प्राप्त आँकड़ों में इतना ज्यादा अंतर क्या था? ऐसा इसलिए हुआ क्या कि महाजनों और जोतदारों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने वधुआ मजदूरों के अस्तित्व से ही इकार किया था। यदि ये इनके अस्तित्व को स्वीकार कर लेती तो इन मजदूरों का मुक्त कराने के

लिए कानूनी कदम उठाने का भी सवाल पड़ा होता। इससे निहित स्वार्थी तत्वा का चाट पहुँचती जा मौजूदा सामाजिक स्थिति में समभव नहीं था। इसी कारण यूनतम मजदूरी कानून भी लागू नहीं हुआ और अतिहर मजदूर कम मजदूरी पर काम करते रहे।

बधुआ मजदूर निरक्षर थे और उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी। इनमें से अनेक को आज भी यह नहीं पता है कि कानून की निगाह में वे एक स्वतंत्र नागरिक हैं। अपनी अज्ञानता के कारण वे अपने बाजिब हक के लिए एकजुट नहीं हो सके। अक्टूबर 1975 के अध्यादेश के तहत वे मुक्त नहीं हो सका। यदि ऐसा होता तो वे उन महाजना और जोतदारा के खिलाफ आगे उन संगठित करत गिहान उन्हें अभी भी बधुआ बना रखा या। राजनीतिक दल न भी चुप्पी साध रखी थी क्योंकि किमाना और खेतहर मजदूरों की तुलना में जोतदारा और महाजना के साथ उनके ज्यादा पारस्परिक संबंध थे।

ध्यान देने की बात है कि राजस्थान तमिलनाडु और उड़ीसा न सविधान व अंतर्गत इस व्यवस्था को गैर-कानूनी घोषित कर दिया था और अपने-अपने राज्या में क्रमशः 1956, 1940 और 1920 में इसका उन्मूलन कर लिया था। फिर भी बंधुआ मजदूरों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और न अपने अधिकारों के लिए किसी तरह का दावे नहीं कर सकते थे। यदि उन्हें उचित मजदूरी मिलती तो वे शायद इतना कष्ट नहीं लेते जिससे उन्हें बंधुआ बनना पड़ा। चूंकि वे अपठढ़ थे, इसलिए यह नहीं समझ सके कि अदायगी किस पान के वादजून महाजन के खाने में कस उनके कज बढ़ता रहा।

बैकटम्हामी की ही मिमाल ले जिनम 25 प्रतिशत व्याज पर दा वष क लिए 270 रुपया कज लिया था । इस एवज म वह 730 दिन तक काम करन के लिए राजी हुआ था । इस ठके की अवधि क अंत के समय उस पर 405 रुपय चढ़ चुके थे । यदि उसे 4 50 रुपये प्रतिदिन की दर मे यूननम महदूरी मिली होती ता उसके हिस्से म 3,285 रुपय अति । अपना रज चुकता करन के बाद भी उसके पास 2,880 रुपय होत । कहन की जरूरत नहीं कि उस कुछ भी नहीं मिला । मुक्त कराय गय बधुया मजदूरा क पुनर्वास के बार म सरकारी स्तर पर धूर्त्ताधार प्रचार दिया गया । इन मिलमिने म कुछ राज्या की भूमिका का उल्लेख किया जाना चाहिए ।

आकड़ा के अनुसार आंध्र प्रदेश में सितम्बर 1976 तक 926 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया था। इनमें से 698 का फिर्त नाम बसान का दावा किया गया। सरकार ने क्लेक्टर्स तथा हरिजना एंव पिछड़ी जातियों के निदेशकों का निर्देश दिया कि वे मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों की खेती-बाड़ी और आवास के लिए जमीन की व्यवस्था करें। जमीन का टीक करने तथा खेती-योग्य

बनाने के लिए कम व्याज पर ऋण दिये जाने की अपेक्षा की जाती थी। राजस्थान में मुक्त कराये गये 1,328 बधुआ मजदूरों में से प्रत्येक का 500 रुपये का भुगतान किया गया। कुछ को तो काम दिये जाने की भी बात कही गयी। बिहार में 581 बधुआ मजदूरों को स्वतंत्र किया गया और 376 को बल, धान के बीज तथा उर्वरक प्रदान किया गया।

तमिलनाडु सरकार ने तहसीलदारों की नियुक्ति की ताकि अध्यादेश को कारगर बनाने की गारंटी रहे। जिन पनियाआ को स्वतंत्र किया गया उन्हें पहाड़ी क्षेत्रों की विकास योजनाओं में लगा दिया गया। छोटे किसानों को राष्ट्रीय कृषि बैंक की मदद से कृषि पहाड़ी क्षेत्र में छोटे किसानों के विकास से संबंधित कार्यों में लगा दिया गया। उत्तर प्रदेश में 31,000 बधुआ मजदूरों का पता लगाया गया और इनमें से 19,177 को मुक्त कराया गया। 1976 में सितम्बर माह तक यह योजना बनायी जा रही थी कि 16,000 मुक्त मजदूरों को फिर से बसाया जाये।

अनेक राज्य सरकारों ने बधुआ मजदूरों के अस्तित्व से ही इन्कार कर दिया और कहा कि अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया। जिन बधुआ मजदूरों का पता लगाने और उन्हें फिर से बसाने की दिशा में सक्रियता दिखायी थी, वे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह की योजनाएँ और कार्यक्रम वे बना रहे थे उससे पता चलता था कि न तो वे बाई सुनियोजित योजना ही बना रहे थे और न ऐसा करने की उनकी इच्छा ही थी। कोई अनुभव हीन व्यक्ति भी यह आसानी से समझ सकता था कि पुनर्वास के लिए आवश्यक चीजें हैं—खेती-योग्य जमीन, जातन के लिए मवेशी, खेती के उपकरण, बीज, उर्वरक और सिंचाई व्यवस्था। फसल तैयार होने तक खाने पीने के लिए पास में पसा होना भी जरूरी था।

सिंचाई यह थी कि इस तरह की महायत्ना नहीं दी गयी और पुनर्वास का काम शून्य ही रहा। इसका नतीजा भी वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। जिन जमीन मिली थी, उन्होंने उसे महाजन को वापस लौटा दी और फिर अपने कंधों पर गुलामी का जुआ लाद लिया। जिन्हें हल बल दिया गया उन्होंने अपना पट भरा के लिए हल बल बेच दिया और एक बार फिर वे बधुआ मजदूर बन गये। जिन्हें नकद राशि मिली थी, उन्होंने उसे खर्च कर दिया और किसी का गुलाम बनकर वे फिर खेतों में काम करने लगे। देश भर में यही स्थिति देखने को मिली। अध्यादेश के बाद बधुआ मजदूरों की कतार में 526 प्रतिशत में लोग आ गये थे जो हाल में बधुआ बन गये।

केन्द्रीय श्रम मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच भी एक लड़ाई है। दरअसल इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि बधुआ मजदूर महज बेजान

जाकडे नहीं है बल्कि वे भी हाइ मास के आदमी हैं जिन्हें जोतदारों और महाजना का शोषण बरदाश्त करना पड़ता है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान के अनुसार वधुआ मजदूरों की संख्या 23 लाख थी। राज्य सरकारों ने इससे इकार किया और इस संख्या को 1 लाख 20 हजार बताया। केन्द्र सरकार का दावा है कि यह संख्या 2 लाख से कुछ अधिक है। इसने राज्य सरकारों से सर्वेक्षण करने के लिए कहा। राज्य सरकारों और केन्द्र के बीच पनाचार जारी है। कुछ राज्यों ने तो केन्द्र सरकार को जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी।

पुनर्वास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। केन्द्र में कुल खर्च का आधा हिस्सा देने पर सहमति व्यक्त की है। छठी योजना में इस कार्य के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान है। फिर भी कुछ नहीं किया गया। जब तक सरकारी व्यवस्था और भूमि व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं होता, निहित स्वार्थों का ही बोलबाला रहेगा।

हर तरह विचार विमर्श और तरह-तरह की योजनाओं के बावजूद 10 प्रतिशत भी उपलब्ध किये जाने में शक है। केन्द्र के नए इरादों को साबित किया जा सकता है। श्रीमती गांधी ने इस मामले को अपनी 20-सूत्री योजना में शामिल किया और इस सिलसिले में अध्यादेश जारी किया गया। लेकिन सचार्इ यह है कि कुछ भी नहीं बदला। सरकार वधुआ मजदूरों का पता नहीं लगा सकी और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा पेश किये गए आंकड़ों का भी ध्यान नहीं दिया। पुनर्वास का काम खटाई में पड़ा रहा और वधुआ मजदूरों का शोषण जारी रहा।

सही तसवीर पाने के लिए जब सर्वेक्षण शुरू हुआ तब केवल 10 राज्यों में वधुआ मजदूरों के अस्तित्व को स्वीकार किया। जिन राज्यों में वधुआ मजदूरों के अस्तित्व से इकार करके पहले से चली आ रही व्यवस्था की हो रक्षा की। क्या जिन राज्यों में इनकी मौजूदगी को स्वीकार किया, वे मचमुच इस प्रयास को समाप्त करना चाहते थे? ऐसा करने का मतलब सामंती प्रभुओं को कमजोर बनाना होता जो सरकार की रीढ़ हैं। इन राज्यों में केवल राजनीतिक बाजीगरों का पता लगाया। आखिर किस तरह गुजरात में केवल 42 और उड़ीसा में महज 311 वधुआ मजदूरों के होने की बात कही गयी? आखिर कैसे दस मृत्युवादी राज्यों में इनकी संख्या केवल 1 लाख 20 हजार बतायी गयी? तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की सरकारों किस तरह यह दावा कर सकी कि उनके राज्यों में न केवल वधुआ मजदूरों का पता लगा लिया गया है और उन्हें मुक्त करा दिया गया है बल्कि उन्हें फिर से बसा भी दिया गया है? फिर भी इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चार सदस्यों ने उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण किया और बताया कि वधुआ मजदूरों के पता लगाने का काम बहुत बठिन है क्योंकि वे मजदूरों और

अपने मालिका से इतना भयभीत है कि कुछ भी बोलने में घबराये यदि सचमुच मदद करती तो यह काम बंठता नहीं होता।

इस मामले पर देशभर धन खर्च किया जा चुका है, हालाँकि की हालत पहले जैसी ही बनी रहो। 1978-79 में बर्माटिक न 378 वधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए 5.07 लाख रुपये खर्च 388 मजदूरों के पुनर्वास पर 2.69 लाख रुपये मध्य प्रदेश में पुनर्वास पर 2.37 लाख रुपये, उड़ीसा में 308 लोगों के पुनर्वास रुपये राजस्थान में 700 मजदूरों के पुनर्वास पर 14 लाख रुपये न 495 मजदूरों के पुनर्वास पर 10 लाख रुपये खर्च किये।

तमिलनाडु सरकार के अनुसार वधुआ मजदूरों की सहायता 1977-78 में 517 मजदूरों को फिर से बसाया गया। 19 द्वारा इसी काम के लिए दिया गया 5.32 लाख रुपये यह खर्च : जाय प्रदेश में 1978-79 में मुक्त कराया गया 2,920 वधुआ मज पर 18.01 लाख रुपये खर्च किये।

1978-79 में मुक्त कराया गया वधुआ मजदूरों के पुनर्वास 97.64 लाख रुपये प्रदान किये। बताया जाता है कि 5,420 मज पर राज्यों में इसमें से 55.92 लाख रुपये खर्च किये।

1979-80 में 53.62 लाख रुपये दिए गए थे। इस धन को के पुनर्वास में व्यय किया जाता था। चाल वर्ष के लिए 3 व प्रावधान है। यह पता बेकार पड़ा हुआ है, क्योंकि कनाटक और छाड़कर दूसरे किसी राज्य में वाइ याजना नहीं पेश की।

यदि काम की प्रगति इसी स्तर पर होती रहती तो पुनर्वास चला जायेगा। छठी योजना में 25 करोड़ रुपये का जो प्रावधान इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।

यह मान लेना बंठता है कि महज इस पैसे से खर्च किया जा कराये गए मजदूरों को समाज में उचित स्थान प्राप्त हो जायेगा। देख लिया है कि पुनर्वास की याजना एक ढांग है। हम यह नहीं भावी याजनाएँ इससे कुछ बेहतर होंगी।

जब तक वधुआ मजदूरों में चेतना नहीं पैदा होती और वे खड़े नहीं हो जाते, कोई भी उन्हें आजाद जिलगी बिताने का हक नहीं

हम प्रारंभ के अध्यायों में देखा कि किस तरह बधुआ मजदूर प्रणाली की शुरुआत हुई और खती-बाड़ी में लग लोग का बधुआ मजदूर बनना पड़ा। जानकारों और महाजनों द्वारा दाय जा रहे जुल्म भी आज भी जारी हैं।

1947 के बाद में इन मजदूरों की दुश्शा पर जनक चार विचार विमर्श द्वारा और पर्याप्त घड़ियाली आँसू बहाय गए। फिर भी हालात में कोई तपस्वी नहीं आयी। यह हालात तब तक ऐसी ही बनी रहेंगी जब तक भूमि वापसकारी में आमूल परिवर्तन नहीं आता। फिलहाल 20 प्रतिशत जमीन के पास 80 प्रतिशत जमीन है और 80 प्रतिशत जमीन के पास 20 प्रतिशत जमीन। राजनीतिक दलों में जमीन का वास्तविक विमान का दान का झूठा नारा उछाला है और इस प्रकार समूचे समान को एक राजनीतिक खेल बना दिया गया। दरअसल इन प्रकार के खिलाफ आम आन्दोलन छेड़ने की जरूरत है और कोई भी राजनीतिक दल—चाहे उसका रंग लाल पीला, नीला कुछ भी हो—नतुन नहीं दे सकता, क्योंकि सभी स्तरों के राजनीतिक नेता गैर-नेतिहर जमीनदार परिवारों के हैं। इसलिए इन मतलों के बने रहने में जनता भी स्याय है। यह जाना नहीं की जा सकती कि ये सभी व्ययस्था का नष्ट कर देंगे या उनका पालन है। इसीलिए बधुआ मजदूरों के अस्तित्व में इस्तेमाल करते हैं और हम प्रकार जनता निर्दिष्ट स्याय बनाय रखते हैं। जो राज्य इन गरीब अभागों के हान की बात मानने भी नहीं है उन मजदूरों का मुक्त कराने और उन्हें बर्मान की लड़ाई में कुछ भी नहीं करते।

इस प्रकार आज भी वही हालात बनी हुई है जो 1947 में थी।

इस समय का श्रीमती गांधी की 20-सूत्री योजना में शामिल किया गया और एक अध्यात्म जारी किया गया। राष्ट्रीय धर्म सम्मान के तहत इन में पता चलता है कि हम कोई लाभ नहीं दिखता। अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जातियों के आनुकूलन जातकारी के कि 1970 में मात्र 1,05,180 बधुआ मजदूरों का पता लगया गया है 1,04,789 का मुक्त करवाया गया है और 31,844 का रिक्त

करने के काम म या जगला म दैनिक मजदूरी पर काम करें। इस तरह के काम त तो हमेशा उपलब्ध रहत ह और न सबको दिये जा सकने ह। भूख और गरीबी न एक बार फिर उह वधुआ बनने के लिए मजबूर कर दिया।

मजदूरों की ठेकेदारी करन वालों को इसी मौके का इतजार था। जनता सरकार के शासन काल मे ठेकेदारों न बिहार और उत्तर प्रदेश म मुक्त कराये गये इन मजदूरों को गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र म काम करने के लिए भेज दिया।

1979 के अकाल न इस प्रक्रिया मे तेजी ला दी। भूख और गरीबी का अब ज्यादा जोर था। सरकार की तरफ म किसी तरह की राहत नहीं मिली जो अस्थायी तौर पर इन लोगों को मदद पहुँचा सकती। इसलिए उनके दल के दल अपक्षावृत समृद्ध राज्या म भेज दिये गये जहा उद्योगों तथा बड़े उड़े कृषि फार्मा म काम करने के लिए सस्ते मजदूरों की जरूरत थी। कोटा से दूसरे राज्य म स्थानांतरित एक मजदूर न बताया कि किस प्रकार अशुशल मजदूरों को महाराष्ट्र भेजा गया। ये सभी मुक्त कराये गये वधुआ मजदूर थे। पंजाब के धनी किसानों न भी ठेकेदारों के जरिए कई हजार ऐसे मजदूरों का आयात किया जिन्हें वधुआ जिंदगी से मुक्त कराया गया था।

महाराष्ट्र और पंजाब म इन मजदूरों का जो अत्याचार झेलना पड़ता है उसकी जानकारी किसी को भी उत्तर प्रदेश म हा सकती है। ठेकेदारों न अच्छी तनवाह, अच्छा भोजन और आरामदेह मकान का लालच देकर इन मजदूरों को महाराष्ट्र पहुँचा दिया। लेकिन सचार् यह थी कि उह इतने पैसे भी नहीं मिलत थे जिससे वे दिन म एक बार भी अपना पेट भर सकें और रहने के लिए उनके पास काइ जगह भी नहीं थी।

जो पंजाब गये उनकी हालत भी बदतर थी। उह यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। काम के घंटे बहुत ज्यादा थे। उनकी हालत पहले जमी ही थी—बेम, अब मालिक पल गये थे।

इसका सारा दाप पुनर्वास क काम म सरकार की उपेक्षा का दिया जाना चाहिए। वधुआ जिंदगी स जाजाद इन मजदूरों न अपन का जोर भी बुरी हालत म पाया, क्योंकि सरकार ने अपन उस कृतव्य का पालन नहीं किया था जो इनका मुक्त कराये जाने के बाद उसे करना चाहिए था।

मुक्त कराये गये मजदूर महाजनों और जोतदारों के पास नहीं जा सक, क्योंकि कानूनी कर्म उठाने के कारण इनसे उनके मवध बटु हो चुके थ। साथ ही सरकार तैका तथा इस तरह की सस्या का गठन नहीं किया था जिसम नृण के रूप म मजदूरों का कुछ सहायता मिल सके।

दरअसल ऐसी कोई सस्या नहीं है जिसे सरकार गाव के महाजनों के स्थान

तरह के कानून से किसको ज्यादा सुशी होती ?

अध्यादेश में वर्णित रूपों के अनिश्चित और भी कई तरह के बधुजा मजदूर हैं। वे कानून के दायर में नहीं आते। उनके राज्या न इनके अस्तित्व से ही इकार करके इस प्रथा का बनाय रखने में मदद पहुँचायी है। ता भी राष्ट्रीय धर्म संस्थान न साबित कर दिया है कि बधुजा मजदूरों का अस्तित्व है और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है।

मुक्त कराये गये बधुजा मजदूरों का दी गयी जमीन खेती याच नहीं थी और फसल तयार होने तक उनका भरण पोषण का कोई इतजाम नहीं किया गया था। कुछ का हल मिला तो बल नहीं और कुछ को बल मिला तो हल नहीं। कुछ को खाल बल और हल मिला ता जमीन नदारद। गवर्नर की थी यह पुनर्वास योजना।

यह एक सुनियोजित तमाशा था। इस तमाशा में जाकर्षित न होने वाला म दिना दिन बढ़ती तादाद में मुक्त कराये जा रहे वे बधुजा मजदूर वे जिनके कंधा पर एक नयी तम्ब की गुलामी का जुआ रखा जा रहा था।

परिशिष्ट
बधित श्रम-पद्धति (उत्सादन) अधिनियम
1976

(1976 का अधिनियम सस्याक 19)

(9 फरवरी, 1976)

जनता के दुबल वर्गों के जाधिक और शारीरिक शोषण का निवारण करन के उद्देश्य से बधित श्रम-पद्धति के उत्सादन का और उससे सबधित या उसके आनुपगिक विषया का उपबध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छठ्वीसवे वष म ससद द्वारा निम्नलिखित रूप मे यह अधिनियमित हा—

अध्याय 1

प्रारभिक

सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारभ

- 1 (1) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम बधित श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम, 1976 है।
- (2) इसका विस्तार सपूर्ण भारत पर है।
- (3) यह 1975 के अक्तूबर के पच्चीसवें दिन को प्रवत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएँ

2 इस अधिनियम में, जब तक कि संभव हो अन्यथा अपेक्षित नहीं है—

- (क) 'अग्रिम' से, चाहे नकद या वस्तु रूप में अथवा भागत नकद या भागत वस्तु रूप में ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति द्वारा (जिसे इसमें इसका पश्चात ऋणी कहा है) दिया जाता है
- (ख) 'करार' से ऋणी और ननदार के बीच करार (चाहे वह लिखित रूप में हो या मौखिक अथवा भागत लिखित रूप में हो और भागत मौखिक) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत काइ एमा कगार भी है जिसमें ऐसे बलात श्रम का उपबन्ध किया गया है जिसके अस्तित्व की उपधारणा संबंधित परिक्षेत्र में प्रचलित किसी सामाजिक रूढ़ि के अधीन की जाती है।

स्पष्टीकरण—ऋणी और लेनदार के बीच करार के अस्तित्व की उपधारणा सामाजिक रूढ़ि के अधीन निम्नलिखित प्रकार के बलात श्रम के संबंध में की जाती है, अर्थात्

आदियामार वारामासिया बसहया वेधू, भगेला, चेल्मार, गारुगल्लू हाली, हारी हरवद, हालया, जाना, जीता, कामिया, खुडिन मुडित, कुथिया लखरा मुची, मेट, मुतीश पद्धति तित मजूर पलरू पडियाल पनार्शलाल मागडी, सजी सजावत सबक सेबकिया, सेरी, उडो

(ग) मातप्रधान समाज के व्यक्ति के संबंध में 'बूबपुरुष या वधज' में वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस समाज में प्रवृत्त उत्तराधिकार की विधि के अनुसार ऐसा अभिव्यक्ति के समरूप है,

(घ) 'वधित ऋण' से ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो वधित श्रम-पद्धति के अधीन या उसके अनुरण में वधित श्रमिक द्वारा अभिप्राप्त किया जाता है या जिसके बारे में यह उपधारणा की जाती है कि वह एम अभिप्राप्त किया गया है,

(ङ) 'वधित श्रम' से वधित श्रम पद्धति के अधीन किया गया काइ श्रम या को गयी काइ मका अभिप्रेत है

(च) 'वधित श्रमिक' से ऐसा श्रमिक अभिप्रेत है जो वधित ऋण करता है या जिसे उपगत किया है या जिसके बारे में यह उपधारणा की जाती है कि उसने वह उपगत किया है

(छ) 'वधित श्रम पद्धति' से बलात श्रम या भागत बलात श्रम की उपधारणा अभिप्रेत है जिसके अधीन ऋणी लेनदार में इन जायज वा करार में है या जिसमें ऐसा करार किया है या जिसके बारे में यह उपधारणा

परिशिष्ट
वधित श्रम-पद्धति (उत्सादन) अधिनियम
1976

(1976 का अधिनियम सख्याक 19)

(9 फरवरी, 1976)

जनता के दुबल वर्गों के आर्थिक और शारीरिक शोषण का निवारण करने के उद्देश्य से वधित श्रम-पद्धति के उत्सादन का और उससे संबंधित या उसके आनुपंगिक विषयो का उपबध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवे वष म ससद द्वारा निम्नलिखित रूप म यह अधिनियमित हो—

अध्याय 1

प्रारम्भ

सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- 1 (1) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम वधित श्रम पद्धति (उत्सादन) नियम, 1976 है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- (3) यह 1975 के नवतूवर के पच्चीसवे दिन का प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषाएँ

2 इस अधिनियम म, जब तक कि सदम स अथवा अपेक्षित न हो—

(क) 'अग्रिम' से, चाहे नकद या वस्तु रूप म अथवा भागत नकद या भागत वस्तु रूप म, ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति द्वारा (जिसे इसम इनक पश्चान ऋणी कहा है) दिया जाना है,

(ख) 'करार' म ऋणी और लेनदार क बीच करार (चाहे वह लिखित रूप म हो या मौखिक अथवा भागत लिखित रूप म हो और भागत मौखिक) अभिप्रेत है और इसक अन्तगत कोई एसा करार भी है जिसम एस बलात धम का उपग्रह किया गया है जिसक अस्तित्व की उपधारणा संबंधित परिसेन म प्रचलित किसी सामाजिक रूढ़ि क अधीन की जाती है।

स्पष्टीकरण—ऋणी और लेनदार क बीच करार क अस्तित्व की उपधारणा सामाजिक रूढ़ि के अधीन निम्नलिखित प्रकार के बलात धम के संबध म की जाती है, अर्थात

आदियामार वारामासिया बसहया बयू भगेला, चेहमार भारगल्लू हाली, हारी हरवाई हालया, जाना जीता कामिया खुडित मुडित बुभिया लेखेरी, मुझी भेट, मुनीश पद्धति नित मजूर पलेर पडियाल पनाईताल, मागडी, मजी, मजाबन, सेवक सबकिया मेरी वेट्टी,

(ग) मातप्रधान समाज क व्यक्ति क संबध म 'पूवपुरुष या वंशज' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जा उस समाज म प्रवृत्त उत्तराधिकार की चिद्वि के अनुसार एसी अभिव्यक्ति के समरूप हे

(घ) 'वधिन ऋण' से ऐसा अग्रिम अभिप्रेत है जा वधित धम-पद्धति के अधीन या उसक अनुत्तरण म वधित धमिक द्वारा अभिप्राप्त किया जाना ह या जिसक वार म यह उपधारणा की जानी ह कि वह एस अभिप्राप्त किया गया है

(ङ) 'वधित धम से वधित धम-पद्धति क अधीन किया गया कोई धम या की गयी कोई सेवा अभिप्रेत है

(च) 'वधिन धमिक' से ऐसा धमिक अभिप्रेत है जा वधिन ऋण उगगत करता ह या जिनम उपगत किया ह या जिसक वार म यह उपधारणा की जाती है कि उसन वह उगगत किया है

(छ) 'वधित धम पद्धति से बलात धम या भागत बलात धम की पद्धति अभिप्रेत है जिसके अधीन ऋणी लेनदार से इस जाशय का करार करता है या जिसन एसा करार किया है या जिसके वार म यह उपधारणा की

जाती है कि उसने ऐसा करार किया है कि—

(1) उसके द्वारा या उसके पारम्परिक पूर्वपुरुष या वंशजों में से किसी के द्वारा अभिप्राप्त उधार के प्रतिफल में (चाहे ऐसा जग्गिम किसी दस्तावेज द्वारा साक्षित है या नहीं) और ऐसे जग्गिम पर देय ब्याज के, यदि कोई हो, प्रतिफल में अथवा

(2) किसी रुढिगत या सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में, अथवा

(3) किसी ऐसी बाध्यता के अनुसरण में जो उत्तराधिकार द्वारा उसको यागत हुई है अथवा

(4) उसके द्वारा या उसके पारम्परिक पूर्वपुरुष या वंशजों में से किसी के द्वारा प्राप्त किसी आर्थिक प्रतिफल के लिए, अथवा

(5) किसी विशेष जाति या समुदाय में उसके जे में लेने के कारण, वह—

(i) स्वयं या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के माध्यम से या अपने पर जाधित किसी व्यक्ति के माध्यम से लेनदार का, या देनदार के फायदे के लिए श्रम या सेवा, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए या तो मजदूरी के बिना या नाममान की मजदूरी पर करेगा, अथवा

(ii) अपने नियोजन या अपनी जीविका के अर्थ साधना की स्वतन्त्रता विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए खा देगा अथवा

(iii) भारत राज्य क्षेत्र में सबन अबाध संचरण का अपना अधिकार खा देगा अथवा

(iv) अपनी किसी सम्पत्ति या अपने श्रम के या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य या अपने पर जाधित किसी व्यक्ति के श्रम के उत्पाद को विनियोजित करेगा या उसे बाजार मूल्य पर विनियमन के अपना अधिकार खा देगा,

और इसके अतिरिक्त बलात् श्रम या भागत् बलात् श्रम की वह पद्धति भी है जिसके अधीन ऋणी प्रतिभू लेनदार के साथ इस आशय का करार करता है या जिसने ऐसा करार किया है या जिसके बार में यह उपधारणा की जाती है कि उसने ऐसा करार किया है कि ऋणी द्वारा ऋण का प्रतिसदाय करने में असफल रहने की दशा में वह ऋणी की ओर से बधित श्रम करेगा

(ज) किसी व्यक्ति के सबध में कुटुम्ब के अतिरिक्त उस व्यक्ति का पूर्वपुरुष और वंशज भी है,

(य) किसी श्रम के संबंध में 'सामान्य' की मजदूरी से वह मजदूरी अभिप्रेत है जो—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसी श्रम या उसी प्रकृति के श्रम के संबंध में सरकार द्वारा नियत निम्नतम मजदूरी से कम है और

(ख) जहाँ किसी प्रकार के श्रम के संबंध में ऐसी यूनतम मजदूरी नियत नहीं की गयी है वहाँ, उसी परिशेष में काम करने वाले श्रमिकों को उसी श्रम या उसी प्रकृति के श्रम के लिए प्रसामान्यतः सदात्त मजदूरी से कम है

(ज) 'विहित' से इस अधिनियम के अधीन बनाया गया नियमा द्वारा विहित अभिप्रेत है।

अधिनियम का अप्यारोही प्रभाव

3 इस अधिनियम के उपबन्ध, इस अधिनियम में भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगा।

अध्याय 2

वधित श्रम-पद्धति का उत्सादन

4 (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर वधित श्रम-पद्धति का उत्सादन हा जायगा और एन प्रारम्भ पर प्रत्येक वधित श्रमिक, वधित श्रम करने की किसी भी बाध्यता से मुक्त और उमाचित हा जायगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई व्यक्ति —

(क) वधित श्रम-पद्धति के अधीन या उसके अनुसरण में कोई श्रम नहीं दगा, जयवा

(ख) किसी व्यक्ति या कोई वधित श्रम या किसी अन्य प्रकार का बताते श्रम करने के लिए विवश नहा करगा।

क्रूर, रुद्धि, आदि का पू य होना

5 इस अधिनियम के प्रारम्भ पर कोई ऐसी रुद्धि या परम्परा या कोई मक्का, क्रूर या अन्य लिखत (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या उमर

पश्चात की गयी हो या निष्पादित की गयी हो) जिसके आधार पर किसी व्यक्ति से या उस व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी सदस्य से या उस व्यक्ति के आश्रित से बधित श्रमिक के रूप में कोई काम करने या सेवा करने की अपेक्षा की जाती है, शून्य और अप्रवर्तनीय होगी।

अध्याय 3

वधित ऋण का प्रतिमदाय करने के दायित्व की समाप्ति

6 (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर किसी बधित ऋण का प्रतिमदाय करने या ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व चुकता न किये गये किसी बधित ऋण के किसी भाग का प्रतिमदाय करने के लिए वधित श्रमिक का प्रत्येक दायित्व समाप्त हुआ समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किसी बधित ऋण या उसके किसी भाग की वसूली के लिए काइ वाद या अन्य कायवाही किसी सिविल यायालय में या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष नहीं होगी।

(3) बधित ऋण की वसूली के लिए प्रत्येक डिन्नी या आदेश, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व पारित किया गया हो और ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पूर्णतया चुकता न किया गया हो, एम प्रारम्भ पर पूर्णतया चुकता किया गया समझा जायेगा।

(4) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी बधित ऋण की वसूली के लिए की गयी प्रत्येक कुर्की एम प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगी और जहाँ ऐसी कुर्की के अनुसरण में वधित श्रमिक को काइ जाम सम्पत्ति अभिगृहीत हो गयी थी और उनकी अभिरक्षा से हटा ली गयी थी और उसका प्रिक्रय के लम्बित रहने के कारण किसी यायालय या अन्य प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी थी वहाँ ऐसी जाम सम्पत्ति का कब्जा एम प्रारम्भ के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से, वधित श्रमिक को वापस कर दिया जायेगा।

(5) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व बधित श्रमिक की या उसके कुटुम्ब के किसी सम्पत्ति या अन्य आश्रित की किसी सम्पत्ति का कब्जा किसी बधित ऋण की वसूली के लिए किसी जेनदार द्वारा जलपूर्वक ले लिया गया या वहाँ ऐसी सम्पत्ति का कब्जा एम प्रारम्भ के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से उस व्यक्ति को वापस कर दिया जायेगा जिसे वह अभिगृहीत की गयी थी।

(6) यदि उपधारा (4) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का कब्जा एम अधिनियम के प्रारम्भ से तीस मिनट के भीतर वापस नहीं किया जाता है तो वधित व्यक्ति उसी सम्पत्ति का कब्जा की वापसी के लिए विहित प्राधिकारी

को ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाय, आवेदन कर सकेगा और विहित प्राधिकारी लेनदार का सुनवाई का उचित अंतर देने के पश्चात्, लेनदार को यह निर्देश दे सकेगा कि वह जाबदस्त को सम्बन्धित सम्पत्ति का कब्जा ऐसे समय के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, वापस कर दे।

(7) विहित प्राधिकारी द्वारा उपधारा (6) के अधीन किया गया आदेश सिविल यायालय द्वारा किया गया आदेश समाना जायगा और धन सम्बन्धी निम्नतम अधिकारिता वाले एम यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकेगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर लेनदार मजदूर से निवास करता है या कारबार चलाता है या अभिलाष के लिए स्वयं काम करता है।

(8) शकाओं को दूर करने लिए यह घोषित किया जाता है कि जहाँ कुछ की गयी किसी सम्पत्ति का विषय किसी बधित ऋण का बसूनी के लिए किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किया गया या वहाँ ऐसे विषय पर इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का प्रभाव नहीं पड़ा।

पर तु बधित श्रमिक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राविष्ट अभिकर्ता ऐसे प्रारम्भ से पाँच वर्ष के भीतर किसी समय एम विषय का अपास्त करने के लिए आवेदन तय कर सकेगा जब वह उस विषय की उद्घापणा में विनिर्दिष्ट उस रकम को जिसकी बसूली के लिए विषय का आदेश किया गया था उसमें से उतनी रकम और अतः कालीन लाभ जो विषय की ऐसी उद्घापणा की तारीख से डिक्रीद्वारा प्राप्त किया गया हो, कम करके डिक्रीदार का तदर्थ करने के लिए यायालय में जमा कर दे।

(9) जहाँ बधित श्रम पद्धति के अधीन किसी बाध्यता के प्रारम्भ के लिए कोई वाद या कायवाही जिसमें अतः बधित श्रमिक का दिया गया किसी उधार का बसूली के लिए वाद या कायवाही भी है, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर चर्चित हो वहाँ ऐसा वाद या अन्य कायवाही इस प्रारम्भ पर चर्चित हो जायगी।

(10) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रत्येक बधित श्रमिक का निषेध के पूर्व या उसके पश्चात् सिविल कारागार में निरुद्ध किया गया है, एम निषेध तत्काल छोड़ दिया जायगा।

बधित श्रमिक की सम्पत्ति का बधक आदि से मुक्त किया जाना

7 (1) बधित श्रमिक में निहित सभी सम्पत्ति या इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी बधित ऋण के सम्बन्ध में किसी बधक, भार धारणा अधिकार या अन्य विल्लामा के अधीन थी जहाँ तक उसका सम्बन्ध बधित ऋण में है वहाँ तक एम बधक भार धारणाधिकार या अन्य विल्लामा में मुक्त और उपाचित हो जायगी और जहाँ ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक

पूव बधकदार के कब्जे म थी या भार, धारणाधिकार या विल्लगम क धारक क कब्जे म थी वहा एसी सम्पत्ति का कब्जा (उस दशा के सिवाय जय वह किसी जय भार के अधीन थी) एस प्रारम्भ पर बधित श्रमिक को वापस कर दिया जायगा।

(2) यदि उपधारा (1) म निर्दिष्ट किसी सम्पत्ति का कब्जा बधित श्रमिक का वापस करन म कोई विलम्ब किया जाता है तो ऐसा श्रमिक एस प्रारम्भ की तारीख स ही बधनार म या भार धारणाधिकार या विल्लगम क धारक से ऐस अत कालीन लाभ बसूल करन का हक्दार हागा जा धन-सम्बधी निम्नतम अधिकारिता वाले एस सिविल न्यायालय द्वारा अवधारित किय जायें जिसकी स्थानीय सीमाभा की अधिकारिता के भीतर ऐसी सम्पत्ति स्थित है।

मुक्त किये गये बधित श्रमिक का वासस्थान, जादि से बेदखल न किया जाना

8 (1) एस किसी व्यक्ति का जो बधित श्रम करन क किमी दायित्व स इस अधिनियम के अधीन मुक्त और उन्मोचित किया गया है, किसी वासस्थान या जय निवास परिसर स जिसका अधिभाग वह इस अधिनियम के प्रारम्भ स ठीक पूव बधित श्रम के प्रतिफल क भागरूप कर रहा था, बंदखल नहीं किया जायगा।

(2) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ क पश्चात ऐसा कोई व्यक्ति लेनदार द्वारा उपधारा (1) म निर्दिष्ट किसी वासस्थान या जय निवास परिसर स बंदखल किया जाता है तो उस उपखंड का, जिसम ऐसा वासस्थान या निवास-परिसर स्थित है कायपालक मजिस्ट्रेट बधित श्रमिक को ऐसे वासस्थान या जय निवास परिसर का कब्जा, यथासाध्य शीघ्रता से वापस करेगा।

समाप्त ऋण के लिए लेनदार द्वारा सदाय का स्वीकार न किया जाना

9 (1) कोई लेनदार किसी एस बधित ऋण के लिए जो इस अधिनियम क उपबधा क जाधार पर समाप्त हो गया है या समाप्त हुआ समझा गया है या पूणतया चुकता कर दिया गया समझा गया है, कोई सदाय स्वीकार नहीं करेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबधा का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वष तक की हो सकेगी और जुर्माना स भी दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला यायालय उस व्यक्ति को निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी शास्त्रियों के अतिरिक्त जो उस उपधारा के अधीन अधिरोपित की जायें, यायालय म वह रकम जो उपधारा(1) क उपबधा के उल्लंघन म स्वीकार की जाती है ऐसी अवधि के भीतर जा जादेश म विनिर्दिष्ट की जाय बधित श्रमिक को वापस किय जान के लिए जमा करे।

अध्याय 4

कार्यान्वयन प्राधिकार

वे प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट किये जायें

10 राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी जा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि इस अधिनियम के उपबन्ध समुचित रूप से कार्यान्वित किये जा रहे हों और जिला मजिस्ट्रेट अपना ऐसा अधीनस्थ अधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इस प्रकार प्रदत्त सभी या किही शक्तियाँ का प्रयोग और इस प्रकार अधिरोपित सभी या किही कर्तव्यों का पालन करेगा और उन स्थानीय सीमाओं को विनिर्दिष्ट करेगा जिनके भीतर ऐसी शक्तियाँ का प्रयोग या ऐसे कर्तव्यों का पालन इस प्रकार विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किया जायगा।

ऋण सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारियों का कर्तव्य

11 धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत जिला मजिस्ट्रेट और उस धारा के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकारी वधित श्रमिक के आर्थिक हितों को सुनिश्चित करके आरक्षण देकर ऐसे वधित श्रमिक के कल्याण की अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा जिससे कि उस वधित श्रमिक को कोई और वधित ऋण लेने के लिए सविदा करने का बाद जमर या हेतुक न हो।

जिला मजिस्ट्रेट का और उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों का कर्तव्य

12 प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट का और धारा 10 के अधीन उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह जाँच करे कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी वधित श्रम पद्धति या किसी अन्य प्रकार के बलात् श्रम का उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से प्रवर्तन किया जा रहा है या नहीं और यदि ऐसी जाँच के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति वधित श्रम पद्धति या बलात् श्रम की किसी अन्य पद्धति का प्रवर्तन करत पाया जाता है तो वह तत्वात् ऐसी कार्यवाही करेगा जो एक बलात् श्रम के प्रवर्तन का उन्मूलन करने के लिए आवश्यक है।

अध्याय 5

सतकता समितियाँ

13 (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले और प्रत्येक उपखंड में उतनी सतकता समितियाँ गठित करेगी जितनी वह ठीक समझे।

(2) किसी जिले के लिए गठित प्रत्येक सतकता समिति में निम्नलिखित संस्य हागें जयान—

(क) जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति जो अध्यक्ष होगा

(ख) तीन व्यक्ति जो अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियाँ के हों और जिनमें निवास कर रहे हों, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्देशित किये जायेंगे,

(ग) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो जिले में निवासी हों, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे,

(घ) जिनमें ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय या अशासकीय अधिकारणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक तीन व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे

(ङ) जिले में वित्तीय और प्रत्यय समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जायगा।

(3) किसी उपखंड के लिए गठित प्रत्येक सतकता समिति में निम्नलिखित संस्य हागें जयान—

(क) उपखंड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति, जो अध्यक्ष होगा

(ख) तीन व्यक्ति, जो अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियाँ के हों और उपखंड में निवास कर रहे हों, जो उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे

(ग) दो सामाजिक कार्यकर्ता जो उपखंड में निवासी हों, जो उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे

(घ) उपखंड में ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय या अशासकीय अधिकारणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिक से अधिक तीन व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे,

(ङ) उपखंड में वित्तीय और प्रत्यय समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने

के लिए एक व्यक्ति, जो उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा,

(च) एक अधिकारी जो धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट है और उपखंड में कार्य कर रहा है।

(4) प्रत्येक सतकता समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी और उस—

(क) जिले के लिए गठित सतकता समिति को दंगा में डिला मजिस्ट्रेट द्वारा,

(ख) उपखंड के लिए गठित सतकता समिति की दंगा में उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा

ऐसी अनुसचिवाय सहायता दी जायेगी जो आवश्यक हो।

(5) सतकता समिति की कोई कार्यवाही सतकता समिति के गठन या कार्यवाही में किसी त्रुटि के कारण ही अवधिमान्य नहीं होगा।

सतकता समितियों के कृत्य

14 (1) प्रत्येक सतकता समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए इन अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम के उल्लंघन का समुचित रूप में विचार करना होगा, किन गये प्रयत्न और की गयी कार्रवाई के कारण न किता मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का आलाहना

(ख) मुक्त किये गये व्यक्ति श्रमिका के आदि आगे सामाजिक पुनर्वास के लिए व्यवस्था करना

(ग) मुक्त किये गये व्यक्ति श्रमिका के लिए पर्याप्त प्रत्येक की व्यवस्था करने के उद्देश्य से शांतिपूर्ण तरीके और सहकारी माना-नियम के कृत्य का समर्थन करना

(घ) उन अपराधों की सन्ध्या पर नजर रखना जिनका प्रावधान अधिनियम के अधीन किया गया है

(ङ) यह सुनिश्चित करना कि क्या कोई अपराध किया गया है जिसका मतलब इन अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए था

(च) मुक्त किये गये व्यक्ति श्रमिका के या उनके परिवार के या उन पर आश्रित व्यक्ति के विरुद्ध सम्पत्ति किसी भी रूप में प्रतिकार करना जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया हो या मजदूर या उनके किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किया गया हो

ऋण के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

(2) सतकता समिति अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य का इस वाद के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह मुक्त किया गया बधित श्रमिक के विरुद्ध वाद की प्रतिरक्षा करे और इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य मुक्त किया गया बधित श्रमिक का, ऐसे वाद के प्रयाजन के लिए प्राधिकृत अभिकर्ता समया जायगा।

संवृत का भार

15 जब कभी किसी बधित श्रमिक या सतकता समिति द्वारा किसी ऋण के बारे में यह दावा किया जाता है कि वह बधित ऋण है तो ऐसे ऋण के बधित ऋण न हान के संवृत का भार अनन्तर पर होगा।

अध्याय 6

अपराज और विचारण के लिए प्रक्रिया

बधित श्रम के प्रवतन के लिए दंड

16 जो कोई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किसी व्यक्ति को कोई बधित श्रम करने के लिए विवश करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

बधित ऋण के दिये जाने के लिए दंड

17 जो कोई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात कोई बधित ऋण देगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा।

बधित श्रम-पद्धति के अधीन बधित श्रम कराने के लिए दंड

18 जो कोई इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात किसी ऐसी रूढ़ि परम्परा, सविदा, करार या अन्य लिखत का प्रवतन करेगा, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के कुटुम्ब के किसी सदस्य या ऐसे व्यक्ति पर आश्रित किसी व्यक्ति से अपक्षा की जाती है कि वह बधित श्रम पद्धति के अधीन कोई सेवा करे तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा और यदि जुर्माना

वसूल किया जाता है तो उसमें से वधित श्रमिक को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस दिन उससे वधित श्रम कराया गया था पांच रुपये की दर से सदाय किया जायगा।

वधित श्रमिकों को सम्पत्ति का कब्जा वापस करने में लोप या असफलता के लिए दंड

19 ऐसा कोई व्यक्ति जिससे इस अधिनियम द्वारा यह अपेक्षा हो जाती है कि वह किसी सम्पत्ति का कब्जा किसी वधित श्रमिक को वापस करे इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसा करने में लोप करेगा या असफल रहेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती या जुर्माना से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और यदि जुमाना वसूल किया जाता है तो उसमें से वधित श्रमिक को ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान सम्पत्ति का कब्जा उसे वापस नहीं किया गया था पांच रुपये की दर से सदाय किया जायगा।

दुष्प्रेरण का एक अपराध होना

20 जो वाद इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे दुष्प्रेरित अपराध किया गया हो या नहीं वह उसी दंड से दंडनीय होगा जो उस अपराध के लिए उपवधित है जिसका दुष्प्रेरण किया गया है।
स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 'दुष्प्रेरण' का वही अर्थ है जो उसका भारतीय दंडमहिता (1860 का 45) में है।

अपराधों का कायपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा विचारण किया जाना

21 (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए कायपालक मजिस्ट्रेट का प्रथम वग यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वग यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसी शक्तियां प्रदान किय जाने पर उस कायपालक मजिस्ट्रेट को, जिसे इस प्रकार शक्तियां प्रदान की गयी हैं दंड प्रतियां सहित 1973 के प्रयोजना के लिए यथास्थिति प्रथम वग यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय वग यायिक मजिस्ट्रेट समझा जायेगा।
(2) इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संपन्न किया जायगा।

अपराधों का सन्तान

22 इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध मनेय और जमानतीय होगा।

कम्पनियाँ द्वारा अपराध

23 (1) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के लिए जान के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारताध्यक्ष और उसके प्रति उत्तरदायी या और साथ ही वह कम्पनी भी एक अपराध के दायी समझे जायगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किया जान और दंडित किया जान के भागी होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के हात में भी जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित होता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी ऐसे त के कारण माना जा सकता है वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दायी समझा जायगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किया जान और दंडित किया जान के भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) कम्पनी में कोई निगमित निवाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टि का अन्य संगम भी है तथा

(ख) फर्म के मन्वन्ध में निदेशक से उस फर्म के भागीदार अभिप्रेत है।

अध्याय 7

प्रतीक

सबभावपूर्वक की गयी कारवाइ के लिए संरक्षण

24 इस अधिनियम के अधीन सबभावपूर्वक की गयी या की जान के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी के या मतवता समिति के किसी सदस्य के विरुद्ध न होगी।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का बजन

25 किसी भी सिविल न्यायालय का किसी ऐसे विषय के बारे में अधिकारिता नहीं होगी जिस अधिनियम के कोई उपबंध लागू होता है और किसी

सिविल प्रायालय द्वारा किसी ऐसी बात के बारे म काइ व्यादश नही लिया जायगा जा इस अधिनियम के अधीन की गयी है या की जान क लिए आवश्यक है।

नियम बनाने की शक्ति

26 (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयाजना को कार्यावित करने के लिए नियम राजपत्र म अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विधिपुस्तक और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिशत प्रभाव डाल बिना एस नियम निम्नलिखित सभी या कि ही विषय क लिए उपबध करेगा अर्थात्—

(क) वह प्राधिकारी जिसको धारा 6 की उपधारा (4) या उपधारा (5) म निष्पिष्ट सम्पत्ति के कब्ज की वापसी के लिए उस धारा की उपधारा (6) क अनुसरण म जानदन लिया जाना है

(ख) वह समय जिसके भीतर सम्पत्ति क कब्ज की वापसी क लिए धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन आवेदन विहित प्राधिकारी को किया जाना है

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाय गय किसी नियम के उपबध का नियायन सुनिश्चित करने के लिए मतकता समितियां द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उठाये जान वाक कर्म

(घ) काइ ज य विषय जा विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

(3) इस अधिनियम क अधीन क द्वारा सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम प्रभाव जान क पश्चात यथाशीघ्र सदन क प्रत्येक सदन क समक्ष जन वह सदन म हा तीस दिन की अवधि क लिए रखा जायगा। यह अवधि एक सदन म अवधारणा अधिक जानुनमिक सत्रा म पूरी हो सकेगी। यदि इस सदन क या पूर्वोक्त जानुनमिक सत्रा क ठीक बाद क सदन क अवमान क पूर्व दोना सदन उस नियम म कोई परिवर्तन करने क लिए सहमत हा जाये तो तत्पश्चात वह ऐम परिवर्तित रूप म ही प्रभावी हागा। यदि उक्त अवमान क पूर्व दोना सदन सहमत हा जाये कि वह नियम नही बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जायगा। किंतु नियम के एम परिवर्तित या निष्प्रभावी हाग स उसक अधीन पहन की गयी किसी बात की विधिमा यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडगा।

निरसन और व्यावृत्ति

27 (1) वधित श्रम-पद्धति (उत्सादन) अधि
17) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) एस निरसन के हात हुए भी यह है कि
गयी कोई बात या कारवाई (जिसके अंतर्गत कोई
गया कोई निर्देश या नामनिर्देशन, प्रदत्त शक्ति अधि
अधिकारी भी है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपप्रध
जायगी।

देश, 1975 (1975 का

कत अध्यादेश के अधीन की
काशित अधिसूचना, किया
पित कर्तव्य या विनिर्दिष्ट
के अधीन की गयी समझी

